दैनिक जागरण
कला जीवन का सौंदर्य बढ़ाती है

सराहनीय निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह एससी का दर्जा खो देता है और साथ ही एससी-एसटी एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है, जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में एससी समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं, जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाइयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ-लालच और छल-छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन वंचित लोगों का छल-छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आम तौर एससी और एसटी समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि लालच और छल-कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है।

एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहां जाति जैसी कोई मान्यता नहीं और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं-कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं, जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें एससी का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं? जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिये सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्रविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और एससी-एसटी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे, जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है, उसे ही आरक्षण का लाभ मिले।

चारधाम यात्रा की चुनौती

उत्तराखंड में मौसम की करवट ने प्रशासनिक मशीनरी को चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए नए सिरे से काम दे दिया है। महीनेभर पहले तक यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर मशीनरी कुछ राहत महसूस कर रही थी, वजह इस बार शीतकाल में अपेक्षाकृत कम बर्फबारी होना माना जा रहा था। विशेषकर, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल ट्रैक पर बर्फ न होने के कारण प्रशासन मान रहा था कि इसे सुगम में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पिछले दिनों जमकर हुई बर्फबारी और बारिश ने चुनौती बढ़ा दी है। चारों धामों में तीन से पांच फीट तक बर्फ जम गई है, पैदल रास्ते भी बर्फ से अटे पड़े हैं। अगले महीने की 19 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी, ऐसे में तैयारियों के लिए कम समय रह गया है। विभागीय तंत्र को अब न केवल सक्रिय होना पड़ेगा, बल्कि समय सीमा के भीतर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी होंगी। अच्छी बात है कि तंत्र इस बात को समझ रहा है और मौसम खुलते ही वह यात्रा व्यवस्था से जुड़े कार्यों को गति देने में जुट गया है। यह जरूरी भी है। इस बीच व्यवस्थाओं की ठीक से परख कर ली जानी चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान दिक्कतें खड़ी न हों। आमतौर पर देखने में आता है कि यात्रा के शुरुआती महीने में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं बनाने की चुनौती रहती है। चूंकि इस बार यात्रा पिछले सालों की तुलना में कुछ पहले शुरू हो रही है और पांच दिन के अंतराल में ही चारों धामों के पट खुल जा रहे हैं।

चारधाम यात्रा के सुचारु और निरापद संचालन के लिए पारंपरिक सोच से हटकर कार्य करने की जरूरत है

मजहबी खेमों की भी मोर्चेबंदी

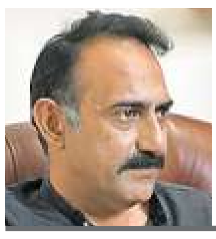

राजा मुनीब

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध शिया-सुन्नी मजहबी पहचान का संघर्ष भी बन रहा है

अवधेश राजपूत

पश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध केवल ईरान बनाम इजरायल या तेहरान बनाम वाशिंगटन संघर्ष के रूप में ही सिमटकर नहीं रह गया है। यह टकराव अब और खतरनाक स्वरूप लेकर बहुस्तरीय बनता जा रहा है। इसमें भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ ही वर्गीय पहचान, वैचारिक वैधता और रणनीतिक अवसरवाद जैसे पहलू भी जुड़ते जा रहे हैं। संघर्ष का दायरा भी गाजा की सड़कों से लेकर पाकिस्तान के जनजातीय इलाकों तक फैल गया है। इसमें शिया-सुन्नी टकराव की लकीरें भी चौड़ी हो रही हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने अपने वैचारिक प्रभाव को अपनी सीमाओं से परे बढ़ाने के भरसक प्रयास किए। चूंकि इस इलाके की आबादी मुख्य रूप से सुन्नी बहुतायत वाली है, इसलिए शिया बहुल ईरान को वैचारिक मोर्चे पर वैधता के लिए संघर्ष ही करना पड़ा। अपने वैचारिक प्रभाव की राह में आ रहे अवरोधों की काट के लिए उसने स्वयं को फलस्तीन संघर्ष जैसी उन मांगों के साथ जोड़ लिया, जिसमें वैचारिक दरारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचे। इसके लिए उसने कुछ संगठनों को पोषित करने से भी परहेज नहीं किया। इससे जहां ईरान के नेतृत्व में शिया संगठनों का नेटवर्क उभरा तो दूसरी ओर सुन्नी प्रभाव वाले सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के राजशाही वाले देश थे। अमेरिकी सुरक्षा ढांचे पर निर्भर इन देशों की समय के साथ इजरायल के साथ नजदीकियां भी बढ़ती गईं। दोनों खेमों के बीच यह विभाजन केवल मजहबी नहीं, बल्कि भूराजनीतिक भी है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष की परतें मजहबी मान्यताओं से अधिक राजनीतिक हितों और शक्ति-संतुलन से जुड़ी हैं। सुन्नी देश ईरान को एक विस्तारवादी वैचारिक खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह अपने प्रभाव के विस्तार के लिए प्रयासरत है और विभिन्न संगठनों के जरिये अपनी पकड़ मजबूत करता है। वहीं, ईरान सुन्नी देशों को पश्चिमी शक्तियों के ऐसे प्रतिनिधि के रूप में देखता है, जो उसके प्रभाव को सीमित करने का काम करते हैं। यही इस संघर्ष का केंद्रीय विरोधाभास है, जहां एक शिया खेमा सुन्नी असंतोष से ताकत हासिल करता है, वहीं सुन्नी शासन तंत्र उसी पश्चिम-समर्थित व्यवस्था के साथ खड़ा है, जिसका अक्सर उसके अपने लोग ही विरोध करते हैं।

ईरान के विरुद्ध अमेरिका-इजरायल की कोई जमीनी या व्यापक सैन्य कार्रवाई 2003 के इराक युद्ध की तुलना में कई गुना जटिल होगी। उन्हें भौगोलिक, सैन्य और वैचारिक तीनों ही स्तरों पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ईरान, इराक जैसा नही हैं। यह आकार में कहीं बड़ा, सामाजिक रूप से अधिक सुसंगठित और मूलतः एकजुट राष्ट्र है। यहां स्थानीय मिलीशिया भी मजबूत हैं, जो एक साथ कई मोर्चे खोलने की क्षमता रखते हैं। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटी हुई है। सुन्नी विद्रोहियों का गढ़ होने के नाते यह चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र रहा है। आइएसआइएस-खुरासान और जैश अल-अदल जैसे संगठन इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये कट्टर शिया विरोध की जमीन पर ही पनपे हैं और ईरान का प्रतिरोध करते हैं। ये समूह एक वैकल्पिक दबाव तंत्र बना सकते हैं। यानी ईरान के पश्चिमी मोर्चों पर मजबूत किलेबंदी से टकराने के बजाय उसकी पूर्वी सीमा पर अस्थिरता पैदा की जा सकती है। इससे ईरान के सुरक्षा ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। उसे पूर्वी सीमा पर अपने सैन्य संसाधन झोंकने पड़ेंगे, जिससे दूसरे मोर्चों पर उसकी कमजोरियां बढ़ेंगी। अमेरिका सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान ऐसे पैंतरे आजमा कर सैन्य हस्तक्षेप के बिना ही रणनीतिक लाभ हासिल कर चुका है। हालांकि आज हालात उतने अनुकूल नहीं। उस दौर के उलट आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों में एका का अभाव है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष ने पहले से जटिल इस स्थिति को और भी उलझा दिया है। पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति अपनी भूराजनीतिक प्रासंगिकता को वापस पाने की भी है। अतीत पर दृष्टि डालें तो पाकिस्तान ऐसे मौकों को भुनाने में पारंगत रहा है। सोवियत-अफगान युद्ध में अपने सहयोग के बदले उसने वाशिंगटन से तमाम सामरिक एवं आर्थिक लाभ हासिल किए। पाकिस्तान को ईरान संकट में भी ऐसा ही मौका नजर आ रहा है, पर इस बार शायद उसके भाग्य से छींका न टूटे। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन अब पाकिस्तानी रहमोकरम पर नहीं। वह अपनी स्वायत्तता पर अड़ा है। पाकिस्तानी दबाव का प्रतिरोध करने के साथ ही वह अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर रहा है। इससे तनाव निरंतर बढ़ रहा है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में तमाम तरह के आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनकी निष्ठाएं समय के साथ बदलती रहती हैं और इनका एजेंडा भी अक्सर व्यापक क्षेत्रीय संघर्षों के साथ जुड़ जाता है। यदि ये समूह बाहरी शक्तियों के पिट्ठुओं या अपने स्वयं के मजहबी एजेंडे के तहत ईरान संघर्ष में उतरते हैं तो फिर पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ती जाएंगी।

ऐसी स्थिति में आकार लेने वाला परिदृश्य ऐसी रणभूमि के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, जहां हर एक मोर्चा दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इसमें वही भौगोलिक एवं मजहबी दरारें उभरेंगी, जहां ईरानी प्रभाव, सुन्नी असंतोष, अमेरिकी रणनीतिक हित और ऐतिहासिक कड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं। यह टकराव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी आंच सीरिया और खाड़ी के साथ ही अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैलती जाएंगी। पश्चिम एशिया में यही खतरा उभर रहा है, क्योंकि यह दो राज्य शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि पहचान का ऐसा संघर्ष बनता जा रहा है, जिसके प्रतीकों के सिरे कर्बला से लेकर दमिश्क तक और गाजा से लेकर पाकिस्तान की जनजातीय सीमाओं तक जुड़ते हैं। इसमें 21वीं सदी के भू-राजनीतिक मानचित्र को पुनः परिभाषित करने की क्षमता है।

(लेखक सामरिक एवं इस्लामिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
response@jagran.com

धुरंधर पर फालतू का रोना-धोना

राजीव सचान

जैसे धुरंधर-1 को देखकर कई लोगों को मिर्ची लगी थी, वैसे ही धुरंधर-2 को लेकर भी कुछ लोगों को अपच हो गई है

फिल्म धुरंधर-2 पर भी निराधार आपत्तियां। फाइल

ऐसी फिल्मों की गिनती करना कठिन है, जिन पर किसी को आपत्ति न हुई हो। हाल में ऐसी कई फिल्में आ चुकी हैं, जिनका विरोध हुआ अथवा जिन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की गई, जैसे द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं, जिनका विरोध करने के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया या फिर निर्माता-निर्देशकों को धमकाया। याद करें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का कुछ समूहों ने कैसा हिंसक विरोध किया था? इस विरोध का आधार यह था कि फिल्म में रानी पद्मिनी और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिल्म प्रतिबंधित करने की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद वह रिलीज तो हुई, पर कई लोगों का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ, जब तक यह सामने नहीं आया कि वे फिल्म में जिस कथित विकृत चित्रण की आशंका से दुबले हुए जा रहे थे, वह निर्मूल थी।

कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं, जिन्हें इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनमें सच दिखाया गया था। द कश्मीर फाइल्स के अलावा मणिरत्नम की रोजा ऐसी ही फिल्म थी। रोजा का विरोध इस बेवकूफी भरे कुतर्क के सहारे हुआ कि फिल्म में कश्मीरी आतंकियों का पक्ष नहीं दिखाया गया और उनका नकारात्मक चित्रण किया गया है। जाहिर है कुछ लोग यह चाह रहे थे कि आतंकियों को भले मानुष की तरह पेश किया जाता। इसे बेवकूफी के अलावा और क्या कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का सामना कई फिल्मकारों को करना पड़ा। कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं, जो सचमुच बेवकूफी भरी थीं या उनमें कुछ ऐसे सीन थे, जिन्हें कोई बेवकूफ ही पचा सकता था, जैसे कबीर खान की फिल्म 83 में एक विचित्र सीन यह था कि पाकिस्तानी सैनिक इस कारण गोलीबारी रोक देते हैं, ताकि मोर्चे पर डटे भारतीय सैनिक विश्वकप फाइनल मैच की कमेंट्री चैन से सुन सकें। यह नितांत काल्पनिक और सच से कोसों दूर सीन था। इसका मकसद केवल पाकिस्तानी सैनिकों को भला आदमी दिखाना था, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या थी? यह सही है कि फिल्मकार किसी सच्ची घटना पर आधारित या उससे प्रेरित फिल्म में रचनात्मक स्वतंत्रता लेते ही हैं, पर इस बहाने कुछ फिल्मकार बेवकूफी की हद भी पार कर जाते हैं। कई बार ऐसी बेवकूफियां दर्शकों को पसंद भी आ जाती हैं, जैसे फिल्म पठान में यह दिखाया गया कि निर्वासित रा एजेंट शाहरुख खान एक पूर्व रा एजेंट जान अब्राहम के शैतानी इरादों पर आइएसआइ एजेंट दीपिका पादुकोण के सहयोग से पानी फेर देता है। दर्शक इस अजीब कथानक को पचा गए और फिल्म हिट हो गई। रचनात्मक स्वतंत्रता के बहाने फिल्मकार तथ्यों में फेरबदल तो करते ही हैं, कई बार शरारत भी कर देते हैं, जैसे इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ पर बनी फिल्म फायर के महिला पात्रों के नाम राधा और सीता रखना, जबकि मूल कहानी में वे बेगम जान और रब्बो थीं। कृपया नोट करें यह फिल्म महिलाओं के समलैंगिक संबंधों पर थी। यदि निर्देशक दीपा मेहता महिला पात्रों के नाम मूल कहानी के हिसाब से नहीं रख सकती थीं तो फिर उन्हें सीता और राधा नाम ही क्यों सूझे?

इस वर्ष की सबसे कामयाब फिल्म धुरंधर तबसे चर्चा में है, जबसे उसका पहला हिस्सा आया। उसे लेकर यह अफवाह फैलाई गई कि यह एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी फिल्म है, पर इस फिल्म को तमाम पाकिस्तानियों ने भी पसंद कर इस दुष्प्रचार की पोल खोल दी। इस फिल्म के विरोध का मूल कारण यह है कि आदित्य धर ने आतंकी घटनाओं के सहारे पाकिस्तान के उस आतंकी तंत्र की पोल खोल दी, जो भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यदि एक क्षण के लिए इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान मान लें तो भी आखिर भारतीयों को इससे क्यों कष्ट होने लगा? जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान से हमदर्दी क्यों?

जैसे धुरंधर-1 को देखकर कई लोगों को मिर्ची लगी थी, वैसे ही धुरंधर-2 को लेकर भी कुछ लोगों को अपच हो गई है। अपच का एक कारण यह है कि फिल्म में माफिया अतीक अहमद (फिल्मी नाम आतिफ अहमद) को आइएसआइ एजेंट दिखाया गया है। बस इसी कारण फिल्म का विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों में सपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। यदि यह मान लें कि आदित्य धर ने अतीक को आइएसआइ का एजेंट दिखाकर उसका अतिरंजित चित्रण कर दिया तो यह रचनात्मक स्वतंत्रता के दायरे में क्यों नहीं आता? क्या ऐसे चित्रण से अतीक भला आदमी सिद्ध हो जाता है? अतीक परले दर्जे का दुष्ट और निर्दयी अपराधी था। वह आतंकी भले न हो, पर उसकी हरकतें लोगों को आतंकित करने वाली ही थीं। उसका इतना आतंक था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक के बाद एक 10 (जी हां 10) जज उसकी जमानत याचिका सुनने से पीछे हट गए थे। एक बार उसने जेल में बंद रहते एक कारोबारी को अगवा कराकर अपने सामने पेश कराया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। उसने न जाने कितने लोगों को निर्दयता से मारा और मरवाया। इनमें मुस्लिम भी थे, फिर भी कुछ लोग उसे लेकर इसलिए रो रहे हैं ताकि उसके बहाने खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित कर सकें। यह मूर्खता की पराकाष्ठा तो है ही, यह बेजा माहौल बनाना भी है कि मुसलमान अतीक जैसे बदमाश को अच्छा मानते हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संकट का सत्य

मनुष्य का जीवन अनुभूतियों की एक गहन सरिता है, जिसमें सुख और संकट दोनों प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाह में संकट बहुत बड़ा शिक्षक है। यह सत्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहन भी है कि मनुष्य विपत्तियों में ही अपनी वास्तविक चेतना से साक्षात्कार करता है। जबकि सुख के क्षण उसे मधुर स्मृतियों में बांध देते हैं। सुख की अवस्था मनुष्य को आत्मतुष्टि के ऐसे मृदुल आवरण में ढक देती है, जहां वह अपने अतीत के संघर्षों और उनसे प्राप्त शिक्षाओं को विस्मृत करने लगता है। वह मान बैठता है कि जीवन उसकी इच्छानुसार संचालित होगा। तब वह अपनी त्रुटियों को देख ही नहीं पाता।

संकट का आगमन मानो चेतना का तीव्र उद्घोष है। यह मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है और उसे आत्ममंथन के लिए बाध्य करता है। संकट में मनुष्य अतीत के प्रत्येक निर्णय, भूल और अनुभव का सूक्ष्म परीक्षण करता है। यही वह समय होता है जब वह अपने भीतर छिपी सामर्थ्य, धैर्य और साहस को पहचान पाता है। संकट उसे यह बोध कराता है कि वास्तविक शक्ति बाह्य परिस्थितियों में नहीं, अपितु उसके अंतर्मन में निहित है। हमारे दैनिक जीवन में भी यह सत्य प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। असफलता का एक क्षण वर्षों की लापरवाही को उजागर कर देता है और व्यक्ति को आत्मसंशोधन के मार्ग पर अग्रसर करता है। वहीं, निरंतर सफलता उसे अक्सर निष्क्रिय और असावधान बना देती है।

वस्तुतः, संकट मनुष्य को सजग, अनुशासित और आत्मविश्लेषी बनाता है, जबकि सुख उसे क्षणिक आनंद तो देता है, परंतु स्थायी बोध नहीं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम संकटों से भयभीत न होकर उन्हें आत्मविकास के साधन के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि अंततः जो क्षण, सर्वाधिक अधिक पीड़ा देते हैं, वही हमें सबसे अधिक परिपक्व और समर्थ भी बनाते हैं।

कुमार नृपेंद्र

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का समय

सुधीर कुमार

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है

पश्चिमी एशिया में व्याप्त युद्ध की स्थिति और उन पर जीवाश्म ईंधनों के लिए उच्च निर्भरता का असर अब विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और समाज पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में आई उछाल और आपूर्ति संबंधी परेशानियों के कारण महंगाई और खाद्य असुरक्षा का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास कर आसन्न ऊर्जा संकटों से मुकाबला करना कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

दरअसल, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना महज ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता के विकास से जुड़ा विषय ही नहीं रह गया है, बल्कि यह जलवायु संकट से निपटने के साथ-साथ आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता भी बन चुका है। पेरिस जलवायु समझौते (2015) के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रही है। वर्ष 2025 में दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश का जीवाश्म ईंधन में हुए निवेश का दोगुना रहना तथा कोयला को पीछे छोड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली का स्रोत बनना इस तथ्य की पुष्टि भी करते हैं कि दुनिया वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि 'नवीकरणीय ऊर्जा 21वीं शताब्दी के लिए एक शांति योजना है।' नवीकरणीय ऊर्जा केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह युद्ध, असमानता और पर्यावरण संकट को कम करके दुनिया में शांति के स्थायित्व का जरिया भी बन सकता है।

जीवाश्म ईंधन की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक सस्ता, सुरक्षित और सुलभ संसाधन है। सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षरण को कम करने की दिशा में कारगर भूमिका निभाई है। भारत में नवीकरणीय (गैर-परंपरागत) ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 125 गीगावाट तक पहुंच गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना से देश में 30 लाख घरों को रूफटाप सोलर से जोड़ा जा चुका है। वहीं, पवन ऊर्जा के विकास के मामले में भारत आज चौथा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। ऐसे में जरूरी है कि हर स्तर से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आत्मसात करने की दिशा में ठोस पहल की जाए, तभी जाकर ऊर्जा से जुड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है।

बहरहाल, मौजूदा वैश्विक अशांति एक ऐसी आपदा भी है, जहां हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनकर न केवल जीवाश्म ईंधनों से दूरी बना सकते हैं, बल्कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में दुनिया का नेतृत्व भी कर सकते हैं।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

संवाद से निकले समाधान

'युद्ध की तपिश से बचने की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में जयंतीलाल भंडारी ने युद्ध से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया है। दुनिया के लिए यह चिंता का विषय है कि युद्ध जारी रहने से न सिर्फ ईरान के अलावा अमेरिका-इजरायल प्रभावित होंगे, संपूर्ण विश्व प्रभावित होगा। युद्ध जारी रहने की दशा में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका हैं। चिंता की एक बात संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी है, जो मात्र मूकदर्शक बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई उम्मीद नहीं कि कोई पहल करे और युद्ध रुक जाए। अब तो लगता है कि अमेरिका को ही समझदारी दिखानी चाहिए। युद्ध रुकता है तो पूरे विश्व को फायदा ही होगा। सभी देश मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाए और ईरान को भी समझाएं कि वह भी अपने कदम पीछे खींच ले। हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं करती। स्थायी समाधान संवाद से ही संभव है।

सर्वजीत आर्या प्रधानाचार्य कन्नौज

वैश्विक शांति के प्रति सार्थक प्रयास

मंगलवार को प्रकाशित अग्रलेख "विरोधाभासी ट्रंप" में विश्व राजनीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधाभासी बयानों और -परिणामों का जो सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यंत संतुलित और सामयिक लगा। आपने सही रूप से रेखांकित किया है कि ट्रंप ने एक ओर शांति के संकेत दिए, तो दूसरी ओर कठोर अल्टीमेटम और सैन्य विकल्पों का उल्लेख किया। इससे वैश्विक समुदाय में दुविधा और असमंजस की स्थिति बन रही है। आज की अशांत अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में, विश्व-शक्ति के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति का युद्ध और शांति के बीच का ढुलमुल रवैया विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक सत्ता-केंद्र का लक्ष्य शांति, समझौता और वैश्विक स्थिरता होना चाहिए। लेकिन ट्रंप के बयानों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे स्थिर रणनीति और स्पष्ट राजनीतिक दिशा से भटकते हुए निर्णय ले रहे हैं, जो न केवल अमेरिका के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए जोखिम और अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

समाधान की दिशा में आगे बढ़ें देश

कल यानी 24 मार्च के अंक में प्रकाशित अग्रलेख में आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के दुविधा ग्रस्त होने और अपनी ही जुबान से बार-बार पलटने को लेकर सटीक बातें कही हैं। ईरान पर भीषण हमलों की धमकियां देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक रुख बदलना उनके विरोधाभासी और अस्थिर नीति व्यवहार का एक और उदाहरण माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि ईरान होर्मुज समुद्र मार्ग को नहीं खोलता है, तो उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा। यह धमकी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई थी। ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि उसके बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ, तो वह न केवल होर्मुज समुद्री मार्ग को पूरी तरह बंद कर देगा, बल्कि तब तक नहीं खोलेगा, जब तक क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत नहीं हो जाती। इस टकराव ने वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक हलकों में अस्थिरता बढ़ा दी। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ट्रंप द्वारा अचानक पांच दिनों के लिए हमले रोकने की घोषणा करना चौंकाने वाला रहा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और इसी कारण बिजली संयंत्रों तथा तेल-गैस ठिकानों पर हमले रोक दिए गए हैं। हालांकि, इस दावे की पुष्टि ईरान की ओर से नहीं की गई, जिससे इस घोषणा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वर्तमान दौर में, जब दुनिया परमाणु क्षमताओं से लैस है, किसी भी बड़े युद्ध का परिणाम विनाशकारी और अनिश्चित हो सकता है। ऐसे में यह धारणा और मजबूत होती जा रही है कि आधुनिक युग में कोई भी देश पूर्ण विजय हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कूटनीति, संवाद और संतुलित रणनीति ही स्थायी समाधान का मार्ग बन सकते हैं।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मध्य प्रदेश।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

90 करोड़ के आसपास हैं चैटजीपीटी के साप्ताहिक यूजर्स। तीन वर्ष पहले शुरू हुई यह सेवा अब तक लगभग विज्ञापन मुक्त रही है। इसके केवल पांच प्रतिशत यूजर्स ही सदस्यता शुल्क देते हैं, जबकि अब इसमें बदलाव आ रहा है।

पश्चिम एशिया में महासंग्राम

विभीषिका की कीमत चुकाता आम आदमी

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध की आग 20 से अधिक देशों तक फैल चुकी है। इस कारण हजारों जानें तो गई ही हैं, बड़ी मात्रा में तेल और गैस के भंडार भी नष्ट हुए हैं। भारी मात्रा में संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। साथ ही, समुद्री मार्गों के बाधित होने के कारण पूरा विश्व फिलहाल तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से भी जूझ रहा है। युद्ध के कारण दुनिया में मुद्रास्फीति, गरीबी और खाद्य असुरक्षा भयंकर रूप से बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, इस युद्ध की कीमत आम आदमी को ही चुकानी होगी

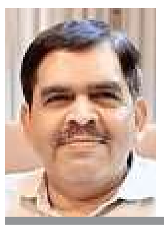

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाजों का आवागमन बाधित होने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। फाइल

पश्चिम एशिया में पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से महासंग्राम जारी है। फिलहाल इसके थमने की संभावना नहीं दिख रही है। इस युद्ध के तमाम दुष्प्रभावों के बीच समूचे विश्व में तेल और गैस का संकट बढ़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के निकट होर्मुज समुद्र मार्ग के बाधित होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक रूप से बाधा आने के साथ ही जहाजरानी लागतों में वृद्धि और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की उपलब्धता में कमी के चलते वैश्विक आपूर्ति आघात, अर्थव्यवस्थाओं में अफरा-तफरी मचा सकते हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका की तेल भंडारों पर पकड़ बनाने की महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है। हालांकि पहले तो यह कहा गया कि ईरान आणविक हथियार बना रहा है और इस कारण अमेरिका एवं विश्व की शांति भंग हो सकती है, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन के लोग भी यह कहने लगे हैं कि अमेरिका ने बिना वजह इस युद्ध को छेड़ा है। वे इजरायल को युद्ध भड़काने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कर उसो अमेरिका लाया जाना, और अब ईरान पर हमला करना, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि यह सब दुनिया के तेल भंडारों पर अमेरिका का काबिज होने की कोशिश का यह संकेत है। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का यह कहना है कि इससे पहले इराक में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से वहां के तेल भंडारों पर भी अमेरिका का लगभग कब्जा हो चुका है।

महंगाई का खतरा : वैसे तो कोई भी जंग महंगाई को बढ़ाने का कारण बनती है, लेकिन दुनिया की अधिकांश कच्चे तेल और गैस की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खाड़ी के देशों के इस जंग में शामिल होने के कारण स्वाभाविक तौर पर तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से महंगाई तो बढ़ती ही है, समुद्र के रास्ते सामान की आवाजाही में आने वाले अवरोधों के कारण साजोसामान की कमी के चलते भी महंगाई बढ़ती है। युद्ध जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, यह समस्या भीषण रूप लेती जा रही है। महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति, आवश्यक वस्तुओं की कमी और सरकारों द्वारा उसे वहन करने की शक्ति कम होने पर सामाजिक अशांति का भी खतरा बढ़ सकता है। समझा जा सकता है कि युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई आवश्यक वस्तुओं की कमी और यदि उसके कारण सामाजिक अशांति फैलती है तो उसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है।

वित्तीय बाजारों में खलबली : युद्ध के हालातों में निवेशकों का रुझान सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर हो जाता है। व्यवसायों में विश्वास डगमगाता है और अनिश्चितता फैलती है। ऐसे में शेयरों और बांडों में निवेश के बजाय लोग ज्यादा सोना, चांदी खरीदने लगते हैं। स्वाभाविक तौर पर शेयर बाजार गिरने लगते हैं। भारत की बात करें तो युद्ध के समय से लेकर अभी तक मुंबई स्टाक एक्सचेंज का सेंसेक्स सात प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में गिरावट का भी असर आम आदमी पर ही पड़ता है। पेंशन फंडों द्वारा शेयर बाजारों में निवेशित धन का मूल्य भी कम हो जाता है।

अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का असर : सामान्यतः भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का असर नकारात्मक ही पड़ता है। सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाते हैं। दूसरे, बढ़ते आयात बिल और संस्थागत निवेशकों द्वारा पूंजी के बहिर्गमन के कारण स्थानीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। गौरतलब है कि युद्ध के पिछले लगभग तीन सप्ताह में रुपये का मूल्य डालर की तुलना में लगभग चार प्रतिशत घट चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। तीसरे मुद्रास्फीति से निजात दिलाने के लिए सरकारों को ऊर्जा, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर अधिक सब्सिडी देनी पड़ती है या कर कम करने पड़ते हैं। ऐसे में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है जिसका सीधा असर दोबारा से मुद्रास्फीति पर पड़ता है जिसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है।

अमेरिका में भी भारी मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि इस बात की 50 प्रतिशत आशंका है कि अमेरिका अगले 12 महीनों में मंदी का शिकार हो जाएगा। इसके पीछे बढ़ती तेल कीमतें, युद्ध के कारण अवरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मार्ग आदि कारण बताए जा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा में बाधा : दुनिया में खाद्य पदार्थों का उत्पादन सभी देशों में ऐसा नहीं है कि हर देश अपनी खाद्य सुरक्षा स्वयं कर सके। ऐसे में इन देशों को खाद्य निर्यातक देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ता है। युद्ध के कारण वस्तुओं के आवागमन में बाधा आती है जिसके चलते खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाता है। खाद्य असुरक्षा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि आदि का सीधा असर भी आम आदमी पर ही पड़ता है। हालांकि भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अधिकांशतः आत्मनिर्भर है, इसके बावजूद तेलों और दालों के मामले में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी आम आदमी के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।

विकास पर प्रतिकूल प्रभाव : लंबे समय में, युद्ध के कारण व्यापार में रुकावटों और बढ़ती अनिश्चितता के कारण निवेश कम हो जाता है, जिससे वैश्विक जीडीपी की वृद्धि धीमी हो जाती है। दूसरे, युद्ध और पुनर्निर्माण पर बढ़ा हुआ खर्च सरकारों को अधिक कर्ज लेने के लिए बाध्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्ज बढ़ जाता है और भविष्य में वित्तीय दबाव पैदा होता है। तीसरे, युद्ध के कारण तकनीकी बदलावों की दिशा रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इससे इनोवेशन को बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन साथ ही संसाधनों को सामाजिक और विकासात्मक क्षेत्रों से हटाकर दूसरी ओर लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर, युद्ध आर्थिक प्राथमिकताओं को बदल कर संतुलित तथा टिकाऊ वैश्विक विकास को कमजोर कर सकता है।

आज सबसे जरूरी काम वैश्विक शांति को बहाल करना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास में कोई रुकावट न आए। कोविड के बाद वैश्विक विकास दर जो अभी 2.5 प्रतिशत से तीन प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, अभी तक कोविड-पूर्व के 3.5 प्रतिशत से चार प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक संवृद्धि की दर 0.2 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक और कम हो सकती है। युद्ध की विभीषिकाओं के चलते एक तरफ जान-माल का विध्वंस तो दूसरी ओर आम आदमी के लिए विकास दर में गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा विश्व के लिए किसी भी प्रकार से मंगलकारी नहीं हो सकती। विश्व के तमाम देशों को युद्ध की समाप्ति के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।

सूझबूझ से रणनीतिक कदम उठाए भारत

डा. अंशुल उपाध्याय

पश्चिम एशिया में युद्ध की भयंकरता निरंतर बढ़ती जा रही है। ईरान द्वारा हिंद महासागर में उपस्थित अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक अड्डे (डिएगो गार्सिया) में जो हमला किया गया, उसने परोक्ष रूप से ब्रिटेन को इस युद्ध में कूदने का निमंत्रण दिया है। ब्रिटेन का इस युद्ध में कूदना मतलब यूरोपीय देशों का युद्ध में शामिल हो जाना होगा। महासागरों में विश्व के विभिन्न देशों के नौसैनिक अड्डे इस प्रकार हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया : अमेरिका और यूके का प्रमुख संयुक्त बेस, जो हिंद महासागर में परिचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर, सेन डिएगो के अलावा अटलांटिक महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है, जो अमेरिकी अटलांटिक बेड़े का मुख्यालय है। ग्वांतानामो बे, क्यूबा में स्थित अमेरिका द्वारा नियंत्रित एक रणनीतिक अड्डा है।

अमेरिका के नौसैनिक अड्डे विश्व के सभी महासागरों में फैले हुए हैं। ये नौसैनिक अड्डे न केवल नौसेना, बल्कि वायु सेना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था, तब अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था।

वर्तमान में जब पश्चिम एशिया में युद्ध तीव्र गति ले रहा है। ऐसे में ईरान द्वारा अमेरिका के नौसैनिक बेस पर हमला करना और इजरायल के परमाणु संयंत्रों के करीब मिसाइल गिराना एक प्रकार से तबाही का संकेत दे रहा है। एक ऐसी तबाही जिसकी आग में यूरोप, अमेरिका और एशिया तीनों महाद्वीप सुलग जाएंगे। वहीं, अमेरिका द्वारा ईरान के ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाना और अप्रत्याशित रूप से ईरान की चीन और अन्य देशों द्वारा मदद किया जाना, हो न हो युद्ध को बढ़ा ही रहे हैं।

हालांकि भारत अपनी कूटनीति और रणनीति के लिए विख्यात है। इसलिए इस युद्ध में भी भारत को अपनी बुद्धिमता का परिचय देना होगा और युद्ध में अपनी भूमिका को नगण्य ही बनाए रखना भारत के हित में होगा। चूंकि भारत के पास उन्नत तकनीकी के साथ जल, थल और वायु सेना की विशाल फौज है। इसके चलते भारत को अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ईरान, अमेरिका और इजरायल से अपने संबंधों को भी संतुलित रखना होगा। ऐसा करने से कम से कम पूर्वी एशियाई देश मुख्य रूप से इस युद्ध में झुलसने से बच जाएंगे और भविष्य के ऊर्जा और जल संसाधनों को भी नष्ट होने से बचाया जा सकेगा।

(लेखिका रणनीतिक मामलों की जानकार हैं)

खरी-खरी

बातों बातों में

सावित्री शर्मा 'सवि'

दुनिया बातों से ही चलती है, आपके पास टैलेंट हो या न हो, इसका कोई अर्थ नहीं। बस आपको बातें बनानी आनी चाहिए। पूरी जिंदगी बातों का ही खेल चलता है। अब देखिए, बातों से ही नारद मुनि बिना माचिस तीली के आग लगा देते थे। एक कर्मचारी बातों बातों में ही अफसर को प्रभावित कर प्रमोशन पा जाता है। कितना काम किया, इसे कौन देखने जा रहा है? अब समय ही किसके पास है जो कोई जांचें परखे। फिर सामने वाला बातों से प्रभावित करने का हुनर भी रखता है।

हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। अरे, आडिट वाले आएं भी तो डर क्या है? लोग ऐसे उलझते उलझाते हैं, बातों को चाशनी से दिल के शीशे में उतार लेते हैं कि सामने वाला वाह-वाह या प्रशंसा किए बिना नहीं रहता और कोरे कागजों पर साइन तक कर बैठता है। बाद में भले अपनी मूर्खता भरी करतूत पर सिर फोड़ता फिरे। अब नेता जी को ही देख लीजिए, बातों का असर ही है जो बातों में ही वोटर का वोट कब चुरा लेते हैं, पता ही नहीं चलने देते।

उसका हो चुका पत्थर जैसा दिल, जो पिछले पांच साल से आंसू बहाते-बहाते सूख कर कठोर हो चुका है, हजार बार कह चुका है, "नेता जी आपके झूठे थे, अत्याचार चरम पर है, सब गैंडे की खाल में घूम रहे हैं, चोर बाजारी बढ़ रही है।" पर उसी पत्थर दिल को नेताजी ने क्षण भर में मोम बना पिघला दिया और वोटर के कान में कहा, "प्रिय मान्यवर, तुम्हीं मेरी मंदिर, तुम्हीं मेरी पूजा।" उसे फिर से भरोसा हो गया नेताजी की बातों का।

उसको अच्छा बुरा और उसके बच्चों का भविष्य एक होशियार वक्ता ही समझा पाता है। होशियार वक्ता की तो इतनी महिमा है कि वह आपका खाता खाली करवा दे, और तो और आपको खड़े खड़े ही बेच दे। इस कला के गुण सबमें नहीं होते। ईश्वर का जिस पर वरदहस्त होता है, उसी को ये कस्तूरी मिलती है। जो मेहनती काम को ही पूजा मानने वाले इंटरव्यू में मुंह ताकते रह जाते हैं, उत्कृष्ट वक्ता कमरे से चौड़े होकर छप्पन इंच मुस्कराहट लेकर शान से निकलता है। निकलना भी चाहिए, गुण है, घमंड भी होना चाहिए, गर्व तो छोटी चीज है।

पोस्ट

वर्तमान विपक्ष इसी भरोसे दिखता है कि एक्स पर पोस्ट के अलावा कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो ही उन्हें सत्ता में ले आएंगे।
उमाशंकर सिंह@umashankarsingh

अगर महिला आरक्षण विधेयक वास्तविक रूप ले पाता है तो यह मोदी सरकार का एक बेहतरीन राजनीतिक दांव होगा।
स्वाति चतुर्वेदी@bainjal

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलेगा। इस्लाम या ईसाई बनने के साथ ही यह दर्जा समाप्त हो जाएगा।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

ट्रंप जब कहते हैं कि ईरान को ऊर्जा क्षेत्रों पर हमला नहीं करना चाहिए या होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता के विरुद्ध है, तो दुर्योधन की याद आती है। अभिमन्यु की हत्या के बाद पांडवों ने जब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को छल का प्रयोग कर मार डाला तो दुर्योधन ऐसे ही नैतिकता की दुहाई दे रहा था। युद्ध में कौनसी नैतिकता होती है? युद्ध तो अपने आप में अनैतिक है।
सुशांत झा@jhasushant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरानी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाने के फैसले से पश्चिम एशिया में तनाव कुछ घटेगा?

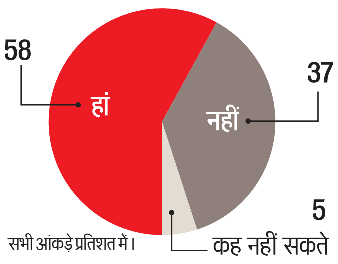

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ आम महिलाओं को भी मिलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सिंपैथी ईरान से रखता है कश्मीर,
काश वहाँ भी आज तो होता कोई मुनीर।
होता कोई मुनीर बरतता जरा कड़ाई,
कहता जा ईरान वहीं अब लड़ो लड़ाई।
'वे' कुत्ते की पूँछ सदा रहती जो ऐंठी,
यहां खाय ईरान संग रक्खें सिंपैथी !
– ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

गलत को दोहराना सही होने की गारंटी नहीं

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

अंग्रेजी की एक कहावत है- टू रांग्स डू नाट मेक ए राइट। यानी दो गलतियां एक सही नहीं बना सकतीं। यह कहावत यहां इसलिए दी जा रही है क्योंकि विपक्ष में रहकर जो नेता किसी घटना को लेकर जोर-जोर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सत्ता में आने पर उसी तरह की घटना को लेकर अपनी जुबान को ताले लगा लेते हैं। वस्तुतः पिछले चार दिनों से पंजाब में वेयरहाउस कारपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या को लेकर जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है, उससे सरकार रक्षात्मक मोड में है, क्योंकि आत्महत्या को लेकर सरकार का एक कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर इसमें फंसा हुआ है। भुल्लर ने अपने पिता का गोदाम बनाने का टेंडर देने के लिए रंधावा पर दबाव बनाया हुआ था।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार की ओर से इस मामले में अब तक जो कार्रवाई की है, उसको सही ठहराते हुए कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंसाफ के लिए आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के मंत्री पर भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती है, जबकि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए न्याय की बलि चढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में एडीजीपी वाइएस पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की, तो कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन भाजपा और उसकी सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने में उतर आई।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आज इसी तरह का बयान दिया है। दरअसल,

लालजीत सिंह भुल्लर। फाइल

आम आदमी पार्टी के दोनों नेता इस बात से परेशान हैं कि कार्रवाई के बावजूद विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहा है? या सीबीआइ की जांच क्यों मांगी जा रही है, जबकि पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर यह आश्वासन दिया था जिसमें कांग्रेस के सांसदों ने इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हरियाणा में एडीजीपी वाइएस पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की थी, तब किन लोगों ने सीबीआइ की जांच करवाई थी और इस्तीफा दिया था। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान पटियाला में एक व्यक्ति द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर आत्महत्या कर ली गई थी, तब की सरकार ने किन लोगों की जांच करवाई और किसने इस्तीफा दिया। अकाली-भाजपा के कार्यकाल में महल कला में एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या की गई। क्या उस मामले में सीबीआइ जांच हुई या किसी ने इस्तीफा दिया?

यह सही है कि मुख्यमंत्री ने जिन घटनाओं का जिक्र किया, वे सभी ऐसी घटनाएं थीं, जिनको लेकर विपक्ष ने तब खूब शोर-शराबा किया, सड़कों पर धरने दिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। रोष में आए लोगों ने चुनाव के समय अपना गुस्सा भी प्रकट किया और सत्ता को विपक्षी पार्टियों को सौंप दिया। ये सब गलतियां रही ही हैं, इनसे कोई भी इन्कार नहीं कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या यह निकाला जाना चाहिए कि अगर उस समय गलतियां हुई थीं, तो मौजूदा सरकार को भी उतना ही हक है गलतियां करने का? क्या दो गलतियां एक सही बना सकती हैं?

निस्संदेह मौजूदा घटनाक्रम में किसी जनरल मैनेजर को प्रताड़ित करने के मामले में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने ले लिया, लेकिन इस तरह किसी को अपनी जान दे देने के लिए मजबूर करने वाले मंत्री पर केस दर्ज करने में 17 घंटे और उसे गिरफ्तार करने में 48 घंटे लगने को मुख्यमंत्री भगवंत मान जस्टिफाई कैसे करेंगे? अच्छा होता कि संबंधित मंत्री पर यह कार्रवाई आधे घंटे के भीतर होती, ताकि वह अन्य उन ताकतवर लोगों के लिए एक मिसाल बनती, जो अपने अधीनस्थों पर दबाव डालकर गलत काम करने को कहते हैं और नहीं करने पर परिवार सहित जान से मार देने की धमकियां देते हैं। संभवतः ऐसा किया होता तो जिस काम के लिए आज विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसी काम के लिए आम लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे होते।

दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि सत्ता में रहते हुए अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने को कोसने वाली आम आदमी पार्टी को क्या यह बिल्कुल पता नहीं चला कि उनका मंत्री अपने पिता के नाम पर बड़े-बड़े गोदाम बनाने के ठेके ले रहा है और वह भी अपने पद का दबाव बनाकर... ?

मंथन

एआइ और बाजार का गठजोड़

एआइ आज विश्व में बदलाव का सबसे बड़ा वाहक साबित होता दिख रहा है। बाजार और विज्ञापन की रणनीति को यह कैसे बदल रहा है, इसे कई रूपों में समझा जा सकता है

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

डिजिटल दुनिया आज कई युगांतकारी बदलावों के मुहाने खोल रही है। इसमें सबसे दिलचस्प है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के जोर पर आकार लेता विज्ञापनों का नया संसार। यह संसार अपनी प्रस्तुति में तो मोहक है ही, संरचनात्मक लिहाज से खासा रणनीतिक भी है। दरअसल, जिस तरह कभी सर्च इंजन और इंटरनेट मीडिया ने विज्ञापनों की पूरी प्रकृति बदल दी थी, अब वही बदलाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नए संवादात्मक मंचों तक पहुंच गया है। हाल के घटनाक्रम को देखकर साफ लगता है कि एआइ अब महज सवाल-जवाब का माध्यम नहीं, बल्कि वह वाणिज्य, ब्रांडिंग और लक्षित विपणन का भी बड़ा मंच बनने जा रहा है। इस परिवर्तन को इस क्षेत्र की तीन दिग्गज कंपनियों एंथ्रोपिक, ओपनएआइ और गूगल की रणनीतियों को देखकर समझा जा सकता है। ये तीनों कंपनियां अमेरिकी हैं। कह सकते हैं कि बदलाव की ये आंधी एक बार फिर उस देश से ही पूरी दुनिया में बहेगी, जिसने इंटरनेट के आमद के दौर से अपनी भूमिका को लगातार निर्णायक बनाए रखा है।

एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपने विज्ञापन अभियान के जरिये चर्चा बटोरी। सुपर बाउल से जुड़े विज्ञापनों में एक एआइ सहायक बातचीत के बीच अचानक जूते के इनसोल या डेटिंग सेवा जैसे उत्पादों का प्रचार करने लगता है। ऐसा करते हुए यह संदेश भी दिया जाता है कि एआइ में विज्ञापन आने वाले हैं, चैटबाट क्लाड में नहीं। इस अभियान ने लोगों की उस चिंता को बढ़ाया कि जिन एआइ प्लेटफार्म पर वे भरोसा करते हैं, वहां यदि विज्ञापन शामिल हुए तो उपयोगी सलाह और प्रायोजित प्रभाव के बीच की रेखा बेहद धुंधली होकर रह जाएगी।

रुचियों के अनुरूप विज्ञापन : इस तरह की चिंता स्वाभाविक है। वैसे सच यह भी है कि डिजिटल दुनिया का अधिकांश हिस्सा पहले से ही लक्षित विज्ञापन पर आधारित है। सर्च इंजन, इंटरनेट मीडिया फीड और ई-कामर्स मंच वर्षों से उपयोगकर्ता की रुचियों के अनुरूप विज्ञापन दिखा रहे हैं। फर्क महज इतना है कि यह माध्यम ज्यादा निजी और भरोसेमंद होगा और ऐसे में विज्ञापनों का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ जाएगा। इस बीच, ओपनएआइ ने अपने लोकप्रिय चैटबाट चैटजीपीटी में अमेरिका के चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए विज्ञापनों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि सभी विज्ञापन स्पष्ट रूप से प्रायोजित होने की घोषणा के साथ होंगे। यह भी कि इन्हें मुख्य उत्तर से अलग रखा जाएगा और उपयोगकर्ताओं के लिए यह केवल एक विकल्प रहेगा कि उन्हें वह विज्ञापन क्यों दिखाया गया। वे चाहें तो विज्ञापन डाटा हटा भी सकेंगे।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैटजीपीटी के साप्ताहिक उपयोगकर्ता 90 करोड़ के आसपास हैं और यह इंटरनेट की सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों में शामिल है। तीन वर्ष पहले शुरू हुई यह सेवा अब तक लगभग विज्ञापन मुक्त रही है। इसके महज पांच प्रतिशत उपयोगकर्ता ही सदस्यता शुल्क देते हैं। ऐसे में स्थायी वित्तपोषण माडल की आवश्यकता स्वाभाविक है। छोटा-सा भुगतान करने वाला वर्ग लंबे समय तक पूरी व्यवस्था का खर्च नहीं उठा सकता।

यदि यह माडल पारदर्शी और वैकल्पिक हो, तो यह एक संतुलित समाधान बन सकता है। टेलीविजन, यूट्यूब और अनेक समाचार वेबसाइटें इसी ढांचे पर टिके हैं- जो भुगतान नहीं करते, वे विज्ञापन देखते हैं। इसी तरह जो विज्ञापन नहीं चाहते, वे सदस्यता लेते हैं। एआइ में भी ऐसा संतुलन उभर सकता है। इन सबके बीच कांटेक्स्चुअल एड की अवधारणा भी आकार ले रही है। पारंपरिक डिजिटल विज्ञापन अक्सर कुकी और क्रास-साइट ट्रैकिंग के आधार पर उपयोगकर्ता की रुचि का अनुमान लगाते हैं। इसके विपरीत, कांटेक्स्चुअल एड उसी क्षण की जरूरत पर आधारित होते हैं। मसलन, यदि कोई उपयोगकर्ता पूछे कि मैं दोस्तों के लिए आसान मैक्सिकन व्यंजन बनाना चाहता हूं, सामग्री क्या होगी। इस पर अब एआइ पहले रेसिपी बताएगा और फिर स्पष्ट लेबल के साथ किसी स्थानीय सुपरमार्केट या मील-किट का प्रायोजित लिंक दिखाएगा। इस तरह निर्णय से क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया एक ही संवाद में पूरी होगी।

इस बारे में गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल में संपन्न इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट में कहा कि आनलाइन खरीदारी तेजी से एआइ-चालित होगी, एआइ एजेंट उपयोगकर्ताओं को उत्पाद खोजने, तुलना करने और खरीद पूरी करने में मदद करेंगे। पिचाई ने भारत में 15 अरब डालर के बुनियादी ढांचा निवेश की घोषणा भी की, जिसमें विशाखापत्तनम में एक फुल-स्टैक एआइ हब स्थापित करने की योजना शामिल है।

प्रतीकात्मक

विज्ञापनों की इस नई दुनिया से जुड़े बदलाव और विमर्श का एक वैश्विक आयाम भी है। दुनिया में छह में से करीब एक व्यक्ति जेनरेटिव एआइ का उपयोग करता है, किंतु इसका वितरण असमान है। विकसित देशों की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लागत और पहुंच बड़ी चुनौती है। यदि विज्ञापन-आधारित माडल सेवाओं को कम लागत पर उपलब्ध रखने में सहायक होता है, तो छात्रों, नौकरी चाहने वालों और छोटे संगठनों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। यह भी कि यदि निर्धारित सुरक्षा मानक मजबूत रहे, तो एआइ में विज्ञापन पहुंच बढ़ाने, यूजर्स सुविधा सुधारने और डिजिटल विभाजन कम करने का माध्यम बन सकते हैं। इसके उलट यदि भरोसे की नींव कमजोर हुई, तो यह प्रयोग भारी भी पड़ सकता है। यही संतुलन एआइ युग की दिशा तय करेगा।

वनप्लस इंडिया के सीईओ राबिन लियू ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली : चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता कंपनी वनप्लस इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राबिन लियू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वह लगातार घट रही बिक्री को फिर से सुधारने की कोशिश कर रही है। साइबरमीडिया रिसर्च रिसर्च के अनुसार, लियू के कार्यकाल में 2025 में कंपनी की बिक्री में 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। (प्रेट्र)

ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और भुगतान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आरबीआइ अधिक डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफार्म विकसित कर रहा है।
– पी. वासुदेवन, कार्यकारी निदेशक, आरबीआइ

सेंसेक्स	74,068.45	▲ 1,372.06
निफ्टी	22,912.40	▲ 399.75
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,43,600	▲ ₹1,200
चांदी प्रति किलोग्राम	₹2,30,000	बदलाव नहीं
डालर	₹93.76	▲ ₹0.23
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 101.4	

एक नजर में

मणिपाल हेल्थ ने जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली : अस्पताल चेन का संचालन करने वाली कंपनी मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, इस आइपीओ में आठ हजार करोड़ रुपये के नए शेयर और 4,32,27,668 प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि में से 5,378 करोड़ रुपये कर्ज भुगतान और 574 करोड़ रुपये सब्सिडियरी सहयाद्री हास्पिटल्स में हिस्सेदारी खरीदने पर किया जाएगा। (प्रेट्र)

गुजरात में एक और संयंत्र लगाएगी मारुति सुजुकी

नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात में बनने वाले नए मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र के पहले चरण में 10,189 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता सालाना 2.5 लाख इकाई होगी। खोरज औद्योगिक एस्टेट में बनने वाला यह मारुति का देश में पांचवां मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र होगा। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि पहले चरण का निर्माण कार्य 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 24 लाख इकाई है। (प्रेट्र)

अगले वर्ष घट सकता है निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च

नई दिल्ली : अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान के दौरान निजी क्षेत्र का नई संपत्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत खर्च 16.5 प्रतिशत घटकर 9.55 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में नई संपत्तियों के अधिग्रहण पर कुल पूंजीगत खर्च 11.43 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सर्वेक्षण में 5,366 चालू उद्यमों में से 4,203 (लगभग 78.3 प्रतिशत) ने अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए अपनी पूंजीगत निवेश योजनाओं की जानकारी दी। (प्रेट्र)

अमेरिका-ईरान वार्ता से भारतीय बाजारों में उछाल

संसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,068 पर पहुंचा, एनएसई निफ्टी में 400 अंकों की बढ़त रही

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के एनर्जी इन्फ्रा पर किए जाने वाले हमलों पर अस्थायी रोक के एलान से मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग दो प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत उछलकर 74,068.45 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान एक समय यह 1,793 अंक या 2.46 प्रतिशत चढ़कर 74,489.39 के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 399.75 अंक या 1.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,912.40 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में लार्सन एंड टूब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, इटरनल, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। केवल पावरग्रिड और एसबीआइ के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति 7.56 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4,22,78,312.77 करोड़ रुपये हो गई। ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर कहा है कि उन्होंने ईरान के लिए स्ट्रेट आफ होर्मुज को फिर से खोलने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह जलडमरूमध्य पर्शियन गल्फ और गल्फ आफ ओमान के बीच स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को पांच दिनों तक टालने का भी एलान किया है।

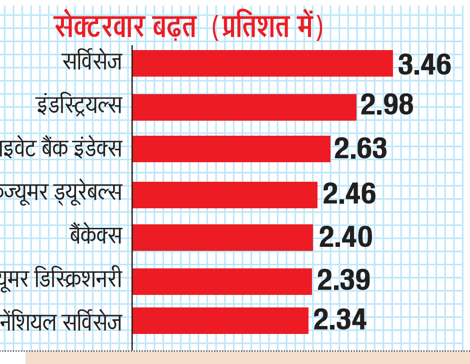

सोमवार को हुई भारी बिकवाली के बाद बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। यह रिकवरी मुख्य रूप से जोखिम की धारणा में आई कमी के कारण हुई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में संभावित कमी के शुरुआती संकेतों ने निवेशकों का कुछ भरोसा बहाल करने में मदद की। इस तेजी को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
–हरिप्रसाद के, संस्थापक, लाइवलांग वेल्थ

एशियाई बाजारों में भी रही तेजी

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स काफी बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त रही थी।

23 पैसे टूटकर 93.76 के रिकार्ड निचले स्तर पर रुपया

मुंबई, प्रेट्र : रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.76 प्रति डालर पर आ गया। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की मजबूती और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते निवेशकों में चिंता का माहौल रहने से घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों की निकासी ने भी रुपये पर दबाव डाला। रुपया 93.66 पर खुला और अंत में यह 93.76 पर रहा, जो पिछले बंद स्तर से 23 पैसे की गिरावट है।

पूर्व चेयरमैन के पत्र की स्वतंत्र जांच कराएगा एचडीएफसी बैंक

नई दिल्ली, प्रेट्र : एचडीएफसी बैंक ने अपने पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के त्याग पत्र में उठाए गए मुद्दों की स्वतंत्र जांच के लिए कई बाहरी ला फर्म नियुक्त की है। बैंक ने एक निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाया है।

बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उन उच्चतम प्रशासन मानकों के साथ लगातार तुलना करना है, जिनका पालन बैंक दशकों से करता आ रहा है। बता दें कि अतनु चक्रवर्ती ने देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से 18 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया था। अपने त्याग पत्र में चक्रवर्ती ने नैतिक चिंताओं का हवाला दिया था। यह पहली बार है जब एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन ने कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ दिया है, जिससे बैंक के कामकाज को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

अप्रैल से फरवरी के दौरान 99 कंपनियों ने आइपीओ से जुटाए 1.65 लाख करोड़ रुपये

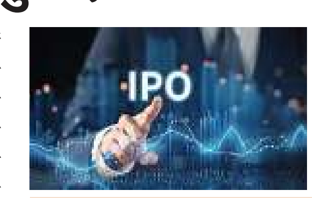

- 2024-25 में 79 कंपनियों ने 1.62 लाख करोड़ जुटाए थे
- एनएसई इमर्ज पर 105 कंपनियों ने 5,121 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत का प्राइमरी मार्केट मजबूत बना हुआ है और मेनबोर्ड आइपीओ ने अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि एसएमई सेगमेंट में सक्रियता थोड़ी कम रही। एनएसई मार्केट पल्स रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से फरवरी के दौरान 99 कंपनियों ने अपने पब्लिक इश्यू लांच किए, जिनसे उन्होंने कुल 1.65 लाख करोड़ रुपये जुटाए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 79 कंपनियों के आइपीओ आए थे और इन्होंने कुल मिलाकर 1.62 लाख रुपये जुटाए थे। यह वृद्धि बड़े पब्लिक आफरिंग में निवेशकों की लगातार दिलचस्पी को दिखाती है।

दूसरी ओर, इस दौरान एसएमई सेगमेंट में कुछ नरमी दिखाई पड़ती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर कुल 105 आइपीओ लांच किए गए और इनके जरिये 5,121 करोड़ रुपये जुटाए गए। यह वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले कम है। उस समय 163 आइपीओ ने 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए थे। कुल मिलाकर दोनों सेगमेंट के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 204 कंपनियों ने आइपीओ के जरिये 1.70 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 242 कंपनियों ने 1.69 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पता चलता है कि आइपीओ की संख्या में कमी आई है, लेकिन बड़े आकार के चलते जुटाए गए कुल फंड मजबूत बने रहे। रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में एसएमई आइपीओ का आकार लगभग औसत 50 करोड़ रुपये रहा है।

मेनबोर्ड पर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों का रहा दबदबा

सेक्टर के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों ने मेनबोर्ड के जरिये निवेश जुटाने में अपना दबदबा बनाए रखा और इनका कुल योगदान 34 प्रतिशत रहा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फर्मों का योगदान 31 प्रतिशत रहा जबकि इंडस्ट्रियल कंपनियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत रही। एसएमई में इंडस्ट्रियल कंपनियों ने 36 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा योगदान दिया।

अब स्विगी ने प्लेटफार्म फीस 17 प्रतिशत बढ़ाई

नई दिल्ली, आइएएनएस : जोमैटो के बाद फूड अब डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने अपनी प्लेटफार्म फीस में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। स्विगी के एप पर उपलब्ध बिलिंग के अनुसार, अब उसके प्लेटफार्म से खाना मंगाने वालों को 17.58 रुपये प्रति आर्डर की प्लेटफार्म फीस देनी पड़ेगी, जो पहले 14.99 रुपये प्रति आर्डर थी। यानी अब ग्राहकों को प्लेटफार्म फीस के रूप में प्रति आर्डर 2.59 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

यह संशोधित फीस अब स्विगी के एप पर दिख रही है। कंपनी ने यूजर्स को बताया है कि यह बढ़ोतरी उसे "प्लेटफार्म को चलाने और उसका रखरखाव करने" में मदद करने के लिए की गई है। पिछले सप्ताह ही जोमैटो ने अपनी प्लेटफार्म फीस में 19 प्रतिशत या दो रुपये प्रति आर्डर की बढ़ोतरी की थी। ताजा संशोधन के बाद स्विगी और जोमैटो दोनों की प्लेटफार्म फीस जीएसटी के साथ 17.58 रुपये प्रति आर्डर के करीब हो गई है।

मिस-सेलिंग पर बैंक को लौटाना होगा ग्राहकों को पूरा पैसा

राजीव कुमार ● जागरण

- बैंकों में थर्ड पार्टी उत्पाद बेचने को लेकर आरबीआइ ला रहा है नया नियम
- सभी बैंकों को बनाना होगा एक तंत्र, तय समयसीमा में दूर करनी होगी शिकायत

नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस जैसे थर्ड पार्टी उत्पाद ग्राहकों को भ्रामक जानकारी देकर बेचना अब बैंकों को भारी पड़ सकता है। मिस-सेलिंग को लेकर लगातार शिकायत मिलने पर आरबीआइ बैंकों के लिए नया नियम लाने जा रहा है जो आगामी जुलाई से लागू हो सकता है। नए नियम को लेकर आरबीआइ की तरफ से जारी मसौदे के मुताबिक अगर ग्राहकों को लगता है कि उसे गुमराह करके या भ्रामक जानकारी देकर बैंक ने उत्पाद की बिक्री की है तो वह उसकी शिकायत कर सकता हैं।

ग्राहकों की शिकायत प्राप्त करने के लिए सभी बैंक एक तंत्र बनाएंगे और ग्राहकों को शिकायत के लिए एक समयसीमा दी जाएगी। अगर समयसीमा नहीं दी गई है तो ग्राहक उत्पाद के खरीदने के अधिकतम 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आरबीआइ के मसौदे के मुताबिक मिस-सेलिंग को लेकर अगर ग्राहक की शिकायत सही पाई जाती है तो बैंक ग्राहक को पूरा पैसा वापस करेगा और उत्पाद को रद करने की सूचना ग्राहक को देगा। अगर ग्राहक को उस खरीदारी से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसका भुगतान भी बैंक करेगा। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की मिस-सेलिंग पर बैंक के कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाए। बैंक अपने किसी उत्पाद के साथ थर्ड पार्टी के उत्पाद को नहीं जोड़ेगा। थर्ड पार्टी उत्पाद की बिक्री के बाद बैंक ग्राहकों से 30 दिनों के भीतर फीडबैक भी लेगा कि ग्राहक उस उत्पाद से कितना संतुष्ट है। इस फीडबैक के आधार पर छमाही रूप से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

एसबीआइ ने थर्ड पार्टी के उत्पाद बेचकर कमाएं 4,522 करोड़ : बैंकों में किसी अन्य के वित्तीय उत्पाद को बेचने का चलन है। बैंकों को इस बिक्री पर कमीशन या शुल्क का भुगतान होता है। पिछले पांच सालों के दौरान बैंकों को थर्ड पार्टी वित्तीय उत्पादों को बेचने से मिलने वाले कमीशन की राशि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रकार की बिक्री से कमीशन के रूप में 4522 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 652 करोड़ रुपये अधिक है। अभी बैंकों में लोन लेने के दौरान थर्ड पार्टी उत्पाद बेचने की पेशकश की जाती है। छोटे शहरों के कम जानकार जमाकर्ताओं को थर्ड पार्टी उत्पाद से अधिक लाभ मिलने की बात बताकर उन्हें इसकी बिक्री कर दी जाती है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मिस-सेलिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि बैंक को अपने मुख्य काम (जमा लेना और उधार देना) पर ध्यान देना चाहिए।

रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : अर्थशास्त्रियों के अनुसार आरबीआइ आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में (6-8 अप्रैल) में यथास्थिति बनाए रख सकता है। इसका कारण यह है कि निकट भविष्य में वैश्विक घटनाक्रमों का असर महंगाई के बजाय विकास पर ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। अग्रणी निवेश बैंक एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा स्थिति का ज्यादा असर विकास पर ज्यादा पड़ेगा। एचएसबीसी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, "हमारा मानना है कि आठ अप्रैल की बैठक पूरी तरह से तेल की कीमतों में झटके को लेकर चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होगी।"

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान के सिंध में फिर एक हिंदू किशोरी का अपहरण

- सिंध में हाशिए पर रहने वाले हिंदू समुदायों में मेघवार, भील और कोल्ही शामिल
- मानवाधिकार समूह ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ी हिंसा की ओर ध्यान खींचा

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तानी मानवाधिकार संगठन वायस आफ पाकिस्तान माइनारिटी (वीओपीएम) ने कहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 15 वर्षीय हिंदू लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया गया है। इससे लड़की का परिवार निराशा में डूबा है। संगठन ने नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण पर चिंता व्यक्त की है, जो इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक लड़कियों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है।

वीओपीएम ने मंगलवार को कहा,हिंदू अल्पसंख्यक मीरान मेघवार का उसके घर से तारेक काउरी और अल्ला डीनो काउरी नाम के दो लोगों को अगवा कर लिया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद लड़की कहां है, इसका कुछ पता नहीं चला है। सिंध में हाशिए पर रहने वाले हिंदू समुदायों (मेघवार, भील, और कोल्ही) के लिए मीरान का लापता होना अलग घटना नहीं है, बल्कि एक दिल दहला देने वाले पैटर्न का हिस्सा है। यह स्पष्ट संकेत है कि ग्रामीण सिंध में अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों के लिए सुरक्षा कितनी कमजोर हो सकती है। मेघवार परिवार ने पुलिस अफसरों और नागरिक समाज से आग्रह किया है कि वे उनकी बेटी के अगवा होने को गंभीरता से लें। वे मीरान की सुरक्षित, स्वतंत्र व बिना किसी नुकसान के वापस चाहते हैं। मीरपुरखास में समुदाय ने परिवार के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। न्याय की मांग को दोहराते हुए एक निवासी ने कहा, "न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना है।" हिंदुओं का तर्क है कि बहुत से मामले अनसुलझे रह जाते हैं।

दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप

वेलिंगटन, एपी : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास मंगलवार को एक मजबूत भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, 7.6 तीव्रता वाले भूकंप की गहराई करीब 237 किमी थी। भूकंप का केंद्र टोंगा के दूसरे सबसे बड़े शहर नेयाफू से 153 किमी पश्चिम में था। अभी तक किसी भी प्रकार की हानि की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि भूकंप के कारण तटीय क्षेत्रों को खाली करा लिया गया, पर व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। ज्ञात हो, भूकंप की गहराई बहुत अहम होती है। जितना भूकंप सतह के करीब होता है, उतना ही ज्यादा झटका महसूस होता है। टोंगा के आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यालय के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती, लोगों को समुद्र तटों और निचले तटीय क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए।

कोलंबिया में सैन्य विमान दुर्घटना में 66 लोगों की मौत, चार अब भी लापता

न्यूयार्क टाइम्स से

- उड़ान भरने के दौरान रनवे के अंत में किसी चीज से टकराने की आशंका
- मरने वालों में 58 सैनिक, छह वायुसैनिक और दो पुलिस अधिकारी शामिल

बोगोटा : कोलंबिया में सेना के परिवहन विमान हरक्यूलिस सी-130 के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 66 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने दर्जनों जीवित बचे लोगों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। चार लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। विमान में कुल 128 लोग सवार थे।

देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख ह्यूगो अलेजांद्रो लोपेज के अनुसार, विमान में वायुसेना के 11 जवान, थलसेना के 115 जवान व राष्ट्रीय पुलिस के दो अधिकारी सवार थे। मृतकों में 58 सैनिक, छह वायुसैनिक और दो पुलिस अधिकारी शामल हैं। लोपेज ने बताया कि जीवित बचे लोगों में से 57 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 27 की हालत गंभीर है।

कोलंबिया के प्यूर्टो लेगुइजामो में सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हरक्यूलिस सी-130 विमान के पास बचावकार्य में जुटे सैनिक। रायटर

रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने 'एक्स' पर बताया कि दुर्घटना तब हुई जब विमान पेरू की सीमा पर स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था। अग्निशमन विभाग ने आशंका जताई है कि उड़ान भरते समय विमान रनवे के अंत में किसी चीज से टकरा गया। उसके बाद नीचे गिरते समय विमान का एक पंख एक पेड़ से टकरा गया। इस कारण विमान में आग लग गई और उसमें लदे कुछ विस्फोटक उपकरण फट गए। इस दूरदराज क्षेत्र में स्थानीय निवासी सबसे पहले जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने के लिए आगे आए। एक वीडियो में लोगों को अपनी मोटरसाइकिलों के पीछे घायल सैनिकों को बिठाकर कच्ची सड़क पर तेजी से ले जाते हुए देखा जा सकता है।

रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन की बौछार, हमले में चार की मौत, 27 घायल

कीव, रायटर : रूस ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्रों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। गत 24 घंटों में मास्को ने यूक्रेन पर लंबी दूरी के 400 ड्रोन दागे। इस हमले में चार नागरिकों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए हैं।

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, ड्रोन के अलावा रूस ने 23 क्रूज और सात बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागीं। इन हमलों ने देश भर में 10 स्थानों को निशाना बनाया। राजधानी कीव में मंगलवार सुबह भी दर्जनों ड्रोन मंडराते देखे गए, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ज्ञात हो, चार साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की कोशिशें विफल रही हैं। रूस ने युद्धविराम के यूक्रेनी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। ईरान युद्ध की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होने से यूक्रेन की स्थिति की अनदेखी हो रही है, जिससे वहां मानवीय संकट और गहरा गया है।

सूडान के अस्पताल में हुए हमले में अब तक 70 लोगों की मौत

जेनेवा,रायटर : सूडान के एक अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और चिकित्सक शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि पूर्वी दारफुर स्थित अल दीन टीचिंग अस्पताल पर 20 मार्च को हमला हुआ था, हालांकि उसने किसी पर दोष नहीं लगाया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस हमले के कारण चिकित्सा सुविधा ठप हो गई है। यह 20 लाख से अधिक लोगों के लिए रेफरल अस्पताल के रूप में कार्य करती थी। सूडान में डब्ल्यूएचओ की कार्यवाहक उपप्रतिनिधि हाला खुदारी ने ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ने कहा, हवाई हमले में ड्रोन का प्रयोग किया गया था। हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुआ था, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृहयुद्ध में सेना से लड़ रही है।

20 अरब डालर से चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाएगा नासा

- चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना रद
- नासा प्रमुख ने कहा- लगभग असंभव को संभव करने के लिए प्रतिबद्ध

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका चांद पर स्थायी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इस योजना पर 20 अरब डालर खर्च होंगे। नासा ने मंगलवार को कई पहलों को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें चंद्र मिशन में तेजी लाने, चंद्रमा पर बेस बनाने, विज्ञान मिशनों का विस्तार करने की योजनाएं शामिल हैं। वहीं, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की अपनी योजना रद करने का फैसला लिया है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख जेरेड इसाकमैन ने कहा, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बजाय अगले सात वर्षों में चंद्रमा की सतह पर बेस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दिसंबर में नासा की कमान संभालने वाले इसाकमैन ने नासा के वाशिंगटन मुख्यालय में एक कार्यक्रम के अवसर पर नासा के प्रमुख चंद्र मिशन - आर्टेमिस में किए जा रहे कई बदलावों के बारे में बताया।

इसाकमैन ने कहा, नासा एक बार फिर लगभग असंभव को संभव करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही चंद्रमा पर पहुंचना, चंद्रमा पर बेस बनाना शामिल है। महाशक्तियों की इस प्रतिस्पर्धा में समय तेजी से बीत रहा है, और सफलता या विफलता का निर्धारण वर्षों में नहीं, महीनों में होगा। किसी को हैरत नहीं होना चाहिए कि हम गेटवे को उसके वर्तमान स्वरूप में रोक रहे हैं और ऐसे बुनियादी ढांचे पर जोर रहे हैं जो चंद्र सतह पर निरंतर संचालन का समर्थन करे। लूनर गेटवे स्टेशन का अधिकांश भाग पहले ही बन चुका है और इसे चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया गया था।

लूनर गेटवे को रिसर्च प्लेटफार्म और ट्रांसफर स्टेशन दोनों के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका उपयोग अंतरिक्षयात्री चंद्र सतह पर उतरने से पहले चंद्र लैंडर पर सवार होने के लिए करेंगे। नासा ने कहा कि उपयुक्त हार्डवेयर का पुनः उपयोग किया जाएगा और इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की प्रतिबद्धताओं का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्तावों के अनुरोध के मसौदे आने वाले दिनों में जारी किए जाएंगे।

नासा की योजना में 2027 में एक और मिशन और उसके बाद हर साल कम से कम एक चंद्र लैंडिंग का लक्ष्य रखना शामिल है। 2027 में निर्धारित आर्टेमिस III, आर्टेमिस IV चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले पृथ्वी की कक्षा में एकीकृत प्रणालियों, परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करेगा। कहा,वह चंद्र सतह पर अधिक बार और किफायती मानवयुक्त मिशनों का समर्थन करने के लिए दोबारा इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर को शामिल करना शुरू करेगा। नासा ने कहा कि शुरुआत में उसका लक्ष्य हर छह महीने में लैंडिंग करना है, और बाद में इसमें और तेजी आएगी।

अमेरिका के 14 राज्यों में गर्मी ने तोड़ा रिकार्ड

न्यूयार्क, एपी : अमेरिका के 14 राज्यों में मार्च महीने में गर्मी ने पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र से उठी भीषण गर्मी अब विशाल 'हीट डोम' के रूप में पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे पूरे देश में तापमान असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाल के वर्षों की सबसे व्यापक और तीव्र ताप लहरों में से एक साबित हो सकती है।

राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी ग्रेग गैलिना के अनुसार, यह स्थिति अप्रैल की शुरुआत तक जारी रह सकती है। इस बार गर्मी का दायरा बेहद बड़ा है, जो इसे असामान्य बनाता है। वहीं, येल क्लाइमेट कनेक्शंस के जेफ मास्टर्स ने कहा, हीट डोम के कारण कई शहरों में रिकार्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है। दक्षिणी व मध्य मैदानी क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि देश के एक-तिहाई हिस्से में मार्च के उच्चतम तापमान के रिकार्ड के करीब पहुंच सकता है।

बांग्लादेश के प्रभावशाली पूर्व सैन्य जनरल मसूद उद्दीन चौधरी गिरफ्तार

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को प्रभावशाली पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मसूद उद्दीन चौधरी को उनके ढाका स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया।

डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख शफीकुल इस्लाम के अनुसार, चौधरी पर पांच विभिन्न मामले दर्ज हैं। हालांकि उनके विवरण अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं। मसूद उद्दीन चौधरी को 2007 के सैन्य-समर्थित तख्तापलट का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन 'नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आन सीरियस क्राइम' के समन्वयक के रूप में भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया था।

मसूद उद्दीन चौधरी के कार्यकाल के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वह आस्ट्रेलिया में राजदूत रहे और बाद में शेख हसीना की सहयोगी 'जातीय पार्टी' से सांसद बने। उन पर शेख हसीना और खालिदा जिया को राजनीति से बेदखल करने के लिए 'माइनस टू फार्मूला' लागू करने की कोशिश का आरोप था। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जुलाई में उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए गए थे।

मसूद उद्दीन चौधरी। फाइल

चिंतन

धर्मांतरण रोकने में अहम साबित होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता यानी वह अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले लाभ व विशेषाधिकारों का पात्र नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। पीठ ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का 30 अप्रैल 2025 का आदेश को बरकरार रखा और कहा कि यह स्थिति स्पष्ट है। यह फैसला भारतीय सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यह निर्णय मूलतः उस संवैधानिक ढांचे की पुनर्पुष्टि है, जो अनुसूचित जातियों को ऐतिहासिक-सामाजिक भेदभाव के आधार पर संरक्षण देता है। अदालत का तर्क यह है कि जाति-आधारित उत्पीड़न मुख्यतः उन धर्मों की सामाजिक संरचना से जुड़ा है, जहां जाति व्यवस्था मौजूद है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म को अपनाता है, जहां सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती तो उसे अनुसूचित जाति के विशेष अधिकारों जैसे आरक्षण व कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस फैसले का पहला बड़ा प्रभाव आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है लेकिन अभी तक एससी प्रमाणपत्र रखते हैं, अब कानूनी रूप से उन लाभों के पात्र नहीं रहेंगे। इससे शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि कई मामलों में धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति प्रमाणपत्र रद्द नहीं किए जाते। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपयोग पर पड़ेगा। इससे ऐसे मामलों में कमी आ सकती है, जहां आरोप लगाया जाता रहा है कि कानून का दुरुपयोग हुआ। हालांकि इसके साथ ही यह चिंता भी उठेगी कि धर्म परिवर्तन कर चुके दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को अब किस कानूनी ढांचे में संबोधित किया जाएगा। तीसरा पहलू सामाजिक और राजनीतिक बहस का है। लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक भेदभाव समाप्त नहीं होता। ऐसे में यह निर्णय इस बहस को और तेज कर सकता है कि क्या एससी दर्जा केवल धर्म से जुड़ा होना चाहिए या सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर तय होना चाहिए। यह फैसला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सरकार और समाज दोनों के सामने यह चुनौती रखता है कि वे धर्म परिवर्तन कर चुके दलितों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक संतुलित और समावेशी नीति तैयार करें, ताकि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हालांकि यह फैसला भविष्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनेक बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर प्रलोभन देकर अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। इस फैसले से एससी वर्ग के लोग धर्मांतरण करने से बचेंगे।

सीएम का जन्मदिन

हरि अग्रहरि

चरैवेति दर्शन के 'अनन्य साधक'

मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने बारंबार दोहराया कि मध्यप्रदेश को कृषि, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आगे ले जाना प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को राज्य की प्रगति का आधार बताया। इसलिए हम पाते हैं कि किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए कई फैसले लिए गए। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने डॉ. यादव ने रात-दिन एक कर दिए। उन्होंने हर क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर काम करते हुए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट आयोजनों की शुरूआत की।

'चरैवेति' का अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। यह भारतीय संस्कृति का प्रेरक दर्शन है, जो आशावादी दृष्टिकोण के साथ निरंतर सक्रिय रहने और बिना थके-रुके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। 'चरैवेति दर्शन' के अनुसार जीवन में रुकना मृत्यु के समान है और चलना ही जीवन है। 'चरैवेति' दर्शन कर्मयोग से जुड़ा है। डॉ. मोहन यादव 'चरैवेति' दर्शन को ही प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही वे बिना रुके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं जनमानस के समक्ष रेखांकित हुई हैं। आज जब पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव के यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है और वे राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। हर पल विकास योजनाओं की चर्चा करते हैं। विशेषज्ञों से संवाद करते हैं। पिछले दो सालों में ही मध्यप्रदेश ने विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास की ऐसी परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जो कई वर्षों से लंबित थी। यह डॉ. मोहन यादव के अथक परिश्रम का परिणाम हैं। सुबह योग के साथ दिन की शुरूआत और दिन भर बिना रूके जनहित कार्यों के संपादन उनकी सामान्य दिनचर्या है। राष्ट्र प्रथम का ध्येय उनकी कार्यप्रणाली का मूल तत्व है। डॉ. मोहन यादव का राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि संगठन से निकलकर लगातार मेहनत और प्रतिबद्धता के बल पर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा जा सकता है। उज्जैन से छात्र राजनीति और संगठनात्मक कार्य से शुरू हुआ उनका सफर विधायक, मंत्री और फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचा। वे हमेशा आत्मविश्वास से भरे नेता रहे। उनका ध्यान सिर्फ विकास की राजनीति पर रहा है। उनका आत्मविश्वास उनकी शिक्षा-दीक्षा के कारण कई गुना बढ़ जाता है। डॉ. मोहन यादव के व्यक्तित्व में संगठन, शिक्षा, वैचारिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक शैली से बने नेतृत्व जैसे तत्व प्रमुखता से अनुभव किए जा सकते हैं। डॉ. मोहन यादव को भी ऐसे ही नेताओं में गिना जाता है, जिन्होंने संगठन, शिक्षा और प्रशासन क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई। अपनी उत्तम शैक्षणिक पृष्ठभूमि से डॉ. मोहन यादव सार्वजनिक भाषणों और नीतिगत निर्णयों में शिक्षा, संस्कृति, इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों का उल्लेख बार-बार आता है।

डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा को नई आभा प्रदान की। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जनजागरण के उद्देश्य से क्षिप्रा परिक्रमा, श्रीकृष्ण-सुदामा सांदीपनि यात्रा और श्री महाकालेश्वर से श्री बोरेश्वर महादेव (दंगवाड़ा) यात्रा जैसे आयोजनों ने उज्जैन को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में और सुदृढ़ किया। इन सभी पहलों के माध्यम से डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को आस्था, संस्कृति, विज्ञान और राष्ट्रचेतना का समन्वित केंद्र बनाने की दिशा में दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत किया है। डॉ. यादव ने शहरों में गीता भवन बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। बहुत जल्द गीता भवनों में वैचारिक आयोजन, बौद्धिक वर्ग की विचार गोष्ठियां, पुस्तकालयों, वाचनालयों का

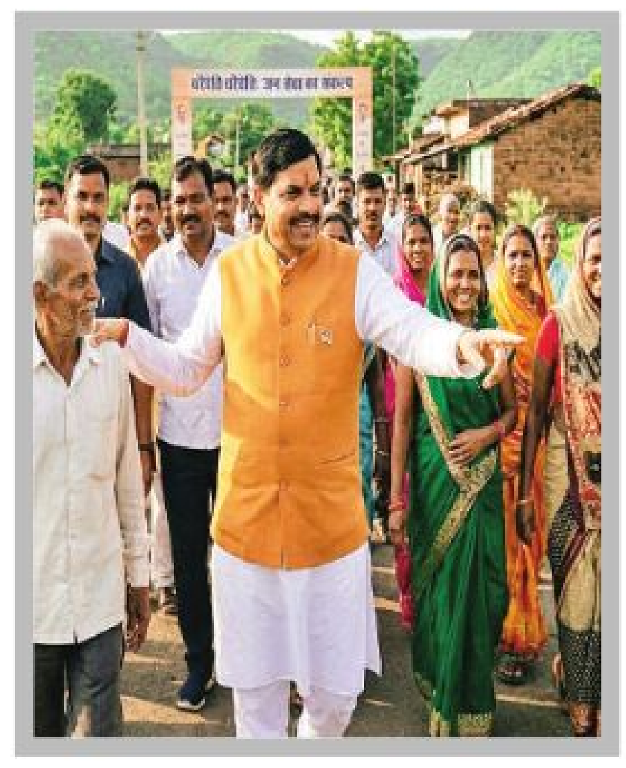

संचालन और आध्यात्मि कार्यक्रमों की शुरूआत होगी। उनकी आध्यात्मिसक पहल का परिणाम है कि समाज और सरकार मिलकर पर्व और त्योहार मना रहे हैं। दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा फिर जीवित हुई। इंदौर, उज्जैन में होली के अवसर पर गेर का आयोजन हो, चाहे अन्य जिलों में रंग पंचमी का अवसर। सभी पर्व सार्वजनिक रूप से उल्लास के साथ बनाए गए। उज्जैन की गौरवशाली सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐतिहासिक पहल प्रारंभ की हैं। उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से भारतीय इतिहास, कालगणना और सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान को संस्थागत स्वरूप मिला। वर्ष 2024 में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना कर भारतीय समय-बोध और वैदिक खगोल परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया गया।

मध्यप्रदेश में एक गहन आध्यात्मितक बोध रखने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भगवान महाकाल के अनन्य भक्त डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया है। आधुनिकता और परंपरा और आध्यात्मिकता को एक साथ लाने की शुरूआत की है। उन्होंने मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास को आर्थिक विकास से जोड़ने की नीति अपनाई। प्रदेश की गोशालाओं को 'गो मंदिर' के रूप में विकसित करने, उनके बेहतर प्रबंधन, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया दिया जा रहा है। गोशालाओं को स्थानीय निकायों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संचालित करने की पहल हो रही है। जैविक खेती और गोबर से बने उत्पादों को भी आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की योजना है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने बारंबार दोहराया कि मध्यप्रदेश को कृषि, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आगे ले जाना प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को राज्य की प्रगति का आधार बताया। इसलिए हम पाते हैं कि किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए कई फैसले लिए गए।

औद्योगिक विकास की गति को तेज करने डॉ. यादव ने रात-दिन एक कर दिए। उन्होने हर क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर काम करते हुए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट आयोजनों की शुरूआत की। उनकी सोच स्पष्ट है कि प्रत्येक रीजन की अपनी विशेषताएं हैं और उसी के अनुरूप निवेश आना चाहिए। इस उददेश्य को लेकन उन्होंने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार निर्माण वर्ष घोषित किया, जिससे पूरे वर्ष संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता मिले। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। यह विकास की नई कार्यशैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (जीवायएएन) के सम्मान का मंत्र दिया है। मध्यप्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में डॉ. मोहन यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया है। गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ की गई यात्रा को उन्होंने अब और अधिक विस्तार दिया है। अब इंडस्ट्रिलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है। ज्ञान (जीवायएएन) से यात्रा का शुभारंभ कर 'ज्ञानी' (जीवायएएन-2) की ओर कारवां बढ़ा दिया है।

(लेखक हरिभूमि समाचार पत्र, भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार हैं)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सीएम का जन्मदिन

आशीष उषा अग्रवाल

मोदी के मन में मोहन 'भाव' नहीं... सजीव 'वास्तविकता'

भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व की वास्तविक कसौटी केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि जनविश्वास को बनाए रखते हुए विकास को धरातल पर उतारना है। वर्ष 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जिस भाव के साथ संवाद स्थापित किया, वह था- मोदी जी के मन में मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश के मन में मोदी। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि विश्वास, जुड़ाव और विकास की सशक्त अभिव्यक्ति थी, जिसने आमजन और नेतृत्व के बीच एक मजबूत एवं सकारात्मक संबंध स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया यह चुनाव जनता की आकांक्षाओं, स्थिर शासन और निरंतर प्रगति के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा। इसी विश्वास की मजबूत नींव पर जब डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनके सामने केवल प्रशासन संचालन की चुनौती नहीं थी, बल्कि इस विजन को प्रभावी रूप से प्रदेश में लागू करने का संकल्प भी था। डॉ. मोहन यादव ने प्रारंभ से ही यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध और परिणामोन्मुख तरीके से लागू करना है। 'विजन' और 'इंटेंशन' के इस संतुलन ने उनके नेतृत्व को एक विशिष्ट पहचान दी है। आज, लगभग सवा दो वर्षों के कार्यकाल और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जब हम इस यात्रा का अवलोकन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि यह सोच केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर साकार हुई है। शासन ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्राम स्तरीय व्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। शासन के प्रति एक नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है, जिसमें गति, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यही कारण है कि सरकार के निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव सीधे जनता के जीवन में दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सशक्त समन्वय इस विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन को त्वरित रूप से क्रियान्वित करना इस नेतृत्व की कार्यक्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री का विकास दृष्टिकोण चार प्रमुख स्तंभों- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति- पर आधारित है। मध्यप्रदेश में इन चारों क्षेत्रों में संतुलित और प्रभावी कार्य हुआ है। 'ज्ञान से आगे, ज्ञानी' की अवधारणा को अपनाते हुए शिक्षा को व्यवहारिक कौशल से जोड़ा जा रहा है, जिससे हर नागरिक सशक्त बन सके। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसरों का विस्तार किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सहभागी बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश ने नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। समर्थन मूल्य में वृद्धि, बोनस तथा आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने जैसे निर्णयों ने किसानों की स्थिति को सुदृढ़ किया है। 'कृषि वर्ष' की अवधारणा इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों को विकास का केंद्र मानती है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' जैसे अभियान सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं। 'लाड़ली बहना' योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर सहयोग दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) जैसे आयोजनों ने प्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इन पहलों के माध्यम से 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर लागू हो चुके हैं। इससे लगभग 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। आईटी, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक अवसर निर्मित हुए हैं। पीएम मित्र पार्क जैसे प्रकल्प विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। पीएम मोदी के मन में मप्र सदैव विशेष स्थान रखता रहा है, किंतु मोहन सरकार के प्रभावी कार्यों ने इस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 'मोदी के मन में मोहन' अब केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक सजीव वास्तविकता बन चुका है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यकुशलता ने मिलकर मध्यप्रदेश के लिए एक ऐसा विकास मॉडल प्रस्तुत किया है, जो विश्वास, पारदर्शिता और परिणामोन्मुख शासन का प्रतीक है।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं)

धन्वंतरि का ध्यान कर स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट रहें

संकलित

दर्शन

धन त्रयोदशी या धनतेरस पर्व की विशेषता यही है कि उस दिन आप यह मानें कि आप जो चाहते हैं, वह धन आपके पास है। केवल सोना-चांदी ही धन नहीं है, ज्ञान भी धन है। यह सबसे बड़ा धन है। आपको अपने ज्ञान को संजोना चाहिए और प्रचुरता का अनुभव करना चाहिए। जीवन में धन्यभागी अनुभव करना, कृतज्ञता का अनुभव करना सबसे बड़ा धन है, जिनमें कृतज्ञता का अभाव होता है, वे धनी नहीं होते हैं। स्वास्थ्य भी धन है। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं, तो भौतिक धन का क्या उपयोग हो सकता है। धन त्रयोदशी देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि की जयंती भी है। कहा जाता है कि वह समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः धन त्रयोदशी पर धन्वंतरि का ध्यान कर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेष्ट रहें। योग व ध्यान करें। आपके पास जो मानव शरीर है, यह भी तो ईश्वर का दिया बड़ा उपहार है। यह भी धन है। हमारी चेतना में ऐसा गुण है कि जो बीज आप बोते हैं, वही प्रकट होता है। यदि आप यह सोचें कि वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त धन है, तब आप धन के पीछे पागल नहीं होते। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन है, चेतना में धैर्य आता है, हिम्मत आती है। कहा गया है, उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः, जिसका अर्थ है, जो मेहनत करता है और शेर जैसा निर्भय होकर चलता है, लक्ष्मी भी उसी के पास आती हैं। धनतेरस के दिन अपनी चेतना से 'अभाव के भाव' को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अपने मन से, 'मैं विपन्न हूं, मैं भिखारी हूं' ये सब बातें हटा दीजिए।

कभी भी अपने पद और धन का घमंड न करें

संकलित

प्रेरणा

देवताओं के कोषाध्यक्ष को एक दिन अपने पद और धन का घमंड हो गया है। इसी घमंड में वे शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी को सपरिवार अपने महल में खाने के लिए निमंत्रण दिया। शिवजी ने कहा कि मैं तो कहीं आता-जाता नहीं हूं, आप एक काम करें, गणेश को अपने साथ ले जाएं। खाने का निमंत्रण पाकर गणेश जी कुबेर के महल पहुंच गए। कुबेर ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनवाया। गणेश जी खाने बैठे तो वे खाए जा रहे थे, थोड़ी ही देर में कुबेर की रसोई का पूरा खाना खत्म हो गया। गणेश जी ने और खाना मांगा। कुबेर ये देखकर घबरा गए। गणेश जी बार-बार खाना मांग रहे थे। कुबेर ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब तो मेरे घर का सारा खाना खत्म हो गया है। गणेश जी ने कहा कि लेकिन मेरी भूख तो अभी शांत ही नहीं हुई है। मुझे अपने रसोईघर में ले चलो। कुबेर गणेश जी को रसोईघर में ले गए तो वहां रखी सभी चीजें गणेश खा गए। उन्होंने शिव जी को पूरी बात बता दी। शिव जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ, माता पार्वती को बुलाकर लाओ। मां पार्वती को देखकर गणेश ने कहा कि मां, कुबेर देव के खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई है। पार्वती अपने रसोईघर में गईं और खाना बनाकर ले आईं। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को अपने हाथ से खाना खिलाया तो गणेश तृप्त हो गए। मां और खिलाने लगी तो गणेश जी ने कहा, मां मेरा पेट भर गया है। ये सब देखकर कुबेर देव का घमंड टूट गया और उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। कुबेर ने सभी से क्षमा मांगी।

शोभायात्रा में उमड़े लोग

शिमला। मंगलवार को शिमला में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान राम नवमी से पहले 'शोभा यात्रा' जुलूस में लोग भाग लेते हुए।

आज की पाती

मोदी ने तोड़ा चामलिंग का रिकॉर्ड

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो इतिहास का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब सामने आया जब नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों को मिलाकर 8931 दिनों तक शासन का नेतृत्व करना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का भी संकेत है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के लंबे समय तक बने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो स्वयं स्थिर शासन और विकास के प्रतीक माने जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यह सफर साधारण परिस्थितियों से शुरू होकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी है।

- विनती, सोनीपत

ट्रेंड

स्थापना दिवस की बधाई

असम राइफल्स के वीर जवानों, उनके परिवारों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वे पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, मानवीय सहायता के माध्यम से समुदायों में विश्वास कायम करते हैं।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

नारी सशक्तिकरण

प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रावधान नारी सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगा और बेटियों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराएगा। विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय समावेशन के ये प्रावधान उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त करेंगे।

-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

रानी हाट

दिल्ली में "रानी हाट" स्थापित किए जाएंगे, जहां हमारी बहनें अपने हुनर, अपने उत्पाद और अपने उद्यम को एक सशक्त पहचान दे सकेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हर बहन को आत्मनिर्भर बनाने, हर हाथ को सशक्त करने और हर परिवार को संबल देने का यह प्रयास है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

हॉकी एशियन चैंपियनशिप

पंजाब में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है। इस उपलब्धि के पीछे पंजाब सरकार और सीएम भगवंत मान की कड़ी मेहनत है और इसी मेहनत के दम पर पंजाब अब हर क्षेत्र में अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

दक्षिण अफ्रीका के एक प्रांत में हिंदू संगठन की सराहना

दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत के प्रमुख के कार्यालय ने देश में सामाजिक सामंजस्य व मानवतावाद को बढ़ावा देने में प्रमुख हिंदू संगठन 'एसए हिंदूज' की भूमिका की सराहना की। जोहानिसबर्ग के लीनासिया में आयोजित संगठन के 10वें वार्षिकोत्सव समारोह के मौके पर उसकी यह सराहना की गई। गौटेंग के प्रमुख पनयाजा लेसुफी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 'एसए हिंदूज' की संस्थापक पंडिता लूसी की भूमिका की भी प्रशंसा की और बताया कि उनकी योजनाएं प्रशासन की योजनाओं से मेल खाती हैं। लेसुफी खुद इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उनाथी एमफेंडु ने कहा, 'हम यह भी देख रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार के मुद्दों का हल कैसे निकाला जा सकता है, और पंडिता लूसी भी इसी तरह काम कर रही हैं। यही कारण है कि हम यहां उन्हें अपना समर्थन देने आए हैं।' उन्होंने 'एसए हिंदूज' की ओर से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उठाए गए कई कदमों का उल्लेख किया, जिनमें खाद्य सामग्री वितरण और सामाजिक एवं कल्याण से जुड़ी सहायता शामिल हैं।

ऑफ बीट

मनुष्य मृत्यु के बाद के जीवन से आकर्षित रहा

जैसे-जैसे हैलोवीन करीब आता है, हम भूतों, राक्षसों और पिशाचों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद के जीवन और दूसरी दुनिया के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है: दुनिया भर की भूत की कहानियां साबित करती हैं कि यह प्रागैतिहासिक काल से मानव अनुभव का हिस्सा रहा है। 5,000 साल पहले लेखन के आविष्कार से पहले भी, मनुष्यों को उन सामानों के साथ दफनाया जाता था जो उनके बाद के जीवन में उपयोगी हो सकते थे, जैसे पीने के बर्तन या हथियार। यद्यपि प्रागैतिहासिक कब्र के सामान के अर्थ के बारे में कुछ बहस है, मेसोपोटामिया के भूत विशेषज्ञ इरविंग फिंकेल दृढ़ता से तर्क देते हैं कि वे एक विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं कि मृत व्यक्ति का कुछ हिस्सा अगले जीवन में बना रहेगा। मेसोपोटामिया, एक ऐतिहासिक क्षेत्र जो मोटे तौर पर आधुनिक इराक के क्षेत्र में स्थित है, दुनिया के कुछ महान साम्राज्यों का घर था। प्राचीन मेसोपोटामिया के भूत और राक्षस शायद आज डरावनी फिल्मों में अपनी उपस्थिति के कारण सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। घोस्टबस्टर्स (में, सिगोरनी वीवर्स के दाना को ज़ूल अपने कब्जे में कर लेता है, जो काल्पनिक देवता गोज़र का एक सेवक है, जिसे फिल्म की पृष्ठभूमि में सुमेरियों द्वारा एक देवता के रूप में पूजा जाता था।

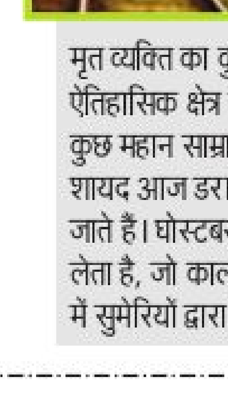

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

पीबी-2, चतुर्थ तल, मानसरोवर कॉम्पलैक्स, वार्ड नं. 50, शिवाजी नगर, निकट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, (म.प्र.) 462016
aapkepatra.haribhoomi@gmail.com
पर भेज सकते हैं।

नगर निगम में जल सुनवाई के हाल बेहाल... कर्मचारी दो घंटे रजिस्टर लेकर अकेले बैठे रहे

शहरभर के 85 वार्डों में न कोई सैंपल लेकर पहुंचा न कोई शिकायत हुई दर्ज

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर के नगरीय निकायों में मंगलवार को दो घंटे होती है सुनवाई

हरिभूमि पड़ताल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

नगर निगम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रति मंगलवार को शुरू की गई जल सुनवाई के प्रति अब लोगों को रुझान खत्म हो रहा है। मंगलवार को शहर के वार्डों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई 85 वार्डों में हुई जल सुनवाई में हालात यह रहे कि कहीं कर्मचारी दो घंटे रजिस्टर लेकर अकेले बैठे रहे तो कहीं केवल टेबल ही लगी मिली और कर्मचारी गायब मिले। पूछने पर बताया कि कई दिनों से कोई भी व्यक्ति सैंपल लेकर नहीं आ रहा है। अगर सैंपल लेकर कोई आएगा तो उसे लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। शहरभर के 85 वार्डों में न तो कोई सैंपल लेकर पहुंचा न ही कोई पानी से संबंधित शिकायत दर्ज हुई।

हरिभूमि की टीम मंगलवार को जोन-16 के तीन वार्डों वार्ड नंबर-72, 73 और 74 में जल सुनवाई में स्थिति देखने पहुंची तो वार्ड-72 में एक कर्मचारी टेबल पर रजिस्टर लेकर बैठे मिले। उनसे पूछा कि कोई व्यक्ति सैंपल लेकर आया तो उनका जवाब था कोई नहीं, जबकि वार्ड नंबर-73 और 74 में भी यही स्थिति रही। वार्ड-74 में तो केवल टेबल ही लगी थी और कर्मचारी नदारद। वार्ड के अन्य कर्मचारियों से जब सैंपल की संख्या पूछी तो बताया कि कोई आया ही नहीं। यह सुनवाई शहर के 85 वार्डों में आयोजित हुई।

नगम निगम आयुक्त संस्कृति जैन का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल सुनवाई सभी वार्डों में हर मंगलवार को आयोजित की जा रही है। इसमें शहर का कोई भी व्यक्ति पानी के सैंपल देकर जांच करवा सकता है। यहां पानी के सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट मिलने की सुविधा है।

वार्ड 72 में खाली बैठे कर्मचारी।

वार्ड 73 में लोगों का इंतजार करते कर्मचारी।

नियमित कार्रवाई के दौरान 183 पानी के सैंपल

निगम के जलकार्य विभाग के अमले ने नियमित कार्यवाई के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 183 पानी के सैंपल एकत्र किए और 41 स्थानों पर लीकेज सुधारे व 5 शिकायतों का निराकरण भी किया। निगम अमला अब तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 14045 पानी के सैंपल एकत्र कर जांच करवा चुका है।

बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा-युवतियां हुईं शामिल

चैत्र नवरात्रि पर निकली विशाल चुनरी यात्रा, भक्तिमय हुआ पूरा माहौल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ संतनगर

भोपाल चैत्र नवरात्रि पर बैरागढ़ में विराट सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और युवतियां शामिल हुईं।

चुनरी यात्रा से पूरे नगर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। संस्थान के अध्यक्ष रामू केवट ने बताया कि चुनरी यात्रा संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण करती हुई सीहोर नाका स्थित माता मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारे लगाए और पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस अवसर पर राम बंसल, प्रदीप मेवाड़ा, बंटी मोरकल, शुभम केवट, संतोष रजक, दीपक मेहरा व किशन अच्छानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

बैरागढ़ में विराट सेवा संस्थान ने विशाल चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।

खबर संक्षेप

प्रमोद कुमार सिंह होंगे अब डीपीआई संचालक

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने लोक शिक्षण संचालनालय की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए डीपीआई संचालक की जिम्मेदारी अब प्रमोद कुमार सिंह को सौंपी है। प्रमोद कुमार सिंह इसके साथ ही पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भी रहेंगे। वहीं डीपीआई संचालक डी.एस कुशवाह को राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। इस सबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

चौदह साल के फरार इनामी वांरटी गिरफ्तार

भोपाल। एमपी नगर पुलिस ने पिछले चौदह साल से फरार चल रहे बीस हजार रुपए के इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार फरार आरोपी राजीव त्रिपाठी (58) निवासी लखनऊ के खिलाफ जिला न्यायालय भोपाल द्वारा 13 स्थाई वारंट जारी किए गए थे।

4 अफसरों को दो-दो महीने का कारावास

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड, एक तत्कालीन और दो मौजूदा अफसरों को दो-दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी मामले में पूर्व में पारित आदेश का पालन न करने पर दिया है। हालांकि, सजा के आदेश को तीन सप्ताह स्थगित रखा जाएगा।

हिंदू उत्सव समिति 63 साल से मना रही दुर्गा उत्सव

औबेदुल्लागंज। हिन्दू उत्सव समिति नगर में 63 साल से दुर्गा और गणेशोत्सव मना रही है। तब से ही नगर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसके बार हर साल ये आयोजन उत्साह के साथ होते हैं और नगर के रहवासी बढ़चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। नगर के वरिष्ठ द्विज चौरासिया ने बताया हिंदू उत्सव समिति 1962-63 में बनी थी। तब स्टेशन रोड पर बैठक हुई थी, जिसमें स्व. डॉ आरएस चौरासिया, दुर्गा प्रसाद मित्तल, डॉ जीडी बंसल, भैया लाल साहू, जेके मित्तल, प्रेम नारायण तिवारी, राधेश्याम गुप्ता मामा, टेऊमल, चिरौंजी हम्माल, पुरुषोतम पहलवान, सुंदर हम्माल, जसवंत यादव, तेज बहादुर जैन, भीमसेन खन्ना आदि ने श्री दुर्गा उत्सव और श्री गणेश उत्सव मनाने के लिए झांकियां लगाई। इसके अलावा जो स्टेशन रोड पर कार्यक्रम होते थे उनमें लोग स्वयं मां की प्रतिमाएं बनाते और झांकियां सजाते थे। उन्होंने बताया कि तब धर्मिक उत्सव आत्मीयता से होते थे।

शुभांक			
कल्याण:	6138		
दिन:	357	59	577
रात:	340	75	447
तारा:			
दिन:	670	30	136
रात:	690	56	466

टीला जमालपुरा क्षेत्र में मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदला

पानी पीने को लेकर विवाद, सिर में चाकू घोंपा, युवक की हालत गंभीर

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

शहर के टीला जमालपुरा इलाके में मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। यहां पानी पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे के सिर में चाकू घोंप दिया।

पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय दानिश बैग कबाड़ का काम करता है। रविवार को वह शाहजहांनाबाद थाने के सामने पानी की टंकी पर पानी पी रहा था। तभी उसका परिचित भट्टू उर्फ उवेश वहां पहुंचा और उसे पानी पीने से मना करने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कहा कि उसे चर्म रोग है, इसलिए वह पानी न पिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर आरोपी ने दानिश के सिर में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है।

फाइल फोटो

दोस्ती बनी दुश्मनी- कैफे संचालक पर दोस्तों का चाकू से हमला, हालत गंभीर

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार

गांधीनगर इलाके में दोस्ती उस वक्त खून-खराबे में बदल गई जब एक कैफे संचालक पर उसके ही दोस्तों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 29 वर्षीय आर्यन ने नया कैफे शुरू किया था। रविवार रात उसके दोस्त तनु और रवि कैफे पर आए थे। खाने-पीने के बाद जब वे जाने लगे तो संचालक ने उनसे उधार के पैसे मांगे। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ देर बाद शांत हो गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद आरोपियों ने अपने साथी को कैफे पर भेजा, जहां उसने आर्यन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अवैध शराब से लदी कार समेत एक आरोपी गिरफ्तार

निशातपुरा पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक कार समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार निशातपुरा की मोबाइल पेट्रोलिंग टीम को इलाका भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद रंग की कार में अवैध शराब लेकर आयशा मस्जिद के पास किसी का इंतजार कर रहा है।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर कार चालक को दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अखिलेश कुमार आर्य निवासी रायसेन को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर कार की डिग्गी में रखी 6 पेटी अवैध शराब रखी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वह उक्त शराब कहां से लेकर आया था और कहां पर सप्लाई करने वाला था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

बड़े तालाब में मिली युवक की लाश

राजधानी के वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में सोमवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पानी में शव उतराता देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने खुद तालाब में छलांग लगाई थी, हालांकि मौत की असली वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहचान के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और वजह है।

शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म

भोपाल। हबीबगंज पुलिस ने एक युवती की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मूलतः खंडवा निवासी 32 वर्षीय युवती एमपी नगर इलाके में रहती है और प्राइवेट काम करती है। खंडवा के ही रहने वाले अमित नामक युवक से उसकी पहचान हुई थी। अमित भी भोपाल में रहकर प्राइवेट काम करता है। दोनों के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई तो अमित ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती शादी के लिए तैयार हो गई तो करीब एक साल पहले वह उसे घुमाने के बहाने हबीबगंज इलाके में लेकर गया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पिछले दिनों युवती को पता चला कि अमित पहले से शादीशुदा है, तो युवती ने शादी के लिए बोला, अमित ने शादी करने से इंकार कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने कैस दर्ज कराया।

25 किलो 900 ग्राम डोडाचूरा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों पर पहले से ही थाने में दर्ज है कई मामले

हरिभूमि न्यूज ▶▶ औबेदुल्लागंज

थाना प्रभारी गौहरगंज उप निरीक्षक विनोद परमार एवं उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए सोमवार को दो आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति तारानगर ओवरब्रिज, गौहरगंज के पास बैग में अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा रखकर बिक्री के लिए खड़े हैं।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से बैग में पन्नी में छिपाकर रखा कुल 25 किलो 900 ग्राम डोडाचुरा जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई गई, बरामद कर जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अजय पिता किशोर सिंह रायसिख (30), निवासी ग्राम रमगड़ा, थाना बाड़ी, जिला रायसेन, ब्रजेश पिता दलवीर सिंह रायसिख (19), निवासी ग्राम रमगड़ा, थाना बाड़ी, जिला रायसेन होना बताया। आरोपी अजय रायसिख के विरुद्ध थाना बाड़ी में मारपीट एवं अड़ीबाजी तथा थाना सुल्तानपुर एवं सतलापुर में बाइक चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी ब्रजेश रायसिख के विरुद्ध वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला थाना बाड़ी में पंजीबद्ध है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी गौहरगंजश उप निरीक्षक विनोद परमार के साथ सहायक उप निरीक्षक रमेश इवने, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र परमार, विनय दुबे, दुर्गेश सिंह राजपूत, आरक्षक दिलीप चौरे, गौरव परमार, नीरज धुर्वे एवं सैनिक ओमप्रकाश का सराहनीय योगदान रहा।

घर की नौकरानी निकली चोर, उड़ाए 2 लाख

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोलार इलाके में एक पेट्रोल पंप संचालिका के घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को अंजाम किसी बाहरी बदमाश ने नहीं, बल्कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही दिया था। पुलिस के मुताबिक, संचालिका ने बैंक बंद होने के कारण करीब 2 लाख 6 हजार रुपए घर की अलमारी में रखे थे। अगले दिन जब उन्होंने पैसे चेक किए तो रकम गायब मिली। घर में न तो ताले टूटे थे और न ही जबरन घुसने के कोई निशान मिले। शक के आधार पर पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वह टूट गई और चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी के कब्जे से पूरी रकम बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस उससे यह भी पूछताछ कर रही है कि उसने पहले भी ऐसी वारदातें की हैं या नहीं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विधायक सुरेंद्र पटवा की माता को दी श्रद्धांजलि

औबेदुल्लागंज। विधायक सुरेंद्र पटवा के भोपाल निवास पर उनकी माताजी स्व. पारस कुंवर बाई पटवा के देवलोकगमन के उपरांत वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं पटवा एवं उनके परिवार जनों से से बातचीत की।

भजनगढ़ गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब 27 मार्च से

औबेदुल्लागंज। संत संतोख सिंह भजनगढ़ गुरुद्वारा में 27 मार्च से 14 अप्रैल वैशाखी तक अखंड पाठ साहिब चलेगा। औबेदुल्लागंज खालसा पंथ के 327 वें वर्ष पर अर्जुन नगर वार्ड 10 के संत संतोख सिंह भजनगढ़ गुरुद्वारा में 27 मार्च शुक्रवार सुबह 10 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब लड़ीवार प्रारंभ होगा, जो की 14 अप्रैल मंगलवार वेशाखी तक लगातार चलेगा। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ती के बाद 11 बजे दीवान सजेगा, फिर कथा कीर्तन के बाद 1:50 बजे से गुरु का अटूट लंगर चलेगा। वैशाखी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा में भोपाल से कुलविंदर सिंह, बुरहानपुर से करण सिंह रागी जत्था मंडलों के द्वारा संगीतमय भजन कीर्तनों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं प्रसिद्ध कथाकार जगजीत सिंह (जीते भैया) के द्वारा बैसाखी पर्व की कथा का प्रवचन दिया जाएगा। नगर के सिख समाज ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन किया है कि कार्यक्रम में पधारकर धर्म लाभ लें।

शहीद दिवस पर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का आयोजन

गीत-संगीत की सुरमयी धारा ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आयोजित रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत-संगीत की सुरमयी धारा ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉ. विजय कुमार अग्रवाल रहे, जबकि अध्यक्षता मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉ. नवीन आनंद जोशी ने की।

विशेष अतिथियों में असिस्टेंट कमांडेंट जीपी सिंह, गैलेंट्री अवॉर्ड विजेता धीरेंद्र सिंह एवं नरेंद्र कुमार, डॉ. रत्नेश जैन (डीन, स्टूडेंट वेलफेयर), डॉ. सुनील पाटिल (परीक्षा नियंत्रक), डॉ. गगन शर्मा एवं डॉ. बलजीत शर्मा की उपस्थिति रही। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. नवीन आनंद जोशी ने कहा कि आजादी का मूल्य उन वीर सपूतों के त्याग और बलिदान से निर्धारित होता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रेस क्लब पत्रकारिता के विकास के साथ-साथ सामाजिक सरोकार और राष्ट्रप्रेम से जुड़े ऐसे आयोजनों को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। मुख्य अतिथि डॉ. विजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा उसके महान सपूतों के कारण है। इस अवसर पर शहीद परिवारों के सदस्यों का सम्मान किया गया तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

तामोट में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेच रहे प्लॉट

तामोट। राजस्व और पंचायत की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके 5-5 लाख रुपए में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। वहीं आश्चर्य है कि सरकारी जमीन पर बोर करा कर पानी भी बेचा जा रहा है। वर्तमान समय में तामोट में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो तामोट में हो रहे अतिक्रमण रुकवा सके।

तामोट का तालाब हो या मेंन रोड, चारों तरफ अतिक्रमण का कारोबार चल रहा है। तामोट में सभी प्रभावशाली लोग अतिक्रमण होते देख रहे हैं, मगर कोई अतिक्रमण रुकवाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, जिससे तामोट अतिक्रमण का गांव माना जा रहा है। वहीं स्थानीय तालाब के किनारे भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026

कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और भविष्य की रणनीति के बारे में दी जानकारी

प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने कहा- संगठन की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ताओं में निहित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ औबेदुल्लागंज

भाजपा द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत औबेदुल्लागंज मंडल में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

प्रथम सत्र का उद्घाटन जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, महामंत्री डॉ. दीपेश पाल, मंडल अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र नागर, महामंत्री माधव यादव, गजेंद्र नागर और नप अध्यक्ष लक्ष्मी चौकसे ने किया। दूसरे सत्र का उद्घाटन जिला भाजपा उपाध्यक्ष ओपी मीणा, वरिष्ठ नेता अरविंद जैन, डॉ. कैलाश विनय, जीवन सिंह पाल, कन्हैया नंदवंशी, रामेश्वर नागर, डॉ. भुपेंद्र नागर, नप अध्यक्ष लक्ष्मी चौकसे ने किया। तीसरे सत्र के उद्घाटन में कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से में भाग लिया। इस शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और भविष्य की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को सक्रियता, अनुशासन और जनसेवा के मूल मंत्रों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ताओं में होती है और उनकी मेहनत से ही पार्टी का विस्तार संभव है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति समझाई गई। वक्ताओं ने कहा कि हर कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और जनसेवा के माध्यम से ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। शिविर में भाजपा के इतिहास, विकास यात्रा और संगठनात्मक ढांचे पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सभी ने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए आने वाले समय में और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।

कलेक्टोरेट में जनसुनवाई, मिलीं 150 शिकायतें

अधिकारियों ने सुनी समस्याएं मौके पर किया निराकरण

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, एडीएम सुमित पांडेय, अंकुर मेश्राम ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए लोगों से 150 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, एडीएम पांडेय, मेश्राम ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए।

संपादकीय जागरण

बुधवार, 25 मार्च, 2026 : चैत्र शुक्ल – 7 वि. 2083

कला जीवन का सौंदर्य बढ़ाती है

सराहनीय निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह एससी का दर्जा खो देता है और साथ ही एससी-एसटी एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है, जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में एससी समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं, जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाइयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ-लालच और छल-छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन वंचित लोगों का छल-छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आम तौर एससी और एसटी समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि लालच और छल-कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है।

एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहां जाति जैसी कोई मान्यता नहीं और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं-कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं, जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें एससी का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं? जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिये सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्रविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और एससी-एसटी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे, जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है, उसे ही आरक्षण का लाभ मिले।

गंभीर प्रयास जरूरी

दिल्ली की भाजपा सरकार के दूसरे बजट में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाना स्वागतयोग्य है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय और बजटीय प्रविधान किए गए हैं। ग्रीन बजट का 21 प्रतिशत प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर खर्च किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, हरित क्षेत्र का विस्तार, धूल प्रदूषण पर नियंत्रण, कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने जैसे कई उपाय किए गए हैं। बजट में दिल्ली में कई सड़कों के निर्माण और मरम्मत के जरिये धूल प्रदूषण पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। दिल्ली के औद्योगिक विकास को हरित विकास के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और ड्रोन पालिसी बनाने का भी प्रस्ताव है, जो राजधानी में नए हरित रोजगार सृजित करेगा।

> दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट में जो उपाय किए गए हैं, उन पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए

दिल्ली में वायु प्रदूषण वर्ष भर एक गंभीर समस्या बना रहता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही यहां की अर्थ व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली की छवि धूमिल होती है। दिल्ली के बजटीय प्रस्ताव एक उम्मीद दर्शाते हैं, लेकिन ये वास्तव में तभी लाभदायक होंगे, जबकि इनपर गंभीरता से अमल किया जाए और सुनियोजित तरीके से धरातल पर उतारा जाए। बजट में प्रदूषण पर नियंत्रण के जो भी उपाय हैं, उनपर समयबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरानी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाने के फैसले से पश्चिम एशिया में तनाव कुछ घटेगा?

हां	58
नहीं	37
कह नहीं सकते	5

आज का सवाल

क्या विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ आम महिलाओं को भी मिलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मजहबी खेमों की भी मोर्चेबंदी

राज मुनीब

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध शिया-सुन्नी मजहबी पहचान का संघर्ष भी बन रहा है

पश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध केवल ईरान बनाम इजरायल या तेहरान बनाम वाशिंगटन संघर्ष के रूप में ही सिमटकर नहीं रह गया है। यह टकराव अब और खतरनाक स्वरूप लेकर बहुस्तरीय बनता जा रहा है। इसमें भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ ही वर्गीय पहचान, वैचारिक वैधता और रणनीतिक अवसरवाद जैसे पहलू भी जुड़ते जा रहे हैं। संघर्ष का दायरा भी गाजा की सड़कों से लेकर पाकिस्तान के जनजातीय इलाकों तक फैल गया है। इसमें शिया-सुन्नी टकराव की लकीरें भी चौड़ी हो रही हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने अपने वैचारिक प्रभाव को अपनी सीमाओं से परे बढ़ाने के भरसक प्रयास किए। चूंकि इस इलाके की आबादी मुख्य रूप से सुन्नी बहुतायत वाली है, इसलिए शिया बहुल ईरान को वैचारिक मोर्चे पर वैधता के लिए संघर्ष ही करना पड़ा। अपने वैचारिक प्रभाव की राह में आ रहे अवरोधों की काट के लिए उसने स्वयं को फलस्तीन संघर्ष जैसी उन मांगों के साथ जोड़ लिया, जिसमें वैचारिक दरारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचे। इसके लिए उसने कुछ संगठनों को पोषित करने से भी परहेज नहीं किया। इससे जहां ईरान के नेतृत्व में शिया संगठनों का नेटवर्क उभरा तो दूसरी ओर सुन्नी प्रभाव वाले सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के राजशाही वाले देश थे। अमेरिकी सुरक्षा ढांचे पर निर्भर इन देशों की समय के साथ इजरायल के साथ नजदीकियां भी बढ़ती गईं। दोनों खेमों के बीच यह विभाजन केवल मजहबी नहीं, बल्कि भूराजनीतिक भी है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष की परतें मजहबी मान्यताओं से अधिक राजनीतिक हितों और शक्ति-संतुलन से जुड़ी हैं। सुन्नी देश ईरान को एक विस्तारवादी वैचारिक खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह अपने प्रभाव के विस्तार के लिए प्रयासरत है और विभिन्न संगठनों के जरिये अपनी पकड़ मजबूत करता है। वहीं, ईरान सुन्नी देशों को पश्चिमी शक्तियों के ऐसे प्रतिनिधि के रूप में देखता है, जो उसके प्रभाव को सीमित करने का काम करते हैं। यही इस संघर्ष का केंद्रीय विरोधाभास है, जहां एक शिया खेमा सुन्नी असंतोष से ताकत हासिल करता है, वहीं सुन्नी शासन तंत्र उसी पश्चिम-समर्थित व्यवस्था के साथ खड़ा है, जिसका अक्सर उसके अपने लोग ही विरोध करते हैं।

ईरान के विरुद्ध अमेरिका-इजरायल की कोई जमीनी या व्यापक सैन्य कार्रवाई 2003 के इराक युद्ध की तुलना में कई गुना जटिल होगी। उन्हें भौगोलिक, सैन्य और वैचारिक तीनों ही स्तरों पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

अवधेश राजपूत

ईरान, इराक जैसा नही हैं। यह आकार में कहीं बड़ा, सामाजिक रूप से अधिक सुसंगठित और मूलतः एकजुट राष्ट्र है। यहां स्थानीय मिलीशिया भी मजबूत हैं, जो एक साथ कई मोर्चे खोलने की क्षमता रखते हैं। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटी हुई है। सुन्नी विद्रोहियों का गढ़ होने के नाते यह चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र रहा है। आइएसआइएस-खुरासान और जैश अल-अदल जैसे संगठन इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये कट्टर शिया विरोध की जमीन पर ही पनपे हैं और ईरान का प्रतिरोध करते हैं। ये समूह एक वैकल्पिक दबाव तंत्र बना सकते हैं। यानी ईरान के पश्चिमी मोर्चों पर मजबूत किलेबंदी से टकराने के बजाय उसकी पूर्वी सीमा पर अस्थिरता पैदा की जा सकती है। इससे ईरान के सुरक्षा ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। उसे पूर्वी सीमा पर अपने सैन्य संसाधन झोंकने पड़ेंगे, जिससे दूसरे मोर्चों पर उसकी कमजोरियां बढ़ेंगी। अमेरिका सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान ऐसे पैंतरे आजमा कर सैन्य हस्तक्षेप के बिना ही रणनीतिक लाभ हासिल कर चुका है। हालांकि आज हालात उतने अनुकूल नहीं। उस दौर के उलट आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों में एका का अभाव है। उन पर नियंत्रण भी मुश्किल है। एक बार सक्रिय करने के बाद उन्हें निष्क्रिय करना भी मुश्किल है। कई बार तो ये भस्मासुर साबित होते हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष ने पहले से जटिल इस स्थिति को और भी उलझा दिया है। पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति अपनी भूराजनीतिक प्रासंगिकता को वापस पाने की भी है। अतीत पर दृष्टि डालें तो पाकिस्तान ऐसे मौकों को भुनाने में पारंगत रहा है। सोवियत-अफगान युद्ध में अपने सहयोग के बदले उसने वाशिंगटन से तमाम सामरिक एवं आर्थिक लाभ हासिल किए। पाकिस्तान को ईरान संकट में भी ऐसा ही मौका नजर आ रहा है, पर इस बार शायद उसके भाग्य से छींका न टूटे। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन अब पाकिस्तानी रहमोकरम पर नहीं। वह अपनी स्वायत्तता पर अड़ा है। पाकिस्तानी दबाव का प्रतिरोध करने के साथ ही वह अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर रहा है। इससे तनाव निरंतर बढ़ रहा है। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में तमाम तरह के आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनकी निष्ठाएं समय के साथ बदलती रहती हैं और इनका एजेंडा भी अक्सर व्यापक क्षेत्रीय संघर्षों के साथ जुड़ जाता है। यदि ये समूह बाहरी शक्तियों के पिट्ठुओं या अपने स्वयं के मजहबी एजेंडे के तहत ईरान संघर्ष में उतरते हैं तो फिर पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ती जाएंगी। ऐसी स्थिति में आकार लेने वाला परिदृश्य ऐसी रणभूमि के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, जहां हर एक मोर्चा दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इसमें वही भौगोलिक एवं मजहबी दरारें उभरेंगी, जहां ईरानी प्रभाव, सुन्नी असंतोष, अमेरिकी रणनीतिक हित और ऐतिहासिक कड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं। यह टकराव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी आंच सिलसिलेवार ढंग से सीरिया और खाड़ी के साथ ही पूरब में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैलती जाएंगी। पश्चिम एशिया में अब यही खतरा उभर रहा है, क्योंकि यह दो राज्य शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि पहचान का ऐसा संघर्ष बनता जा रहा है, जिसके प्रतीकों के सिरे कर्बला से लेकर दमिश्क तक और गाजा से लेकर पाकिस्तान की जनजातीय सीमाओं तक जुड़ते हैं। इसमें 21वीं सदी के भू-राजनीतिक मानचित्र को पुनः परिभाषित करने की क्षमता है।

(लेखक सामरिक एवं इस्लामिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

धुरंधर पर फालतू का रोना-धोना

राजीव सचान

> जैसे धुरंधर-1 को देखकर कई लोगों को मिर्ची लगी थी, वैसे ही धुरंधर-2 को लेकर भी कुछ लोगों को अपच हो गई है

ऐसी फिल्मों की गिनती करना कठिन है, जिन पर किसी को आपत्ति न हुई हो। हाल में ऐसी कई फिल्में आ चुकी हैं, जिनका विरोध हुआ अथवा जिन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की गई, जैसे द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं, जिनका विरोध करने के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया या फिर निर्माता-निर्देशकों को धमकाया। याद करें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का कुछ समूहों ने कैसा हिंसक विरोध किया था? इस विरोध का आधार यह था कि फिल्म में रानी पद्मिनी और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिल्म प्रतिबंधित करने की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद वह रिलीज तो हुई, पर कई लोगों का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ, जब तक यह सामने नहीं आया कि वे फिल्म में जिस कथित विकृत चित्रण की आशंका से दुबले हुए जा रहे थे, वह निर्मूल थी।

कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं, जिन्हें इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनमें सच दिखाया गया था। द कश्मीर फाइल्स के अलावा मणिरत्नम की रोजा ऐसी ही फिल्म थी। रोजा का विरोध इस बेवकूफी भरे कुतर्क के सहारे हुआ कि फिल्म में कश्मीरी आतंकियों का पक्ष नहीं दिखाया गया और उनका नकारात्मक चित्रण किया गया है। जाहिर है कुछ लोग यह चाह रहे थे कि आतंकियों को भले मानुष की तरह पेश किया जाता। इसे बेवकूफी के अलावा और क्या कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का सामना कई फिल्मकारों को करना पड़ा। कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं, जो सचमुच बेवकूफी भरी थीं या उनमें कुछ ऐसे सीन थे, जिन्हें कोई बेवकूफ ही पचा सकता था, जैसे कबीर खान की फिल्म 83 में एक विचित्र सीन यह था कि पाकिस्तानी सैनिक इस कारण गोलीबारी रोक देते हैं, ताकि मोर्चे पर डटे भारतीय सैनिक विश्वकप फाइनल मैच की कमेंट्री चैन से सुन सकें। यह नितांत काल्पनिक और सच से कोसों दूर सीन था। इसका मकसद केवल पाकिस्तानी सैनिकों को भला आदमी दिखाना था, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या थी? यह सही है कि फिल्मकार किसी सच्ची घटना पर आधारित या उससे प्रेरित फिल्म में रचनात्मक स्वतंत्रता लेते ही हैं, पर इस बहाने कुछ फिल्मकार बेवकूफी की हद भी पार कर जाते हैं। कई बार ऐसी बेवकूफियां दर्शकों को पसंद भी आ जाती हैं, जैसे फिल्म पठान में यह दिखाया गया कि निर्वासित रा एजेंट शाहरुख खान एक पूर्व रा एजेंट जान अब्राहम के शैतानी इरादों पर आइएसआइ एजेंट दीपिका पादुकोण के सहयोग से पानी फेर देता है। दर्शक इस अजीब कथानक को पचा गए और फिल्म हिट हो गई। रचनात्मक स्वतंत्रता के बहाने फिल्मकार तथ्यों में फेरबदल तो करते ही हैं, कई बार शरारत भी कर देते हैं, जैसे इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ पर बनी फिल्म फायर के महिला पात्रों के नाम राधा और सीता रखना, जबकि मूल कहानी में वे बेगम जान और रब्बो थीं। कृपया नोट करें यह फिल्म महिलाओं के समलैंगिक संबंधों पर थी। यदि निर्देशक दीपा मेहता महिला पात्रों के नाम मूल कहानी के हिसाब से नहीं रख सकती थीं तो फिर उन्हें सीता और राधा नाम ही क्यों सूझे?

फिल्म धुरंधर-2 पर भी निराधार आपत्तियां ● फाइल

इस वर्ष की सबसे कामयाब फिल्म धुरंधर तबसे चर्चा में है, जबसे उसका पहला हिस्सा आया। उसे लेकर यह अफवाह फैलाई गई कि यह एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी फिल्म है, पर इस फिल्म को तमाम पाकिस्तानियों ने भी पसंद कर इस दुष्प्रचार की पोल खोल दी। इस फिल्म के विरोध का मूल कारण यह है कि आदित्य धर ने आतंकी घटनाओं के सहारे पाकिस्तान के उस आतंकी तंत्र की पोल खोल दी, जो भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यदि एक क्षण के लिए इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान मान लें तो भी आखिर भारतीयों को इससे क्यों कष्ट होने लगा? जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान से हमदर्दी क्यों?

जैसे धुरंधर-1 को देखकर कई लोगों को मिर्ची लगी थी, वैसे ही धुरंधर-2 को लेकर भी कुछ लोगों को अपच हो गई है। अपच का एक कारण यह है कि फिल्म में माफिया अतीक अहमद (फिल्मी नाम आतिफ अहमद) को आइएसआइ एजेंट दिखाया गया है। बस इसी कारण फिल्म का विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों में सपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। यदि यह मान लें कि आदित्य धर ने अतीक को आइएसआइ का एजेंट दिखाकर उसका अतिरंजित चित्रण कर दिया तो यह रचनात्मक स्वतंत्रता के दायरे में क्यों नहीं आता? क्या ऐसे चित्रण से अतीक भला आदमी सिद्ध हो जाता है? अतीक परले दर्जे का दुष्ट और निर्दयी अपराधी था। वह आतंकी भले न हो, पर उसकी हरकतें लोगों को आतंकित करने वाली ही थीं। उसका इतना आतंक था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक के बाद एक 10 (जी हां 10) जज उसकी जमानत याचिका सुनने से पीछे हट गए थे। एक बार उसने जेल में बंद रहते एक कारोबारी को अगवा कराकर अपने सामने पेश कराया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। उसने न जाने कितने लोगों को निर्दयता से मारा और मरवाया। इनमें मुस्लिम भी थे, फिर भी कुछ लोग उसे लेकर इसलिए रो रहे हैं ताकि उसके बहाने खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित कर सकें। यह मूर्खता की पराकाष्ठा तो है ही, यह बेजा माहौल बनाना भी है कि मुसलमान अतीक जैसे बदमाश को अच्छा मानते हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संकट का सत्य

मनुष्य का जीवन अनुभूतियों की एक गहन सरिता है, जिसमें सुख और संकट दोनों प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाह में संकट बहुत बड़ा शिक्षक है। यह सत्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहन भी है कि मनुष्य विपत्तियों में ही अपनी वास्तविक चेतना से साक्षात्कार करता है। जबकि सुख के क्षण उसे मधुर स्मृतियों में बांध देते हैं। सुख की अवस्था मनुष्य को आत्मतुष्टि के ऐसे मृदुल आवरण में ढक देती है, जहां वह अपने अतीत के संघर्षों और उनसे प्राप्त शिक्षाओं को विस्मृत करने लगता है। वह मान बैठता है कि जीवन अब उसकी इच्छानुसार संचालित होगा। तब वह अपनी सीमाओं-त्रुटियों को देख ही नहीं पाता। वह अपने ही अनुभवों के सार को खो बैठता है।

संकट का आगमन मानो चेतना का तीव्र उद्घोष है। यह मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है और उसे आत्ममंथन के लिए बाध्य करता है। संकट में मनुष्य अतीत के प्रत्येक निर्णय, भूल और अनुभव का सूक्ष्म परीक्षण करता है। यही वह समय होता है जब वह अपने भीतर छिपी सामर्थ्य, धैर्य और साहस को पहचान पाता है। संकट उसे यह बोध कराता है कि वास्तविक शक्ति बाह्य परिस्थितियों में नहीं, अपितु उसके अंतर्मन में निहित है। हमारे दैनिक जीवन में भी यह सत्य प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। असफलता का एक क्षण वर्षों की लापरवाही को उजागर कर देता है और व्यक्ति को आत्मसंशोधन के मार्ग पर अग्रसर करता है। वहीं, निरंतर सफलता उसे अक्सर निष्क्रिय और असावधान बना देती है।

वस्तुतः, संकट मनुष्य को सजग, अनुशासित और आत्मविश्लेषी बनाता है, जबकि सुख उसे क्षणिक आनंद तो देता है, परंतु स्थायी बोध नहीं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम संकटों से भयभीत न होकर उन्हें आत्मविकास के साधन के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि अंततः जो क्षण, सर्वाधिक अधिक पीड़ा देते हैं, वही हमें सबसे अधिक परिपक्व और समर्थ भी बनाते हैं।

कुमार नृपेंद्र

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

संवाद से निकले समाधान

'युद्ध की तपिश से बचने की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में जयंतीलाल भंडारी ने युद्ध से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया है। दुनिया के लिए यह चिंता का विषय है कि युद्ध जारी रहने से न सिर्फ ईरान के अलावा अमेरिका-इजरायल प्रभावित होंगे, बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित होगा। युद्ध जारी रहने की दशा में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका हैं। चिंता की एक बात संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी है, जो मात्र मूकदर्शक बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई उम्मीद नहीं कि कोई पहल करे और युद्ध रुक जाए। अब तो लगता है कि अमेरिका को ही समझदारी दिखानी चाहिए। युद्ध रुकता है तो पूरे विश्व को फायदा ही होगा। अतः सभी देश मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाए और ईरान को भी समझाएं कि वह भी अपने कदम पीछे खींच ले। स्मरण रहे कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं करती। स्थायी समाधान संवाद से ही संभव है।

सर्वजीत आर्या प्रधानाचार्य कन्नौज

नारी शक्ति का नया अध्याय

भारत का लोकतंत्र एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां महिलाओं की भागीदारी को लेकर ऐतिहासिक परिवर्तन की तैयारी हो रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग अब एक ठोस रूप लेती दिखाई दे रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का विचार अब केवल एक कानून तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बड़े संवैधानिक बदलावों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि कर महिलाओं के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। यह परिवर्तन केवल संख्या का विस्तार नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के चरित्र में गहराई से बदलाव लाने वाला कदम साबित हो सकता है। जब संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता और संतुलन दोनों आएंगे। महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी से शिक्षा स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा और समानता जैसे विषय अधिक गंभीरता से उठेंगे। महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में अब तक सबसे बड़ी बाधा परिसीमन से जुड़ी शर्त रही है। परिसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार इस शर्त को अलग कर आरक्षण को पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह कदम इस बात का संकेत है कि नीति निर्माण में तेजी और इच्छाशक्ति दोनों मौजूद हैं। यह योजना सफल होती है तो वर्ष 2027 से ही महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा। लोकसभा की सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इस संख्या को बढ़ाकर 816 तक करने का विचार है। इससे न केवल महिलाओं को आरक्षण देना आसान होगा बल्कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी अधिक संतुलित होगा। बढ़ी हुई सीटों का मतलब यह भी है कि अधिक क्षेत्रीय आवाजें संसद तक पहुंच सकेंगी और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

आपदा प्रबंधन में सहयोग दें

पश्चिम एशिया के युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने भले ही पांच दिनों तक ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमला न करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन ईरान तो बड़ी शिद्दत से इजरायल पर हमले कर रहा है। काफी अनिश्चितता की स्थिति है। पूरे विश्व में त्राहि-त्राहि मच गई है। भारत ने अपनी दूरदर्शिता के कारण स्थिति पर काफी नियंत्रण रखा हुआ है। उसके तेल एवं गैस से लदे जहाजों को ईरान सुरक्षित रास्ता दे रहा है। पेट्रोल और घरेलू गैस के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है पर निकट भविष्य में ही इनके मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभी से ही कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए। सप्ताह में कार्य के दिन घटाकर तीन-चार दिन किए जा सकते हैं, वर्क फ्राम होम प्रारंभ किया जा सकता है। सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। एक कार्यालय के लिए अनेक कर्मी किसी एक कर्मी की गाड़ी से आ-जा सकते हैं। पीएनजी का उपयोग अधिक करना होगा। इन उपायों से पेट्रोल और डीजल की बचत की जा सकती है। गर्मी प्रारंभ हो रही है। बिजली की मांग बढ़ेगी। एसी, कूलर चलेंगे। गैस न मिलने की स्थिति में या उसकी खपत कम करने के लिए इंडक्शन और ओवन का प्रयोग बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बिजली चाहिए। कहने का मतलब है कि बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ सकती है। ऐसे कई उपाय हैं, जिनके सहारे हम आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पोस्ट

वर्तमान विपक्ष इसी भरोसे दिखता है कि एक्स पर पोस्ट के अलावा कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो ही उन्हें सत्ता में ले आएंगे। उमाशंकर सिंह@umashankarsingh

अगर महिला आरक्षण विधेयक वास्तविक रूप ले पाता है तो यह मोदी सरकार का एक बेहतरीन राजनीतिक दांव होगा। स्वाति चतुर्वेदी@bainjal

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलेगा। इस्लाम या ईसाई बनने के साथ ही यह दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

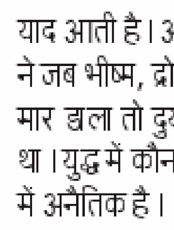

ट्रंप जब कहते हैं कि ईरान को ऊर्जा क्षेत्रों पर हमला नहीं करना चाहिए या होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता या विश्व आर्थिकी के विरुद्ध है, तो दुर्योधन की याद आती है। अभिमन्यु की घेरकर हत्या के बाद पांडवों ने जब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को छल का प्रयोग कर मार डाला तो दुर्योधन ऐसे ही नैतिकता की दुहाई दे रहा था। युद्ध में कौनसी नैतिकता होती है? युद्ध तो अपने आप में अनैतिक है। सुशांत झा@jhasushant

जनपथ

सिंपैथी ईरान से रखता है कश्मीर,
काश वहाँ भी आज तो होता कोई मुनीर।
होता कोई मुनीर बरतता जरा कड़ाई,
कहता जा ईरान वहीं अब लड़ो लड़ाई।
'वे' कुत्ते की पूँछ सदा रहती जो ऐंठी,
यहां खाय ईरान संग रक्खें सिंपैथी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : **0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90** समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 249

www.jagran.com दैनिक जागरण

जोश
आगे बढ़ने का

बुधवार, 25 मार्च, 2026

जेईई एडवांस्ड-2026

देश के आइआइटीज के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा आगामी 17 मई को प्रस्तावित है। इस परीक्षा के लिए अभी करीब डेढ़ महीने का समय बचा है। ऐसे में इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे कम समय में स्मार्ट तैयारी करके टाप 100 रैंकिंग में अपनी जगह बनाएं, इस बारे में जानें विषय विशेषज्ञ अजीत सिंह से...

अपनी तैयारी को ऐसे बनाएं धारदार

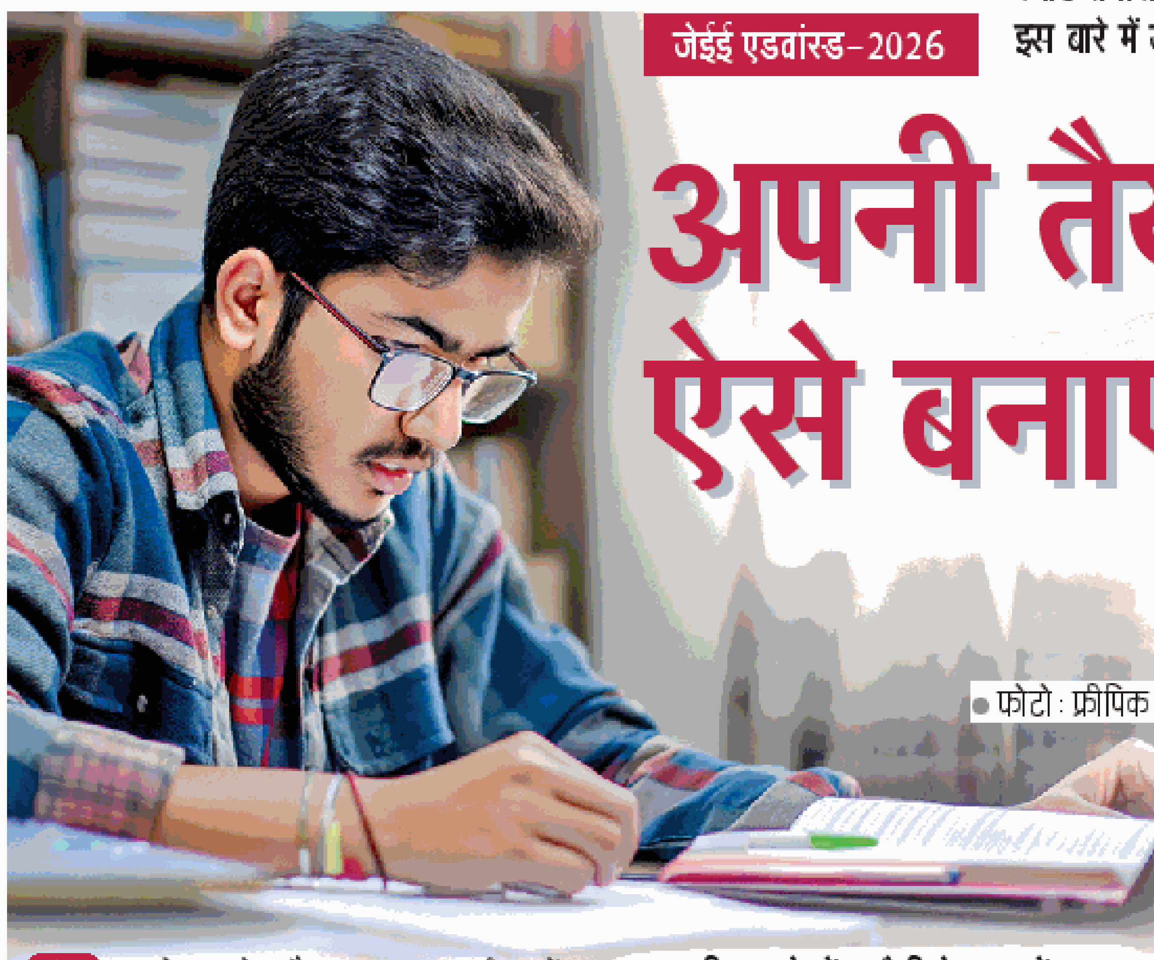

● फोटो : फ्रीपिक

देश के पुराने और नए आइआइटीज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई एडवांस्ड) एक ऐसी परीक्षा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में छात्र डेढ़ से दो साल की लगन के साथ कड़ी तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें इन प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश मिल सके। यदि आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी रैंक लाने के लिए अभी निम्न बातों को जरूर फालो करें, जैसे कि:

न करें नए सिरे से तैयारी: जेईई एडवांस्ड के लिए अब करीब डेढ़ महीने का समय बचा है। ऐसे में अभी सभी छात्रों की मुख्य रणनीति यह होनी चाहिए कि आखिरी के इस बचे हुए समय में नए सिरे से कोई तैयारी न करें। इस दौरान जिन चैप्टर्स को आपने तैयार कर लिया है, उसे ही और अच्छा करने की कोशिश करें। जो टापिक आपके कमजोर रह गए हैं, उसे ठीक करने की अभी बिल्कुल कोशिश न करें, क्योंकि जेईई एडवांस्ड का लेवल बोर्ड या जेईई मेन से ऊपर का होता है। ऐसे में अभी कोई नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि एक महीने बाद उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर इस बचे हुए समय में जो पहले से सीखा हुआ है, उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो शायद परीक्षा में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए ऐसे सभी छात्रों के लिए मूलमंत्र यही है कि अभी उन्हीं एरिया पर फोकस करें, जिसे पिछले एक-डेढ़ साल में आपने तैयार किया है।

प्रमुख चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस: यदि आपने पिछले 10 वर्षों के जेईई एडवांस्ड के पेपर्स को बारीकी से देखा होगा तो यह अंदाजा आपको हो चुका होगा कि किन-किन चैप्टर्स से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय क्या करना है। यदि आप केवल अपना रैंक सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं या इस परीक्षा में और बेहतर करना चाहते हैं तो इस समय पेपर की प्रैक्टिस और गहन रिवीजन करने के अलावा अगले 40 दिनों का एक शेड्यूल बना लीजिए। अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो तीनों विषयों में औसतन 20 से 25 मुख्य चैप्टर हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है।। हर विषय के एक-एक चैप्टर को एक दिन के अंतराल पर उठाएं और उसे अच्छी तरह तैयार करें। मैथ में कई ऐसे चैप्टर्स हैं, जिसका महत्व ज्यादा है, जैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस एरिया अंडर कर्व, एप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, काम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर प्लस थ्रीडी, मैट्रिक्स तथा सर्कल प्लस कोनिक सेक्शन। इन चैप्टर्स की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन इन पर ज्यादा समय तभी दें, यदि आपने इन्हें पहले से तैयार कर रखा है।

परीक्षा को लें चुनौती के रूप में

आपको अभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस समय आपका कोई टापिक छूट भी रहा है, तब भी ज्यादा तनाव न लें। यह भी ध्यान रखें कि इस परीक्षा में बोर्ड एग्जाम की तरह 95 प्रतिशत अंक किसी के नहीं आते हैं। इसलिए प्रैक्टिस के दौरान अगर इतने प्रतिशत अंक नहीं आ रहे हैं तो हैरान-परेशान न हों। आज तक के इतिहास में आइआइटी की इस परीक्षा में फुल मार्क्स किसी को नहीं मिले हैं। इसलिए सुझाव यही है कि अभी वर्तमान में जो स्कोर आपका आ रहा है, बस उसे ही और सुधारने की कोशिश करें। इस समय खुद पर भरोसा रखें। शांत बने रहें। कहा जाता है कि जो लोग कूल रहते हैं, वे औसतन अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

परीक्षा में तनाव होना लाजिमी है, यह होता है। आप इस परीक्षा को चैलेंज के रूप में लें। प्रेशर और चैलेंज में अंतर होता है। अगर इस परीक्षा को चैलेंज के रूप में लेंगे तो इसे एंज्वाय करेंगे। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए अभी पूरे सकारात्मक सोच के साथ इस बचे हुए समय का सदुपयोग करें।

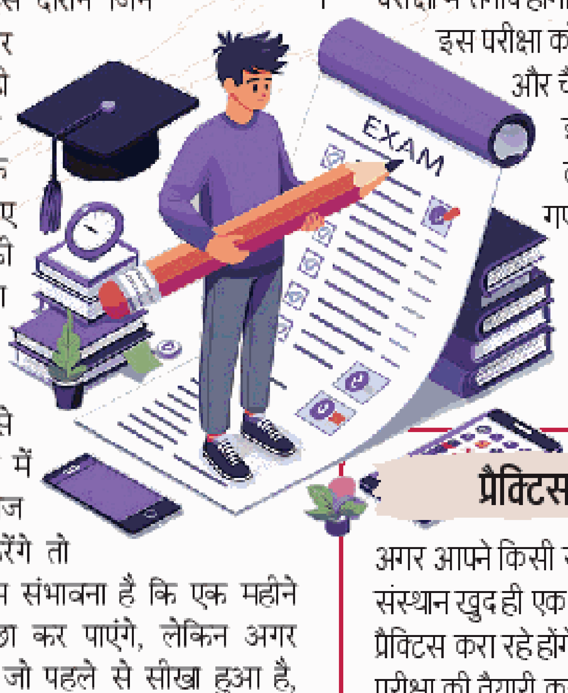

आनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से

आगामी जेईई एडवांस्ड-2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले महीने अप्रैल में शुरू होगी। इसके लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है।

योग्यता: वर्ष 2025 या 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ विषयों के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपीयर होना चाहिए। एनटीए द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए जेईई मेन 2026 क्वालिफाइड होना भी जरूरी है।

पेपर पैटर्न: इस परीक्षा में तीन घंटे की अवधि के दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर्स में सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। प्रत्येक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी मोड में) होगी। परीक्षा एक ही दिन दो सेशन में आयोजित की जाएगी। जेईई मेन के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में टाप ढाई लाख उम्मीदवारों का चयन इस परीक्षा के लिए किया जाता है। जेईई एडवांस्ड में लगातार दो साल तक दो बार अटेंप्ट के लिए अवसर दिया जाता है।

उम्र सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर, 2001 के बाद हुआ हो। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों को पांच साल की छूट प्राप्त है यानी उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर, 1996 के बाद होना चाहिए।

आनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि: 23 अप्रैल से 2 मई, 2026 तक।

परीक्षा तिथि: 17 मई, 2026

कैसे करें रजिस्ट्रेशन: इसके लिए वेबसाइट https://jeeadv.ac.in देखें।

प्रैक्टिस का सही तरीका

अगर आपने किसी संस्थान को ज्वाइन किया है तो संस्थान खुद ही एक नियमित अंतराल पर आपको प्रैक्टिस करा रहे होंगे, लेकिन यदि आप खुद से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वर्ष 2015 से 2025 तक के पिछले वर्षों के जेईई एडवांस्ड के पेपर्स को उठा लीजिए। इन कुल 11 पेपर्स पर 11 दिन इन्वेस्ट करें। प्रति सप्ताह इसमें से दो पेपर ट्राई करें। इस तरह 30 से 35 दिन में यह कवर हो जाएगा। बाकी परीक्षा से पहले बचे पांच दिन सिर्फ रिवीजन करें। पेपर प्रैक्टिस के बाद इस चीज का विश्लेषण जरूर करें कि संबंधित गलती किस कारण से हुई है। अगर इन पेपर्स की प्रैक्टिस में आपके 50 से 60 प्रतिशत तक अंक आ रहे हैं तो समझिए तैयारी सही दिशा में है। इतने प्रतिशत अंक का मतलब है आपका रैंक 300 से 400 के बीच आ रहा है। हो सकता है कि 200 रैंक में भी आ जाए।

प्रस्तुति : धीरेंद्र पाठक

मैं मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूं...

काउंसलर

देवाशीष उपाध्याय
councelor@nda.jagran.com

मैं विगत तीन वर्षों से नीट की तैयारी कर रहा हूं, परंतु चयन नहीं हो पा रहा है। मैं मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहता हूं। नीट परीक्षा में सफल होने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरे कौन से विकल्प हैं, कृपया मार्गदर्शन करें।

राजेश कुमार यादव

नीट में सफलता प्राप्त करने के लिए कुशल रणनीति के साथ कठोर परिश्रम आवश्यक है। यदि किसी कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बैचलर आफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी), बीफार्मा, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स के अतिरिक्त अनेक पैरामेडिकल कोर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें करने के बाद मेडिकल सेक्टर में बेहतरीन करियर बनाया जा सकता है। पैरामेडिकल कोर्स जैसे- डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलाजी (डीएमएलटी), डिप्लोमा इन रेडियोलाजी एंड इमेजिंग टेक्नोलाजी (डीआरआइटी), डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हास्पिटल मैनेजमेंट (डीएचएचएम) इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करना नीट परीक्षा में सफल होने की तुलना में बहुत आसान है। ये कोर्स विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थान में उपलब्ध हैं। आप अपनी सरुचि के अनुरूप किसी भी कोर्स में प्रवेश लेकर मेडिकल सेक्टर में करियर बना सकते हैं।

मैं 12वीं की छात्रा हूं। मैं सोशल वर्क के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हूं। मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? सोशल वर्क के क्षेत्र में करियर विकल्प क्या है

रुचि गुप्ता

सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ की बढ़ती भूमिका के कारण सोशल वर्क के क्षेत्र में करियर के बेहतरीन अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सोशल वर्क के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित बैचलर इन सोशल वर्क (बीएसडब्लू) या बैचलर इन सोशल साइंस, डिप्लोमा इन सोशल वर्क जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। आप 12वीं के बाद अपनी रुचि अनुसार सोशल वर्क से संबंधित कोई बैचलर कोर्स कर सकती हैं। यह बैचलर कोर्स करने के बाद मास्टर इन सोशल वर्क (एमएसडब्लू) कोर्स कर सकती हैं। एमएसडब्लू कोर्स करने के बाद सरकारी, प्राइवेट और एनजीओ सेक्टर में नौकरी के अनेक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। स्वतंत्र रूप से भी इस क्षेत्र में काम करने के मौके हैं।

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें -feature@jagran.com

स्कालरशिप एलर्ट

आइआइटी मंडी समर इंटर्नशिप-2026

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मंडी द्वारा पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे छात्रों को यह इंटर्नशिप प्रदान की जा रही है। यह एक से दो माह का आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रायोगिक अनुसंधान प्रशिक्षण दिया जाता है।

योग्यता: चुनिंदा कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में बीई/बीटेक (तृतीय वर्ष) या स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) में अध्ययनरत छात्र आवेदन के पात्र हैं।

सहायता: चुने गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।

अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2026

www.b4s.in/dj/ITMS2

एलन में जेईई व नीट के बैच की तिथियों की घोषणा

कोटा (राजस्थान) स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट व इसके अन्य सेंटर्स पर आइआइटी जेईई व नीट यूजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए नए बैच के तिथियों की घोषणा कर दी गई है। बैच मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहे हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के प्रसीडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि एलन की ओर से आगामी कई तिथियों में एलन स्कालरशिप एडमिशन टेस्ट (एसेट) का आयोजन किया जाएगा। एसेट में शामिल होने वालों को एडमिशन पर 90 प्रतिशत तक की स्कालरशिप मिलेगी। एलन कोटा में कक्षा 11 में जाने वाले छात्रों के लिए नर्चर बैच 25 मार्च व 2 अप्रैल से, कक्षा 12 में जाने वालों के लिए बैच 2 व 3 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.allen.in देखें।

राष्ट्रीय जागरण

किसानों की आय में हुई दोगुनी वृद्धि: शिवराज

लोकसभा में मंगलवार को बोलते कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने दावा किया है कि पिछले एक दशक में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में यह तीन से चार गुना तक बढ़ी है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जहां आय के आठ गुना तक बढ़ने की बात सामने आई है। लोकसभा में मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है और एमएसपी को लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय करने का निर्णय किसानों के हित में बड़ा कदम साबित हुआ है। विपक्ष की ओर से सवाल था कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ।

शिवराज ने कहा कि जिन किसानों ने पारंपरिक अनाज की जगह बागवानी, दलहन, तिलहन या अन्य नकदी फसलों की ओर रुख किया, उनकी आय में अधिक वृद्धि हुई है। यह संकेत है कि नीति तभी अधिक प्रभावी होती है जब किसान नवाचार अपनाने में सक्षम हों।

ट्रांसजेंडर की सुरक्षा व अधिकारों में बदलाव संबंधी बिल लोस से पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा ने ट्रांसजेंडर की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े संशोधन विधेयक को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विधेयक पर हुई चर्चा पर कहा कि विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा देना है, जिन्हें बायोलाजिकल समस्याओं की वजह से बायकाट का सामना करना पड़ता है। इस बदलाव से यह पक्का होगा कि ट्रांसजेंडरों को कानूनी पहचान और सुरक्षा दोनों ही मिलती रहेगी। ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक-2026 पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक से ट्रांसजेंडर के अधिकारों को प्रभावित करने वाले लोगों को अब अधिकतम 14 साल की जेल की सजा प्रविधान किया गया है। जबकि, 2019 के कानून में अधिकतम दो साल की सजा का प्रविधान किया गया था। इस दौरान संशोधन विधेयक का विपक्ष ने विरोध करते हुए संसद की स्थाई समिति के पास भेजने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि सरकार इस विधेयक के जरिये ट्रांसजेंडर को स्वयं की पहचान तय करने के दिए गए अधिकार को छीन रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद यह कानूनी रूप ले लेगा।

ये होंगे प्रमुख बदलाव

- विधेयक 'ट्रांसजेंडर' शब्द की परिभाषा को संशोधित करता है। इसमें अब जैविक या शारीरिक लक्षणों या विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे किन्नर, हिजड़ा) वाले व्यक्तियों को ही शामिल करने का प्रस्ताव है।
- इस विधेयक के जरिये ट्रांसजेंडर की स्वयं पहचान तय करने के दिए गए अधिकार को सीमित कर दिया गया है। अब ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता के लिए उन्हें मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
- ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराधों पर गंभीरता के आधार पर अधिकतम 14 साल की सजा का प्रविधान।

राहुल ने ट्रांसजेंडर विधेयक को खतरनाक और संवैधानिक अधिकारों पर बताया हमला

कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़े संशोधन विधेयक को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए संसद के बाहर व भीतर भी विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदायों का सम्मान करने के समृद्ध इतिहास को नष्ट कर रही है। यह बिल ट्रांसजेंडर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों पर खुला हमला है। बिल पर चर्चा से पूर्व ट्रांसजेंडर समुदाय प्रतिनिधियों से संसद भवन में मुलाकात के बाद राहुल ने एक्स पर विरोध जताया।

देश में इस साल 74 दिनों में हिरासत में 170 मौतें

नई दिल्ली, एएनआइ: सरकार ने संसद को बताया कि इस साल एक जनवरी से 15 मार्च तक देश में हिरासत में 170 मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के आधार पर संसद में जानकारी दी।

बिहार में इस वर्ष अब तक हिरासत में मौतों के सबसे अधिक 19 दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में 14-14 मामले दर्ज किए गए हैं। ओडिशा में नौ और बंगाल में सात मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में हिरासत में मौतों के चार मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में सात, तेलंगाना में पांच और कर्नाटक में तीन मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में भी इसी अवधि में हिरासत में मौतों के तीन मामले सामने आए। असम में पांच मामले दर्ज किए गए। अरुणाचल में तीन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। मिजोरम, सिक्किम व लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में 2026 में हिरासत में मौत का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

किस वर्ष कितनी मौतें

वर्ष	हिरासत में मौतें
2024-25	140
2023-24	157
2022-23	163
2021-22	176

अब संसद के बजट सत्र में ब्रेक के बाद ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक संभव

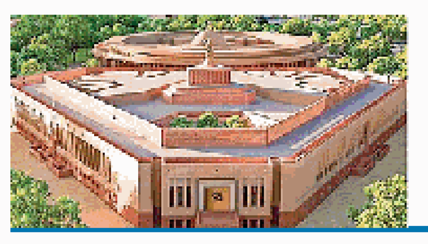

सत्र का जल्दी स्थगन संभव, सत्रावसान नहीं होगा, बाद में चार-पांच दिन का सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक लाया जाएगा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में आरक्षण संबंधी कानून में संशोधन के लिए लाए जाने वाले बिल में कुछ दिन की देरी संभव है। कांग्रेस की ओर से बैठक के लिए समय नहीं दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र समय से पहले स्थगित कर दे और कुछ समय बाद फिर से चार-पांच दिन का सत्र बुलाकर इसे पारित करे। दरअसल सरकार सीमांकन में अब देर नहीं करना चाहती है। उसके साथ ही महिला आरक्षण लागू किया जाना है।

कांग्रेस की ओर से 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाने का आग्रह किया गया है। इस पर फैसला बुधवार को होने की संभावना है क्योंकि गुरुवार को रामनवमी की छुट्टी है। अगर सत्र पहले स्थगित किया जाता है तो सत्र का सत्रावसान नहीं होगा ताकि उचित समय पर फिर से इसे बुलाने का विकल्प खुला रहे और बाद में चार-पांच दिन का छोटा सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (जिसे आमतौर पर महिलाओं के आरक्षण कानून के रूप में जाना जाता है) में संशोधन वाला बिल पेश किया जा सके। बता दें कि बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में दो चरणों में 23 व 29 अप्रैल को वोट पड़ने हैं और चार मई को नतीजे आने हैं।

'चुनावों के बाद महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए महिला आरक्षण कानून में संशोधन बिल लाने से पहले इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक के बाद 15 विपक्षी नेताओं ने सरकार को साझा पत्र भेजकर मांग की है कि 29 अप्रैल के बाद यह सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। केंद्र लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन से संबंधित दो विधेयक मौजूदा सत्र में लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए 15 वर्ष के लिए आरक्षित होंगी।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में भी इस विधेयक का जिक्र नहीं है। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए सरकार सभी दलों से विचार-विमर्श करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह राजग के कुछ घटक दलों के अलावा छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सोमवार को बैठकें कर चुके हैं लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस व तृणमूल के साथ महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में मौजूदा सत्र को स्थगित कर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है।

कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ गायब

राजेश मलकानियां, जागरण, पंचकूला: आइडीएफसी बैंक घोटाले का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अब कोटक महिंद्रा बैंक में जमा पंचकूला नगर निगम के लगभग 160 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आ गया है। इस खेल में कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। नगर निगम ने इस बैंक में पांच से आठ करोड़ की अलग-अलग एफडी (फिक्स्ड डिपाजिट) करवाई थीं। पूरी राशि लगभग 160 करोड़ की है। बैंक अधिकारियों और कर्मियों ने पूरी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी और निगम को केवल कागजी रिकार्ड थमाए जाते रहे। कई वर्षों तक इस काम को अंजाम दिया गया। घोटाला सामने आने पर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पंचकूला के ही किसी व्यक्ति के खाते में ट्रांजेक्शन की गई और उसके बाद पूरी राशि को आगे घुमाया गया।

आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने नगर निगम के नाम पर चार जाली खाते खोलकर पूरी रकम उनमें ट्रांसफर कर दी। फर्जी ई-मेल आइडी बनाई गई, जिससे बैंक के उच्च अधिकारी किसी भी ट्रांजेक्शन की वेरीफिकेशन प्राप्त कर लेते थे। सूत्र बताते हैं कि आरटीजीएस के जरिए ट्रांजेक्शन में फर्जी हस्ताक्षर और स्टैंप का इस्तेमाल किया गया।

एक नजर में

मणिपाल हेल्थ ने जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली : अस्पताल चेन का संचालन करने वाली कंपनी मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, इस आइपीओ में आठ हजार करोड़ रुपये के नए शेयर और 4,32,27,668 प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि में से 5,378 करोड़ रुपये कर्ज भुगतान और 574 करोड़ रुपये सब्सिड्यिरी सहयाद्री हास्पिटल्स में हिस्सेदारी खरीदने पर किया जाएगा। (प्रेट्र)

गुजरात में एक और संयंत्र लगाएगी मारुति सुजुकी

नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात में बनने वाले नए मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र के पहले चरण में 10,189 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता सालाना 2.5 लाख इकाई होगी। खोरज औद्योगिक एस्टेट में बनने वाला यह मारुति का देश में पांचवां मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र होगा। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि पहले चरण का निर्माण कार्य 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 24 लाख इकाई है। (प्रेट्र)

अगले वर्ष घट सकता है निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च

नई दिल्ली : अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान के दौरान निजी क्षेत्र का नई संपत्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत खर्च 16.5 प्रतिशत घटकर 9.55 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में नई संपत्तियों के अधिग्रहण पर कुल पूंजीगत खर्च 11.43 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सर्वेक्षण में 5,366 चालू उद्यमों में से 4,203 (लगभग 78.3 प्रतिशत) ने अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए अपनी पूंजीगत निवेश योजनाओं की जानकारी दी। (प्रेट्र)

अमेरिका-ईरान वार्ता से भारतीय बाजारों में उछाल

सेंसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,068 पर पहुंचा, एनएसई निफ्टी में 400 अंकों की बढ़त रही

मुंबई, प्रेट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के एनर्जी इन्फ्रा पर किए जाने वाले हमलों पर अस्थायी रोक के एलान से मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग दो प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत उछलकर 74,068.45 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान एक समय यह 1,793 अंक या 2.46 प्रतिशत चढ़कर 74,489.39 के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 399.75 अंक या 1.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,912.40 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में लार्सन एंड टूब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, इटरनल, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। केवल पावरग्रिड और एसबीआइ के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति 7.56 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4,22,78,312.77 करोड़ रुपये हो गई। ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर कहा है कि उन्होंने ईरान के लिए स्ट्रेट आफ होर्मुज को फिर से खोलने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह जलडमरूमध्य पर्शियन गल्फ और गल्फ आफ ओमान के बीच स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को पांच दिनों तक टालने का भी एलान किया है।

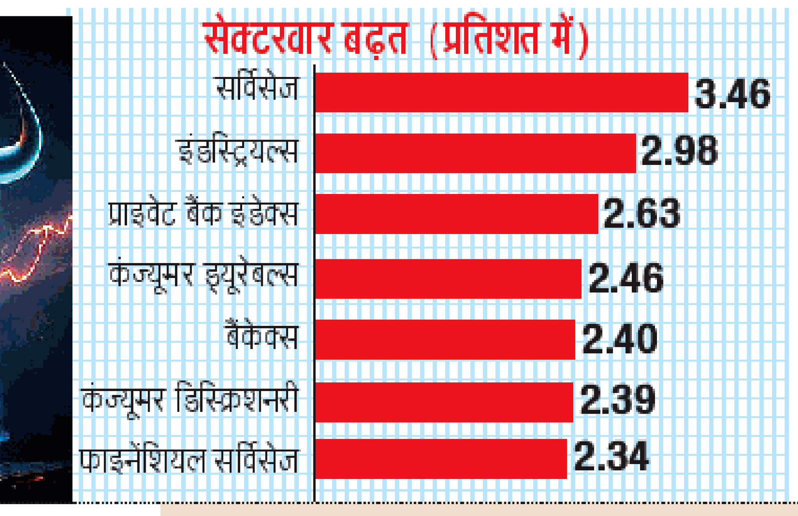

सोमवार को हुई भारी बिकवाली के बाद बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। यह रिकवरी मुख्य रूप से जोखिम की धारणा में आई कमी के कारण हुई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में संभावित कमी के शुरुआती संकेतों ने निवेशकों का कुछ भरोसा बहाल करने में मदद की। इस तेजी को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

-हरिप्रसाद के, संस्थापक, लाइवलांग वेल्थ

एशियाई बाजारों में भी रही तेजी

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स काफी बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त रही थी।

23 पैसे टूटकर 93.76 के रिकार्ड निचले स्तर पर रुपया

मुंबई, प्रेट्र : रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.76 प्रति डालर पर आ गया। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की मजबूती और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते निवेशकों में चिंता का माहौल रहने से घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों की निकासी ने भी रुपये पर दबाव डाला। रुपया 93.66 पर खुला और अंत में यह 93.76 पर रहा, जो पिछले बंद स्तर से 23 पैसे की गिरावट है।

मिस-सेलिंग पर बैंक को लौटाना होगा ग्राहकों को पूरा पैसा

राजीव कुमार ● जागरण

- बैंकों में थर्ड पार्टी उत्पाद बेचने को लेकर आरबीआइ ला रहा है नया नियम
- सभी बैंकों को बनाना होगा एक तंत्र, तय समयसीमा में दूर करनी होगी शिकायत

नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस जैसे थर्ड पार्टी उत्पाद ग्राहकों को भ्रामक जानकारी देकर बेचना अब बैंकों को भारी पड़ सकता है। मिस-सेलिंग को लेकर लगातार शिकायत मिलने पर आरबीआइ बैंकों के लिए नया नियम लाने जा रहा है जो आगामी जुलाई से लागू हो सकता है। नए नियम को लेकर आरबीआइ की तरफ से जारी मसौदे के मुताबिक अगर ग्राहकों को लगता है कि उसे गुमराह करके या भ्रामक जानकारी देकर बैंक ने उत्पाद की बिक्री की है तो वह उसकी शिकायत कर सकता हैं।

ग्राहकों की शिकायत प्राप्त करने के लिए सभी बैंक एक तंत्र बनाएंगे और ग्राहकों को शिकायत के लिए एक समयसीमा दी जाएगी। अगर समयसीमा नहीं दी गई है तो ग्राहक उत्पाद के खरीदने के अधिकतम 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आरबीआइ के मसौदे के मुताबिक मिस-सेलिंग को लेकर अगर ग्राहक की शिकायत सही पाई जाती है तो बैंक ग्राहक को पूरा पैसा वापस करेगा और उत्पाद को रद करने की सूचना ग्राहक को देगा। अगर ग्राहक को उस खरीदारी से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसका भुगतान भी बैंक करेगा। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की मिस-सेलिंग पर बैंक के कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाए। बैंक अपने किसी उत्पाद के साथ थर्ड पार्टी के उत्पाद को नहीं जोड़ेगा। थर्ड पार्टी उत्पाद की बिक्री के बाद बैंक ग्राहकों से 30 दिनों के भीतर फीडबैक भी लेगा कि ग्राहक उस उत्पाद से कितना संतुष्ट है। इस फीडबैक के आधार पर छमाही रूप से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

एसबीआइ ने थर्ड पार्टी के उत्पाद बेचकर कमाएं 4,522 करोड़: बैंकों में किसी अन्य के वित्तीय उत्पाद को बेचने का चलन है। बैंकों को इस बिक्री पर कमीशन या शुल्क का भुगतान होता है। पिछले पांच सालों के दौरान बैंकों को थर्ड पार्टी वित्तीय उत्पादों को बेचने से मिलने वाले कमीशन की राशि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रकार की बिक्री से कमीशन के रूप में 4522 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 652 करोड़ रुपये अधिक है। अभी बैंकों में लोन लेने के दौरान थर्ड पार्टी उत्पाद बेचने की पेशकश की जाती है। छोटे शहरों के कम जानकार जमाकर्ताओं को थर्ड पार्टी उत्पाद से अधिक लाभ मिलने की बात बताकर उन्हें इसकी बिक्री कर दी जाती है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मिस-सेलिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि बैंक को अपने मुख्य काम (जमा लेना और उधार देना) पर ध्यान देना चाहिए।

रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : अर्थशास्त्रियों के अनुसार आरबीआइ आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में (6-8 अप्रैल) में यथास्थिति बनाए रख सकता है। इसका कारण यह है कि निकट भविष्य में वैश्विक घटनाक्रमों का असर महंगाई के बजाय विकास पर ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। अग्रणी निवेश बैंक एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा स्थिति का ज्यादा असर विकास पर ज्यादा पड़ेगा। एचएसबीसी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, 'हमारा मानना है कि आठ अप्रैल की बैठक पूरी तरह से तेल की कीमतों में झटके को लेकर चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होगी।''

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

पूर्व चेयरमैन के पत्र की स्वतंत्र जांच कराएगा एचडीएफसी बैंक

नई दिल्ली, प्रेट्र: एचडीएफसी बैंक ने अपने पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के त्याग पत्र में उठाए गए मुद्दों की स्वतंत्र जांच के लिए कई बाहरी ला फर्म नियुक्त की है। बैंक ने एक निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाया है।

बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उन उच्चतम प्रशासन मानकों के साथ लगातार तुलना करना है, जिनका पालन बैंक दशकों से करता आ रहा है। बता दें कि अतनु चक्रवर्ती ने देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से 18 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया था। अपने त्याग पत्र में चक्रवर्ती ने नैतिक चिंताओं का हवाला दिया था। यह पहली बार है जब एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन ने कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ दिया है, जिससे बैंक के कामकाज को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

अप्रैल से फरवरी के दौरान 99 कंपनियों ने आइपीओ से जुटाए 1.65 लाख करोड़ रुपये

- 2024-25 में 79 कंपनियों ने 1.62 लाख करोड़ जुटाए थे
- एनएसई इमर्ज पर 105 कंपनियों ने 5,121 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत का प्राइमरी मार्केट मजबूत बना हुआ है और मेनबोर्ड आइपीओ ने अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि एसएमई सेगमेंट में सक्रियता थोड़ी कम रही। एनएसई मार्केट पल्स रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से फरवरी के दौरान 99 कंपनियों ने अपने पब्लिक इश्यू लांच किए, जिनसे उन्होंने कुल 1.65 लाख करोड़ रुपये जुटाए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 79 कंपनियों के आइपीओ आए थे और इन्होंने कुल मिलाकर 1.62 लाख रुपये जुटाए थे। यह वृद्धि बड़े पब्लिक आफरिंग में निवेशकों की लगातार दिलचस्पी को दिखाती है।

दूसरी ओर, इस दौरान एसएमई सेगमेंट में कुछ नरमी दिखाई पड़ती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर कुल 105 आइपीओ लांच किए गए और इनके जरिये 5,121 करोड़ रुपये जुटाए गए। यह वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले कम है। उस समय 163 आइपीओ ने 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए थे। कुल मिलाकर दोनों सेगमेंट के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 204 कंपनियों ने आइपीओ के जरिये 1.70 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 242 कंपनियों ने 1.69 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पता चलता है कि आइपीओ की संख्या में कमी आई है, लेकिन बड़े आकार के चलते जुटाए गए कुल फंड मजबूत बने रहे। रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में एसएमई आइपीओ का आकार लगभग औसत 50 करोड़ रुपये रहा है।

मेनबोर्ड पर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों का रहा दबदबा

सेक्टर के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों ने मेनबोर्ड के जरिये निवेश जुटाने में अपना दबदबा बनाए रखा और इनका कुल योगदान 34 प्रतिशत रहा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फर्मों का योगदान 31 प्रतिशत रहा जबकि इंडस्ट्रियल कंपनियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत रही। एसएमई में इंडस्ट्रियल कंपनियों ने 36 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा योगदान दिया।

अब स्विगी ने प्लेटफार्म फीस 17 प्रतिशत बढ़ाई

नई दिल्ली, आइएएनएस: जोमैटो के बाद फूड अब डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने अपनी प्लेटफार्म फीस में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। स्विगी के एप पर उपलब्ध बिलिंग के अनुसार, अब उसके प्लेटफार्म से खाना मंगाने वालों को 17.58 रुपये प्रति आर्डर की प्लेटफार्म फीस देनी पड़ेगी, जो पहले 14.99 रुपये प्रति आर्डर थी। यानी अब ग्राहकों को प्लेटफार्म फीस के रूप में प्रति आर्डर 2.59 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

यह संशोधित फीस अब स्विगी के एप पर दिख रही है। कंपनी ने यूजर्स को बताया है कि यह बढ़ोतरी उसे ''प्लेटफार्म को चलाने और उसका रखरखाव करने'' में मदद करने के लिए की गई है। पिछले सप्ताह ही जोमैटो ने अपनी प्लेटफार्म फीस में 19 प्रतिशत या दो रुपये प्रति आर्डर की बढ़ोतरी की थी। ताजा संशोधन के बाद स्विगी और जोमैटो दोनों की प्लेटफार्म फीस जीएसटी के साथ 17.58 रुपये प्रति आर्डर के करीब हो गई है।

अन्नाद्रमुक देगी परिवार को दस व महिला मुखिया को दो हजार

चेन्नई, एएनआइ : तमिलनाडु के प्रमुख विपक्षी दल और राजग सहयोगी अन्नाद्रमुक ने लोकलुभावन चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। इसमें प्रदेश में हरेक परिवार को दस हजार रुपये का महंगाई भत्ता और परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह दो हजार रुपये देने का वादा किया गया है। पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आती है, तो सभी चावल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त फ्रिज दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें एक किलो दाल और एक लीटर खाद्य तेल मुफ्त दिया जाएगा।

विधानसभा में विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के.पलानीस्वामी ने मंगलवार को 297 वादों के साथ घोषणापत्र में कर बोझ और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए प्रति परिवार 10 हजार रुपये की विशेष सहायता की घोषणा की है। घोषणापत्र में कहा गया, ''प्रशासनिक रूप से अक्षम द्रमुक सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गई हैं। यह राशि सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी।'' पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया। प्रत्येक राशनकार्ड धारक को प्रति वर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर भी मिलेंगे।

के. पलानीस्वामी. फाइल फोटो

तमिलनाडु में राजग में सीट बंटवारे पर सहमति, द्रमुक गठबंधन में खींचतान जारी

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राजग में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, जबकि सत्तारुढ़ द्रमुक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। वहीं, द्रमुक की सहयोगी पार्टी वीसीके ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पुड्डुचेरी विधानसभा चुनाव में तीन सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में द्रमुक से दो अंकों की संख्या में सीटें लड़ने की मांग की है। हालांकि, वीसीके राज्य में आठ सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गया है। द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में तब गतिरोध आ गया जब माकपा ने छह सीटों की मांग की, लेकिन अंततः पांच सीटों पर सहमति बनी।

बंगाल में एसआइआर की पूरक सूची पर असमंजस

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में सोमवार मध्य रात्रि को जारी हुई एसआइआर की पहली पूरक सूची को लेकर असमंजस की स्थिति है। चुनाव आयोग की ओर से इसे लेकर अब तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। इसके चलते, यह पता नहीं चल पा रहा है कि कुल कितने लोगों के नाम कटे हैं और कितनों के नाम इससे अंतिम मतदाता सूची में जुड़े हैं।

राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर बेचैनी है। कितने विचाराधीन मामलों के निपटारे के आधार पर यह सूची जारी की गई है, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पूरक सूची के बारे में जानकारी दिए बिना ही चुनाव आयोग की ओर से इसे जारी किया गया है। पहले सोमवार शाम छह बजे के बाद सूची जारी होने की बात थी। रात आठ बजे तक जब सूची जारी नहीं हुई, तब सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने इतना ही बताया कि रात नौ बजे के बाद पूरक सूची जारी हो जाएगी, हालांकि इसे जारी होने में रात के करीब 12 बज गए। सीईओ ने यह भी बताया था कि विचाराधीन 60 लाख मामलों में से अब तक 29 लाख का निपटारा हुआ है। इससे पहले ईद के पूर्व पूरक सूची जारी होने की बात कही जा रही थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूरक सूची का एक विकल्प शामिल किया है, जहां विचाराधीन श्रेणी वाले लोग अपनी वर्तमान स्थिति का पता कर सकते हैं। हालांकि देखा गया है कि कई मामलों में सूची डाउनलोड नहीं हो पा रही है।

अशांति टालने को आयोग ने अपनाया है बीच का रास्ता: जानकारों के एक वर्ग का मानना है कि पूरक सूची को लेकर अशांति की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल यह तरीका अपनाया है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इससे विचाराधीन श्रेणी के लोग आप्शन यानी विकल्प में जाकर अपनी वर्तमान स्थिति का पता तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें समग्र रूप से कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा। इससे चुनाव के समय व्यापक सामूहिक आक्रोश पैदा होने को रोका जा सकेगा।

बंगाल के एसआइआर के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से संपर्क करें सीएम : शीर्ष कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे सीमावर्ती राज्य बंगाल में चल रहे एसआइआर के संबंध में अपनी शिकायतों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य जज से संपर्क करें।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ ने मंगलवार को कहा, 'अन्य राज्यों में अब लगभग कोई मुकदमा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में एसआइआर के बाद लोगों की निष्कासन दर अधिक है।' याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि उठाए गए कई मुद्दे प्रशासनिक प्रकृति के हैं और इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि चुनावी सूची को मतदान से सात दिन पहले स्थिर करना आवश्यक है और यह प्रस्तुत किया कि कई उम्मीदवार जिनके नाम विचाराधीन हैं, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर नामांकन में असमर्थ हो सकते हैं।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि आयोग पूरक सूचियां दैनिक आधार पर प्रकाशित करने के लिए तैयार है।

शीर्ष कोर्ट ने पूछा- ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकार नहीं होते?

- आइ-पैक छापेमारी मामले में कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार
- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्तियों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र: कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार फर्म आइ-पैक के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या जांच एजेंसी के अधिकारियों के पास नागरिक के रूप में कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आठ जनवरी को मनी लांड्रिंग जांच के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य अधिकारियों ने बाधा उत्पन्न की थी।

अधिकारियों के अधिकारों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी: कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट ने पूछा, 'क्या केवल जांच एजेंसी का अधिकारी होने के कारण वे भारत के नागरिक नहीं रह जाते?' जस्टिस मिश्र ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, 'यदि आप केवल 'ईडी-ईडी' करते रहेंगे और उन अधिकारियों की याचिका भूल जाएंगे जो घटना के शिकार थे, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।'

प्राथमिकी रद करने की लालू यादव की मांग हाई कोर्ट ने ठुकराई

जासं, नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी रद करने की पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने मामले पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि लालू यादव की याचिका मेरिट के आधार पर टिकने योग्य नहीं है। साथ ही अदालत ने लालू यादव के इस तर्क को भी ठुकरा दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-17ए के तहत पहले से मंजूरी न होने के कारण जांच एजेंसी की कार्रवाई कानूनी रूप से सही नहीं है। अदालत ने कहा कि धारा-17 ए 2018 में लागू की गई थी, जबकि आरोप 2004-2009 के हैं।

एशिया के बड़े रेडलाइट एरिया के वोटरों को एसआइआर में ग्रीन सिग्नल

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

- मतदाता सूची में कोलकाता के सोनागाछी इलाके की लगभग शत-प्रतिशत यौनकर्मियों के नाम
- सोनागाछी में वास करती हैं करीब छह हजार यौनकर्मी, सभी कर सकेंगी मताधिकार

कोलकाता: बंगाल में एक ओर जहां मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के क्रम में 60,06,375 लोगों के नाम चुनाव आयोग के विचाराधीन हैं, वहीं एशिया के सबसे बड़े रेडलाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी की लगभग शत-प्रतिशत यौनकर्मियों (सेक्स वर्करों) के नाम सूची में शामिल हैं। सूची में उनके नाम को लेकर कोई समस्या नहीं है और वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगी। सोनागाछी में करीब छह हजार यौनकर्मी रहती हैं। यौनकर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन महिला दुर्बार समन्वय समिति की सचिव बिशाखा लस्कर ने बताया जिन यौनकर्मियों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उम्मीद है कि पूरक सूची में उनके नाम आ जाएंगे।

नाम कटने का था डर: बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यौनकर्मियों में नाम कटने का डर सता रहा था।

नीतीश चौथी बार निर्विरोध चुने गए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष

राब्यू, जागरण ● पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को चौथी बार निर्विरोध जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े से जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के निर्वाचन का प्रमाण पत्र हासिल किया। नीतीश की ओर से संजय झा ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में 19 मार्च को नामांकन किया था। नामांकन पत्र की जांच 23 मार्च को हुई। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं रहने की वजह से नामांकन वापसी की भी औपचारिकता नहीं थी।

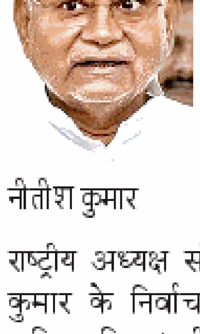

नीतीश कुमार

'11 विधायक मिलें तो मुस्लिम का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर'

जागरण संवाददाता, मेरठ: आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक भी मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। इस बयान को कानून-व्यवस्था तथा संवैधानिक मर्यादाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। पुलिस ने शौकत अली समेत छह नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला व महानगर अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

सोमवार को ईद मिलन कार्यक्रम में शौकत अली द्वारा दिए गए बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने शौकत अली पर कार्रवाई की मांग की है। एएसपी कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि मामले में आरोपित फहीम रजा व इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।

एआइएमआइएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कार्यक्रम में बोलते हुए ● वीडियो ग्रैब

ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने की ओर बड़ा कदम, पहली बार सड़क मार्ग से 'एंटीमैटर' का सफर

- ऐतिहासिक प्रयोग के तहत सीईआरएन के विज्ञानियों का पहली बार साहसिक परीक्षण
- यह जानने का मकसद कि क्या इस संवेदनशील पदार्थ को स्थानांतरित करना संभव?

जिनेवा, एपी: विज्ञान जगत में एक ऐतिहासिक प्रयोग के तहत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन) के विज्ञानियों ने पहली बार 'एंटीमैटर' (प्रतिद्रव्य) को प्रयोगशाला से बाहर सड़क मार्ग पर ले जाने का साहसिक परीक्षण शुरू किया है। 100 एंटीप्रोटोन को एक विशेष ट्रक के जरिये जिनेवा की सड़कों पर चार घंटे की यात्रा पर ले जाया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या इस बेहद संवेदनशील व विनाशकारी पदार्थ को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है।

जर्मनी तक पहुंचाने की भविष्य की योजना: यह परीक्षण उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत सीईआरएन के एंटीप्रोटोन को जर्मनी की हेनरिक हेन यूनिवर्सिटी ले जाया जाना है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि इस परीक्षण की सफलता से परिवहन की अवधि को दोगुना करने में मदद मिलेगी।

पदार्थ से संपर्क होते ही हो जाता है विस्फोट

एंटीमैटर की सबसे बड़ी चुनौती इसकी प्रकृति है। ब्रह्मांड में मौजूद हर कण का एक एंटीपार्टिकल होता है, जिसका आवेश विपरीत होता है। यदि एंटीमैटर सामान्य पदार्थ (मैटर) के संपर्क में आता है, तो वह तुरंत नष्ट हो जाता है और ऊर्जा की एक तेज चमक पैदा करता है। इस जोखिम से बचने को विज्ञानियों ने 1,000 किग्रा का एक विशेष 'ट्रांसपोर्टेबल एंटीप्रोटोन ट्रैप' विकसित किया है। इसमें सुपरकूल्ड मैग्नेट्स का उपयोग किया है जो एंटीप्रोटोन को -269 डिग्री सेल्सियस पर शून्य (वैक्यूम) में लटकाए रखते हैं, ताकि वे कंटेनर की दीवारों को न छुएं।

जेएएल अधिग्रहण पर अदाणी की बोली पर अंतरिम रोक से इन्कार

- अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं की समिति से एक सप्ताह में जवाब मांगा
- सुनवाई के दौरान बैंकों ने कहा- वेदांत का ऊंची बोली लगाना ही जीत की गारंटी नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के अधिग्रहण के लिए अदाणी समूह की 14,535 करोड़ रुपये की बोली पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। वेदांत समूह ने एनसीएलटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदाणी की बोली को मंजूरी दी गई थी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने जेएएल के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को होगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि फिलहाल समाधान योजना पर काम जारी रहेगा, लेकिन यह वेदांता समूह द्वारा दायर अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। वेदांता की बोली 16,726 करोड़ रुपये की थी, जबकि अदाणी एंटरप्राइजेज की बोली 14,535 करोड़ रुपये थी। कंपनी का तर्क है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) का मुख्य मकसद कर्ज में डूबी कंपनी की संपत्तियों की 'ज्यादा से ज्यादा कीमत' वसूलना है, लेकिन बैंकों ने कम बोली (अदाणी की बोली) को चुनकर नियम की अनदेखी की है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

धर्म और आरक्षण

धर्मांतरण और अनुसूचित जाति के दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला दूरगामी और सराहनीय है। शीर्ष अदालत ने साफ-साफ कहा है कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले इस समुदाय के व्यक्ति को अनुसूचित जाति वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति की एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत संरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था। निस्संदेह, वह उचित फैसला था। आखिर स्वेच्छा से कोई धर्म-परिवर्तन कब करता है? जब वह नए धर्म से प्रभावित होता है या फिर अपने मूल धर्म के किसी विद्रूप से हमेशा के लिए मुक्ति चाहता है! जिस धर्म की जाति-व्यवस्था से दुखी हो उसे छोड़कर आप किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं, फिर त्यागी गई जाति को हासिल सुविधाओं के हकदार कैसे हो सकते हैं? चाहे वह सुविधा शिक्षा संस्थानों या नौकरियों में आरक्षण की हो या सामाजिक प्रताड़ना से कानूनी संरक्षण की हो।

सदियों से समाज के हाशिये पर जी रही जातियों- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए संविधान-निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके पीछे उनका पवित्र उद्देश्य यही था कि इन समुदायों के लोग आजाद लोकतांत्रिक देश में अपने को अलग-थलग न समझें; उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो और एक समतामूलक भारतीय समाज का निर्माण हो सके। विडंबना यह है कि आज जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों को संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। कटु सच्चाई तो यह है कि सन् 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून बनाने की नौबत आई। इसलिए, सुनिश्चित किया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई इन कानूनों का दुरुपयोग न करे। जिस व्यक्ति की याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया है, वह धर्म-परिवर्तन करके दस वर्षों से एक प्रतिबद्ध ईसाई की भूमिका निभा रहा है, बल्कि पादरी बन चुका है और इसके बावजूद अपनी पुरानी जाति के लाभ उठाना चाहता था। इसलिए अदालत ने उचित ही कहा है कि ऐसा व्यक्ति किसी कानूनी, सांविधानिक या आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता।

धर्मांतरण के मुद्दे पर आए ताजा अदालती फैसले को संकीर्ण और सांप्रदायिक नजरिये से देखने के बजाय वंचित तबकों के हित से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब बौद्ध धर्म अपनाकर मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग कर रहे दो सवर्ण युवाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और इसे धोखाधड़ी करार दिया था। इसलिए, बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण के मुद्दे को संकीर्ण व सांप्रदायिक नजरिये से देखने के बजाय वंचित तबकों के हित से जोड़कर देखा जाए। जहां एक तरफ, इसे इसके भीतर के लोगों से खतरा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी लोग इसमें सेंध लगाने की फिराक में हैं। जिस कानून का निर्माण दलितों के संरक्षण के लिए हुआ है, उसका उपयोग दूसरे समुदायों को प्रताड़ित करने के लिए होगा, तो इससे उस कानून की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न ही लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए कि उसने साफ कर दिया है, यदि कोई घर वापसी करता है, तो एससी दर्जे की सुविधाएं हासिल करने के लिए यह साबित करना पड़ेगा कि वह सचमुच अपने धर्म में लौट आया है और उसे उस समुदाय ने कुबूल कर लिया है। वह उस समुदाय की सामाजिक प्रथाओं का हिस्सा बन चुका है। आखिर कोई दोहरा लाभ कैसे ले सकता है?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 25 मार्च, 1951

निरर्थक प्रयास

ऐसा विदित होता है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इससे कोई सरोकार नहीं कि काश्मीर की राजधानी में क्या हो रहा है और परिषद में प्रस्तुत, विचाराधीन अथवा स्वीकृत प्रस्तावों की काश्मीरी जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है।...

वास्तव में, काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए एक सीधा मार्ग खोजने के बजाय, विविध प्रस्तावों तथा सुझावों की भूल-भुलैया में प्रवेश कर आगे बढ़ने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा अमरीका का पहला प्रस्ताव भारत ठुकरा चुका था, किन्तु संशोधित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से कोई विशेष रूप में भिन्न नहीं। भिन्नता केवल इतनी है कि संशोधित प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को अगस्त 1948 तथा जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सैन्य विघटन कराना चाहिये।

प्रस्ताव पर ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा किये गये भाषणों पर दिल्ली के अधिकारी-क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया हुई है उसका सार यही है कि दो वर्ष पूर्व काश्मीर की समस्या जैसी थी, वैसी ही इस प्रस्ताव के बाद भी बनी रहेगी। दोनों ही प्रतिनिधियों के भाषणों की शब्दावली और ध्वनि भारतीय पक्ष की विरोधी थी। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि काश्मीर की समस्या पंच-फैसले से हल की जाये। सर ग्लैडविन जेब ने कहा कि पहले संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि मध्यस्थों के रूप में कार्य करते रहे, किन्तु अब ब्रिटिश सरकार का यह दृढ़ मत है कि इस प्रकार की विधि से दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर नहीं किया जा सकता।

अमरीकी प्रतिनिधि श्री ग्रास ने पंच-निर्णय को संशोधित प्रस्ताव का गुरुमंत्र बताते हुए कहा कि भारत ने पंच-निर्णय का सिद्धान्ततः विरोध नहीं किया है, किन्तु उसकी आपत्ति है कि इससे फिर कई सवालों का नया सिलसिला शुरू हो जायेगा।

काश्मीर सरकार द्वारा आयोजित संविधान सभा से पाकिस्तान के दिल में जो कंपकपी पैदा हो गई है, उसकी प्रतिध्वनि उपर्युक्त दोनों प्रतिनिधियों के भाषणों में मिलती है। वे भी इस आशंका से भयभीत हैं कि कहीं यह संविधान सभा भारत के साथ काश्मीर के मिलन पर अपनी मुहर न लगा दे।

तकनीक ने युद्ध को जटिल बना दिया

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

युद्ध में अब निर्णायक जीत का दावा कोई नहीं कर सकता। आधुनिक युद्ध लंबे समय तक जारी रह सकते हैं और उनके नतीजे भी अलग-अलग रूपों में सामने आ सकते हैं।

इस समय जारी अमेरिका-ईरान जंग और रूस-यूक्रेन युद्ध आधुनिक युद्धों के बदलते चरित्र की झलक देते हैं। एक का लंबा और थका देने वाला घमासान धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, तो दूसरे में तेज और कई तरह के दबावों का खुला प्रदर्शन दिख रहा है। हालांकि, इन दोनों युद्धों में जो एक बात आम है, वह यह कि तकनीकी विकास ने युद्धों को और ज्यादा जटिल व अप्रत्याशित बना दिया है। इनसे यह भी सुनिश्चित हुआ है कि युद्ध में अब निर्णायक जीत का दावा कोई नहीं कर सकता। उसकी जगह अनगिनत रूप में नतीजे सामने आने लगे हैं। इनमें जिद और समयानुकूल व्यवस्था व विस्तार देने में महारत से हासिल नतीजे अहम हो गए हैं।

यूक्रेन 21वीं सदी के संघर्षों का प्रतीक बन गया है। उसका युद्धक्षेत्र किफायती और असरदार हथियारों से भरा पड़ा है। रूस ने शुरुआती दौर में यूक्रेन की शक्ति और उसकी पश्चिमी हिमायत को कम करके आंका। पश्चिम से मिल रहे जबर्दस्त सैन्य मदद के कारण यह तो पक्का हो गया है कि यूक्रेन लड़ाई में बना रहेगा। यह लड़ाई पैंतरेबाजी के बजाय धीरज की परीक्षा ज्यादा ले रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध से यह भी पता चला है कि पारदर्शिता ने पूरी रणनीति को बदल दिया। व्यावसायिक सैटेलाइट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, समाचारपत्रों, सरकारी रिकॉर्ड से डाटा एकत्र करने और उनके विश्लेषण से उपयोगी खुफिया जानकारी प्राप्त करने की पद्धति और नेटवर्क ने सबको अचरज में डाल दिया।

इसके ठीक विपरीत, अमेरिका-ईरान युद्ध अपनी मारक तीव्रता, सटीकता और बहुआयामी तरीकों वाले संघर्ष का अलग रास्ता दिखाता है। पिछले साल के 12 दिवसीय इजरायल-ईरान युद्ध जैसे उदाहरणों को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा संघर्ष ने यह दिखाया है कि कैसे 'काइनेटिक हमलों' और अदृश्य चीजों, जैसे साइबर ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध व अंतरिक्ष-आधारित बाधाओं के समन्वय से तेजी से हवाई दबदबा बनाया जा सकता है। अमेरिका-इजरायल ने इस युद्ध के शुरू

में ही ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को खत्म करके कुछ ही दिनों में जवाबी हमले की उसकी क्षमता को कम कर दिया। फिर भी, यह सफलता पूरी और स्पष्ट नहीं दिखी।

बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन काफिलों और असली पहचान छिपाकर प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिये अलग-अलग तरीके से प्रहार करने की ईरान की क्षमता ने गोपनीय रणनीति की अहमियत को उजागर किया। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्ग को बाधित करने से युद्ध के आर्थिक पहलू पर गंभीर असर पड़ा। ऊर्जा बाजार में इससे बेचैनी फैल गई है और पश्चिम एशिया की इस अस्थिरता के अब पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

इन दोनों युद्धों में जो समान बात है, वह यह कि आधुनिक युद्ध निरंतरता के साथ लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। रूस और अमेरिका, दोनों ने अपने युद्ध अभियानों को अपनी सर्वश्रेष्ठता के अहंकार भाव के साथ शुरू किया, जिसमें माना गया था कि उनकी जीत तय ही है, लेकिन इन दोनों का सामना ऐसे दुश्मन से हुआ, जो अलग-अलग पहलुओं का फायदा उठाने, नई तकनीक के प्रयोग और जंग को सैन्य, सूचना-तंत्र और अर्थ-तंत्र तक विस्तार देने में माहिर हैं। नतीजा सामने है, जीत किसी की नहीं हो पा रही है। इसमें पारंपरिक अर्थों वाली जीत किसी को नहीं मिल पा रही है, बल्कि यह युद्ध निर्णायक लड़ाई कम और अनिश्चित हालात में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का प्रबंधन ज्यादा बन गया है।

रणनीतिक तौर पर देखें, तो इस युद्ध का संदेश साफ है, दुश्मन अगर मुकाबले का हो, तो वह न तो जल्दी खत्म होने वाला है और न ही निर्णायक होगा। गठबंधन, आर्थिक मजबूती और युद्ध-विस्तार का प्रबंधन अब मैदान की जीत जितने ही जरूरी हो गए हैं। यूक्रेन की जंग में टिके रहने की क्षमता पश्चिमी देशों के समर्थन से जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले का प्रभाव पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों से गहरे तालमेल पर निर्भर रहा है।

इसके उलट, अलग-थलग रहना आपके विकल्प सीमित करता है और आपको कमजोर बनाता है। सूचनाओं की भूमिका, चाहे साइबर ऑपरेशन हो या वैश्विक मीडिया के जरिये नैरेटिव गढ़ना हो, अब हाशिये से केंद्र में आ गई है, जिससे युद्ध की घरेलू वैधता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, दोनों पर असर पड़ रहा है। यूक्रेन ने साबित किया है कि कैसे हवाई दबदबे को तोड़कर किसी मजबूत दुश्मन को कमजोर किया जा सकता है, जबकि ईरान ने यह दिखाया है कि अगर साइबर व अंतरिक्ष क्षमताओं का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो हालात को बहुत जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है।

सामरिक दृष्टि से देखें, तो मारक क्षमता का विकेंद्रीकरण शायद सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ है। सस्ते ड्रोन और स्वचालित हथियारों ने लड़ाई के खर्च का हिसाब-किताब बदल दिया है। इसमें छोटे युद्धक तंत्र अति-विकसित फौजों पर भारी पड़ रहे हैं। लड़ाई में बने रहना इस बात पर निर्भर करने लगा है कि आपमें गतिशीलता, विस्तार और तेजी से अनुकूलित होने की क्षमता कितनी है? परंपरागत तरीके में टैंकों, लड़ाकू विमानों और स्थायी युद्धक ढांचे के नजर में आने और निशाना बनने के जोखिम लेकर काम करना होगा। ऐसे में, सफलता के लिए न सिर्फ तकनीकी परिष्कार, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर तेजी से अनुकूलित होने की क्षमता भी जरूरी है, जिससे निचले स्तर के कमांडरों को तत्क्षण फैसले लेने में मदद मिले।

कुल मिलाकर, भविष्य की जंगों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। सैन्य शक्ति अब भी जरूरी बनी हुई है, लेकिन यह अब अकेले निर्णायक नहीं रह गई है। तकनीक, आर्थिकी और राजनयिक अंतरसंबंधों से लड़ाइयों को जीतना और खत्म करना, दोनों ही मुश्किल हो जाएंगे। नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती होगी कि वे लक्ष्य को दक्षता के साथ हासिल करने, जल्दी जीत के लालच से बचने और लंबे समय के लिए तैयारी करने पर ध्यान दें।

इन जंगों से एक बात तो पक्की हो गई है कि आधुनिक युद्धों में नतीजे आकार या शुरुआती बढ़त से नहीं, बल्कि तेजी से बदलते युद्धक्षेत्र में सीखने, अनुकूलित होने और टिके रहने की क्षमता से तय होते हैं। आधुनिक युद्धों में सिर्फ दबदबा नहीं, बल्कि तेजी से अनुकूल बनना सफलता की असली कसौटी बन गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वैश्विक सहयोग और विकास का आधार बन रही संस्कृति

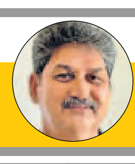

यहां स्कैन करें

शेखर चंद्र जोशी | प्रोफेसर एवं कला विशेषज्ञ

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में संस्कृति, रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, पहचान, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के बीच हुए सांस्कृतिक समझौते यही संकेत देते हैं कि संस्कृति अब कूटनीति, सहयोग और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम बन रही है।

सांस्कृतिक सहयोग और नीतिगत साझेदारियों में दुनिया भर में उल्लेखनीय वृद्धि दिख रही है। पेरू और यूरोपीय देशों के बीच स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा हेतु सहयोग को सुदृढ़ किया गया है। इसी प्रकार, क्रिएटिव न्यूजीलैंड और नियू सरकार के बीच प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। अफ्रीका में घाना और ऑस्ट्रिया के बीच पर्यटन, संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग विकसित किया जा रहा है। एशिया में फिलीपींस और जापान द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (एमएकेएएचएनआई- 2026) ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आपदा-प्रतिरोध जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाया है।

विभिन्न देशों के बीच हुए सांस्कृतिक समझौते यही संकेत देते हैं कि संस्कृति अब कूटनीति, सहयोग का एक सशक्त माध्यम बन रही है।

हालांकि, इस व्यापक विमर्श के केंद्र में कलात्मक स्वतंत्रता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कलाकार बिना भय, भेदभाव या दमन के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति पेश कर सकें। यह स्वतंत्रता केवल सृजन तक सीमित नहीं, बल्कि संसाधनों, मंचों और अवसरों तक समान पहुंच से भी जुड़ी है। डिजिटल युग में यह विमर्श और अधिक जटिल हो गया है। आज बड़ी संख्या में कलाकार डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रहे हैं। इससे सृजन की संभावनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। तकनीकी कौशल की कमी, डिजिटल असमानता और संसाधनों तक सीमित पहुंच आज भी अनेक कलाकारों के लिए बाधा बनी हुई है।

विशेष रूप से एआई और कॉपीराइट का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। अनेक देशों में यह आशंका जताई जा रही है कि एआई मॉडल के प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री का उपयोग बिना अनुमति हो रहा है, जिससे रचनाकारों के अधिकार और आय प्रभावित हो सकते हैं। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विधायी सुधार और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यूनेस्को के 2005 के 'सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता' सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि लगभग 85 प्रतिशत देशों ने सांस्कृतिक नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बावजूद इसके, चुनौतियां कम नहीं हैं। संस्कृति का अत्यधिक व्यावसायीकरण उसकी मौलिकता और विविधता को प्रभावित कर सकता है। अतः जरूरी है कि नीतियां सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण को ध्यान में रखकर विकसित की जाएं।

इस दिशा में सार्वजनिक निवेश की भूमिका अहम है। सरकारों को ऐसे संस्थागत और कानूनी ढांचे भी विकसित करने चाहिए, जो कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करें। सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक और स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना समय की मांग है। विश्व के विभिन्न देशों में इस बाबत सकारात्मक पहल देखने को मिल रही हैं। पराग्वे ने दीर्घकालिक सांस्कृतिक रणनीति विकसित की है, तो स्कॉटलैंड में सांस्कृतिक साझेदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है। सिंगापुर में समावेशी सांस्कृतिक योजनाओं के माध्यम से निम्न-आय वर्ग को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जबकि मॉरीशस जैसे देश कला निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार कर रहे हैं।

तकनीकी विकास को सामाजिक न्याय, समान पहुंच व सांस्कृतिक विविधता के साथ जोड़ना आवश्यक है। इसके साथ ही, लैंगिक असमानता भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। वीजा संबंधी समस्याएं, आर्थिक सीमाएं, पर्यावरणीय चिंताएं और सूचना की कमी भी कलाकारों की वैश्विक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। यह समझना होगा कि संस्कृति अतीत की धरोहर ही नहीं, वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली शक्ति भी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

साधना की उपलब्धि

अनेक साधक वर्षों तक साधना करते रहते हैं, पर उनके मन में एक प्रश्न बार-बार उठता रहता है, आखिर साधना की वास्तविक उपलब्धि क्या है? क्या यह कुछ आध्यात्मिक अनुभवों तक सीमित है या यह जीवन को गहरे स्तर पर बदलती भी है?

भारतीय संत परंपरा इस प्रश्न का उत्तर प्रेम और अनुभव के माध्यम से देती है। कई भक्त संतों ने कहा है कि साधना का सबसे बड़ा फल है परम सत्ता के प्रति गहरा और स्वाभाविक प्रेम। जब साधक के भीतर ईश्वर के प्रति ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जो किसी नियम, भय या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि हृदय की सहज भावना से उपजता है, तब वह भक्ति की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है। इसे ही रागात्मक या स्वाभाविक भक्ति कहा गया है। इस अवस्था में साधक के लिए ईश्वर का स्मरण कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि उसके जीवन की सहज धड़कन बन जाता है।

इस भाव को समझने के लिए प्रकृति की ओर देखना पर्याप्त है। विशाल समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं। वे कुछ समय के लिए अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे समुद्र से अलग नहीं होतीं। अंततः वे उसी समुद्र में लौट जाती हैं, जहां से उनका उद्भव हुआ था। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण सृष्टि एक अनंत चेतना से उत्पन्न होकर उसी में विलीन होने की ओर अग्रसर है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मन और प्रत्येक चेतना उसी मूल स्रोत की ओर लौटने की यात्रा में है।

कई संत कवियों ने इस सृष्टि को आनंद का महासागर बताया है। उनके अनुसार परम सत्ता आनंद और प्रेम का अनंत स्रोत है। इसी कारण इस जगत की प्रत्येक गति में एक लय और संगीत छिपा हुआ है। जब हवा बहती है, जब नदी बहती है, जब ग्रह और तारे अपने मार्ग पर चलते हैं, इन सबमें एक सूक्ष्म ताल और लय मौजूद रहती है। आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अनुभव इसी सूक्ष्म लय से जुड़ा हुआ माना गया है। जब साधक नियमित साधना के जरिये अपने मन को शांत और सूक्ष्म बनाता है, तब उसे भीतर एक अनोखी ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यह ध्वनि बाहरी कानों से सुनाई देने वाली नहीं होती, बल्कि चेतना के भीतर अनुभव की जाती है।

जब साधक नियमित साधना के जरिये मन को शांत और सूक्ष्म बनाता है, तब उसे भीतर एक अनोखी ध्वनि का अनुभव होने लगता है। भारतीय परंपरा में इसे 'ओंकार' या 'प्रणव नाद' कहा गया है।

भारतीय परंपरा में इसे 'ओंकार' या 'प्रणव नाद' कहा गया है। कई भक्त कवियों ने इसे कृष्ण की बांसुरी के मधुर स्वर के रूप में भी प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है।

जब साधक इस दिव्य ध्वनि का अनुभव करने लगता है, तब उसकी साधना में एक नया उत्साह और नई गहराई आ जाती है। उसे लगता है, कोई शक्ति उसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है। इस अवस्था में साधना बोझ नहीं रहती, आनंदमय यात्रा बन जाती है। यही वह बिंदु है, जहां भक्ति, ध्यान और प्रेम एक-दूसरे में मिल जाते हैं।

श्री श्री आनंदमूर्ति

दलाई लामा | बौद्ध धर्मगुरु

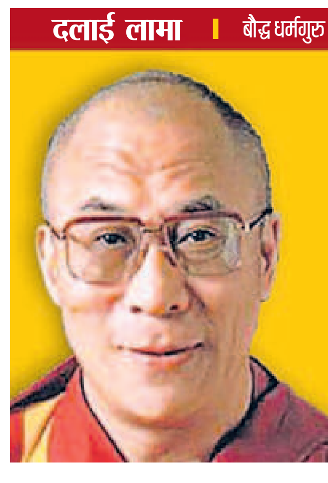

ईमानदार, सच्चे और भलाई करने वाले बनो। अगर तुम दूसरों का ख्याल रखने की फिक्र करोगे, तो झूठ, बदमाशी और धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगर तुम सच्चे हो, तो तुम साफ-साफ और ईमानदारी से जी सकते हो।

अनुलोम-विलोम

चुनावी वायदा

चुनावी तस्वीर बदल देगी यह घोषणा

अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां किस हद तक बढ़ चुकी हैं, इसका पता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई नई घोषणा से चलता है। उन्होंने रविवार को महिलाओं को सम्मानित किया और उनके सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कई एलान किए। उन घोषणाओं में से एक था- महिलाओं के लिए पेंशन। उन्होंने कहा कि अगर सूबे में सपा की सरकार बनी, तो महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन दिए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता केवल एक राजनीतिक वायदा नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी परिदृश्य को बदलने में भी सक्षम है। मुमकिन है, अब विभिन्न पार्टियों के बीच लोक-लुभावन घोषणाओं की प्रतिस्पर्द्धा और तेज हो जाए।

बहरहाल, भारत की चुनावी राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उभरी है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, नकद सहायता और मुफ्त योजनाएं मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रभावी साधन हैं। विशेषकर, महिला मतदाताओं के संदर्भ में यह रणनीति अधिक कारगर मानी जाने लगी है, क्योंकि स्त्रियां निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर चुकी हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों में विभिन्न प्रकार की नकद या सब्सिडी आधारित योजनाओं ने चुनावी परिणाम प्रभावित किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का वायदा कर रहे हैं, ताकि उनको अपने पक्ष में किया जा सके। साफ है, समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों पर दबाव होगा कि वे इससे भी अधिक आकर्षक या प्रतिस्पर्द्धी योजनाएं लाएं। भाजपा पहले से ही उज्ज्वला, मुफ्त राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिये लाभार्थी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं का विस्तार हो सकता है या ये नए रूप में आ सकती हैं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इस प्रकार की घोषणाएं राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के अनुकूल हैं या केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं?

यह छिपा तथ्य नहीं है कि लगातार बढ़ती मुफ्त योजनाएं राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डालती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी खर्च घट जाता है। वैसे, यह बहस भी गलत नहीं कि क्या मतदाता सिर्फ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के आधार पर मतदान का निर्णय लेते हैं या शासन की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे भी सोचते हैं?

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

इन वायदों में अब महिलाएं नहीं फंसेंगी

फ्रीबीज, यानी निःशुल्क योजनाएं शुरू करने का मकसद यह था कि राज्य लोगों की आमदनी में व्याप्त असमानता को कम करना चाहता था और अवसरों, सुविधाओं या स्टेटस में जो नाइंसाफी वे झेल रहे थे, उनको दूर करना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी योजनाएं लोगों को आलसी और नकारा बना रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सालाना 40 हजार रुपये महिलाओं को पेंशन देने संबंधी घोषणा को भी इसी की कड़ी मानना चाहिए। इससे अच्छा तो यह होता कि वह ऐसी योजनाओं का वायदा करते, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनातीं, उनके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलतीं या उनके सम्मान में बढ़ोतरी करतीं। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वही दांव खेला, जो तमाम राजनीतिक दल खेलते रहते हैं। उन्होंने भी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा।

इसी कारण मैं यह मानती हूं कि अव्वल तो महिलाएं अब इस तरह की घोषणाओं में नहीं फंसेंगी। 'पैसे देकर वोट खरीदने' की इस परंपरा को औरतें अब पसंद नहीं करतीं। वह दौर चला गया, जब विशेषकर वंचित तबके की महिलाएं ऐसी घोषणाओं के जाल में फंस जाती थीं। अब तो घर-घर में राशन-पानी पहुंचने लगा है, इसलिए वे इन घोषणाओं की हकीकत समझने लगी हैं। फिर, ऐसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को खूब नुकसान पहुंचाती हैं। चुनावी अभियान के दौरान नेताओं को निस्संदेह वायदे करने पड़ते हैं। उनको नई नौकरी पैदा करने, रोजगार देने या क्षमता बढ़ाने जैसे वायदों पर आगे बढ़ना चाहिए। मगर होता है उल्टा। वे फ्रीबीज संस्कृति को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिससे तरक्की का सही माहौल नहीं बन पाता और एक आलसी कार्यबल आकार लेने लगता है। घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाने से लोगों में राष्ट्र-निर्माण की भावना भी सिमटने लगती है। इसलिए, यदि वंचित तबकों की मदद ही करनी है, तो उनके लिए मुफ्त योजनाएं जरूर चलाई जाएं, पर एक सीमित समय के लिए। जब वे लोग मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, तब उनके लिए योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। आखिर राष्ट्र-निर्माण का फर्ज भी उनको निभाना है।

ऐसे में, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वह नए-नए वायदों के साथ मैदान में उतरे। लोगों को उससे उम्मीद है, इसलिए वह रेवड़ी संस्कृति का पोषण करने वाली पार्टी के रूप में सामने न आए, बल्कि एक ऐसा विकल्प बने, जिससे यह बोध हो कि वह तरक्की की हिमायती है। उम्मीद है, अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे और नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

उद्योग से रोजगार तक युद्ध का असर

युद्ध का जारी रहना स्थानीय उद्योग ही नहीं, देश-विदेश में रोजगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, तब भारत अछूता नहीं रहेगा। आर्थिक संकट कहां-कैसे बढ़ रहा है और इसे कैसे देख रहे हैं स्थानीय उद्यमी? पेश है जमीनी हकीकत की पड़ताल करती दो रिपोर्ट...

हम युद्ध से पहले कहां थे और अब कहां हैं?

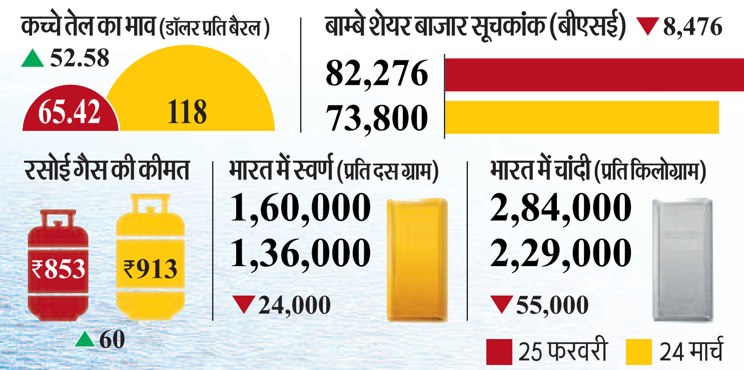

भारतीय उद्यमियों पर बढ़ने लगा दबाव

■ उदय सिंह

नोएडा। मैन्युफेक्चरिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले नोएडा या गौतमबुद्धनगर में ऊपरी तौर पर अभी युद्ध का असर नहीं दिख रहा है, पर उद्यमियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। स्थानीय उद्यमियों की मानें, तो अप्रैल महीने से युद्ध का असर साफ तौर पर दिखने लगेगा।

स्थानीय उद्यमी चिंता जताते हुए बताते हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से शिपमेंट के कंटेनर का किराया बढ़ गया है। इससे कच्चे माल की कीमतों में उछाल आया है। इससे यहां उत्पादन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। उद्यमियों को अब भाड़े या किराये के रूप में दोगुनी रकम चुकानी पड़ रही है।

विदेश से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर स्थानीय उद्यमियों के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक उछाल आया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरुमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिससे तेल टैंकरों से लेकर कंटेनर जहाजों तक की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इससे उद्यमियों की परेशानी बढ़ रही है। उद्यमियों को अपने माल का निर्यात महंगा पड़ रहा है।

अपैरल पार्क क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल बताते हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से शिपिंग कंपनियों के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जिससे परिवहन समय 12-15 दिन बढ़ गया है। इसी वजह से कंटेनर किराये में भारी उछाल आया है। उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले जहां कंटनेर का किराया 1,200 डॉलर (1.10 लाख रुपये) था, वहीं अब 2,400 डॉलर (2.20 लाख रुपये) प्रति कंटेनर तक पहुंच गया है। एशिया-यूरोप व अन्य मार्गों पर स्पॉट रेट में 30-50 प्रतिशत तक की तत्काल वृद्धि हो गई है, जबकि कुछ मामलों में यह 150 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पुराने मार्गों की जगह लंबे रूट अपनाने से ईंधन खर्च, बीमा प्रीमियम और अन्य लागतें बढ़ गई हैं।

फोटो : सोनू मेहता

94.01 रुपये तक पहुंचा अमेरिकी डॉलर का भाव। युद्ध के बाद दो प्रतिशत कमजोर हो गया।

4.6 तक पहुंच गई है महंगाई दर युद्ध की वजह से। एक महीने पहले यह महज 3.21 थी।

निर्यातकों के लिए बढ़ेगी चुनौती

प्लास्टिक ग्रैन्यूल, खाद्य तेल, रासायनिक कच्चा माल और अन्य औद्योगिक सामग्रियों की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसने भारतीय निर्यातकों के साथ ही, स्थानीय निर्यातकों की उत्पादन लागत को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के निर्यातक इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यहां से प्लास्टिक उत्पाद, टेक्सटाइल, ऑटो उपकरण और अन्य अनेक वस्तुओं का निर्यात होता है।

वस्त्र और मेवा पर असर

शहर के उद्यमियों द्वारा ईरान में परिधान, ऑटो पार्ट्स व चमड़े आदि का भी निर्यात किया जाता है। उद्यमी राजीव गोयल बताते हैं कि ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। हर महीने करोड़ों रुपये के परिधान का निर्यात किया जाता है। अब एकाएक ईरान पर हमला होने से निर्यात फंस गया है। डर सता रहा है कि पूर्व में आए ऑर्डर का भुगतान होगा या नहीं। निर्यात बाधित रहा, तो अनेक उद्योगों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष असर तय है।

कारोबारी रमेश गोयल बताते हैं कि सूखे मेवे का सबसे ज्यादा आयात ईरान से होता है। अब ईरान से सूखे मेवे के आयात होने की संभावना खत्म होने लगी है। अब दूसरे देशों से आयात करना होगा। ऐसे में, सूखे मेवे की कीमत बढ़ जाएगी।

वहीं आईआईए के कुलमणि गुप्ता के मुताबिक, किसी भी चीज का समुद्री मार्ग से निर्यात करना अब चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में, शिपमेंट देरी से पहुंचेगी। इसका नुकसान भी उद्यमियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शिपिंग लागत बढ़ेगी, तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी।

बड़े नुकसान की आशंका

दिल्ली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि ईरान और इजरायल के युद्ध के कारण पूरा खाड़ी क्षेत्र प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से जो जहाज खाड़ी देशों के क्षेत्र से होकर गुजरने वाले थे, वे भी हाई-सी एरिया में फंस गए हैं। चावल, अन्य कृषि उत्पाद, मशीनरी समेत निर्यात होने वाले तमाम उत्पाद कंटेनर में फंस गए हैं। इनमें बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं, जिनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका, तो भारत में अप्रैल से व्यापक असर दिखाई देने लगेगा। अगर उद्योगों में उत्पादन कम हुआ या मांग कम हुई, तो बड़ी संख्या में रोजगार, धंधे पर असर पड़ सकता है।

पेट्रोलियम पदार्थों के और महंगे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। इससे महंगाई को बल मिलेगा। अभी तक रोजमर्रा के समान की कीमतों पर असर नहीं पड़ा है, पर उद्यमियों को आशंका है कि अप्रैल से ज्यादातर उत्पादों पर कमोबेश असर दिखने लगेगा।

उद्यमियों की चिंता

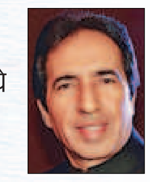
"होर्मुज मार्ग बंद होने से वैश्विक कंटेनर क्षमता का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, तो किराये में तेजी आएगी। भारतीय एमएसएमई इकाइयों के लिए यह बड़ा झटका है।"
-**ललित ठुकराल**, अध्यक्ष, अपैरल पार्क क्लस्टर

"केप रूट से जहाजों का समय बढ़ने से ग्राहकों को डिलिवरी में देरी हो रही है, जिससे ऑर्डर निरस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं कंटेनर किराया पिछले कुछ दिनों में दोगुने से ज्यादा हो गया है।"
-**सीपी शर्मा**, अध्यक्ष, हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन

"पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध के कारण वैश्विक समुद्री मार्गों में भारी अव्यवस्था पैदा हुई है, जिससे कंटेनर किराया, बीमा प्रीमियम और ट्रांजिट समय, तीनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत से मध्य-पूर्व जाने वाला कृषि और खाद्य निर्यात सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।"
-**राजीव बंसल**, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आईआईए, महासचिव, नोएडा एईसी

स्वदेश लौटते भारतीय और रोजगार की चिंता

■ अरुण चट्टा

नई दिल्ली। युद्ध का असर अब भारत के लाखों परिवारों में दिखाई पड़ सकता है। खासकर, उन लोगों पर ज्यादा असर दिख रहा है, जो खाड़ी देशों में काम करते हैं या वहां से लौट आए हैं या वहां जाने की तैयारी में हैं। अब उन सभी के सामने रोजगार का संकट खड़ा होता दिख रहा है।

अनुमान है, 3.75 लाख भारतीय खाड़ी देशों से लौट आए हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) यानी फारस की खाड़ी के छह अरब देशों (सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात) में कार्यरत हैं। भारतीय प्रति वर्ष अपने देश करीब चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजते हैं, जिससे देश के लाखों परिवारों का खर्च चलता है, लेकिन युद्ध की वजह से अब यह व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खाड़ी देशों में कई जगहों पर प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए हैं, जिनमें कार्यरत कामगारों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है या नए कामगारों को काम पर रखने की प्रक्रिया थम गई है। निर्माण, विनिर्माण, ट्रांसपोर्टेशन, तेल और सेवा क्षेत्र में काम करने वालों के सामने सबसे ज्यादा संकट है। युद्ध लंबा चलता है, तो कंपनियां लागत कम करने के लिए छंटनी व्यापक पैमाने पर शुरू कर सकती हैं। उधर, खाड़ी देशों में नई भर्ती भी कम हो रही है, जिससे भारत से वहां जाने वालों की संख्या घट सकती है।

खाड़ी देशों में युद्ध के बीच कम होते रोजगार के अवसर और छंटनी की आशंका के बीच जहां श्रमिकों के परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं, देश की आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी यह ठीक नहीं है। भारत के आयात बिल में लगभग 50,000 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि का अनुमान है।

खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीयों को निकाल लाने की कवायद जारी है।

5,500 से ज्यादा ऐसे एयर फ्लाइट रद्द हुई हैं, जो भारत और पश्चिम एशिया के बीच चलनी थीं।

4,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि भारतीय खाड़ी देशों से कमा कर स्वदेश भेजते हैं।

यूपी, बिहार में दिखेगा ज्यादा असर

उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य प्रदेशों पर सबसे अधिक असर दिखेगा। युद्ध लंबा चलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में, खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों पर रोजी-रोटी का संकट बढ़ेगा। खाड़ी देशों के बड़े हिस्से में निर्माण कार्य बंद हैं। होटल, रेस्तरां, शोरूम भी बंद हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। ऐसे में, उन सभी की नौकरी पर संकट है। जोखिम के बीच भारतीय वापस अपने देश लौटते हैं, तो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल जैसे राज्यों में असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में सेवारत हैं।

सऊदी अरब में डेकोरेशन का काम करने वाले बिजनौर, उत्तर प्रदेश निवासी आफताब आलम बताते हैं कि कुछ क्षेत्रों में काम प्रभावित हुआ है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में स्थिति अभी भी सामान्य है। अब अगर युद्ध लंबा चला, तो निश्चित तौर पर दुष्प्रभाव बढ़ेगा और अधिक संख्या में भारतीय श्रमिक अपने देश वापस लौटना चाहेंगे। हालांकि, अभी ज्यादा डरने जैसे हालात नहीं हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट की शुरुआत हो सकती है। मोटी धनराशि खर्च कर दुबई पहुंचे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। जबकि उन्होंने दुबई जाने के लिए एजेंटों को मोटी धनराशि दी थी। कुछ श्रमिक ऐसे हैं, जिन्हें वीजा मिल चुका है, जो टिकट भी खरीद चुके हैं, पर कंपनी ने उन्हें आने से रोक दिया है। ऐसे हजारों श्रमिक हैं।

अभी लौटने को मजबूर

विदेश मंत्रालय के अनुसार, युद्ध में छह भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। दुबई की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले भारतीय ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि जिस इमारत में हमारा ऑफिस है, वह बीते 20 दिन से बंद है। हम लोग यहां कई कंपनियों को आईटी सेवा देते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कंपनियां अभी बंद हैं। वैसे, अब कंपनी ने कुछ लोगों को छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया है।

अमन का इंतजार

अमरोहा निवासी सोहेल कहते हैं कि मेरे साथ आठ अन्य लोगों को कतर जाना है। युद्ध से पहले ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन एन वक्त पर उस कंपनी ने मना कर दिया। अब कंपनी का कहना है कि जब स्थिति सामान्य होगी, तब वह बुलाएगी। मतलब, अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। धन की प्राप्ति होगी।

वृष : धैर्यशीलता में कमी तो रहेगी। परंतु वाणी में सौम्यता भी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन भी बन सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

मिथुन : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी बहुत रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी।

कर्क : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान मिल सकता है।

कन्या : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मीठे खानपान में रुचि बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। संयत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पारिवारिक संपत्ति से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आय के साधन बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। पिता का साथ मिलेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

25 मार्च, बुधवार, 2026, **शक संवत्** : 04 चैत्र (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 12 चैत्र मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 05 शव्वाल, 1447, **विक्रमी संवत्** : चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि दोपहर 01.51 मिनट तक पश्चात अष्टमी। सौभाग्य योग रात्रि 03.10 मिनट तक पश्चात शोभन योग, वणिज करण, चन्द्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। **सूर्य उत्तरायण**। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 01.51 मिनट से रात्रि 12.50 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमने एक नया फ्लैट लिया है। इसकी सेटिंग में हमें कुछ समस्या आ रही है। यदि इसका कोई वास्तु उपाय हो, तो कृपया बताएं। -प्रफुल्ल कुमार, नोएडा

■ आपका फ्लैट लगभग उत्तर मुखी है, मुख्य द्वार के बगल में ही एक छोटा स्थान है। यहां पर आप अपना पूजा स्थान बना सकती हैं। किंतु इसके ठीक सामने ही दक्षिण दिशा में आपका टॉयलेट भी आ रहा है। पूजा स्थल के एकदम सामने टॉयलेट आ रहा है। इसके लिए आप एक पार्टीशन कहीं भी बीच में कर दें। चूंकि ये दोनों चीजें सामने-सामने होना ठीक नहीं होता, जूते-चप्पल वाला रैक आप वायव्य की ओर रख दें। डाइनिंग टेबल रखते समय ध्यान रखें, ये सेंटर में न हो। इसे थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर रखें।

वर्ग पहेली : 8278

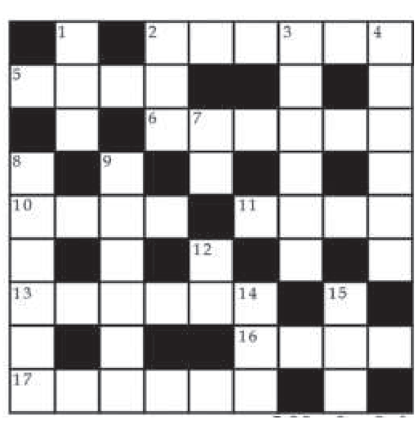

बाएं से दाएं
2. कठिन कोशिश; सख्त मेहनत (3,3)
5. अपकीर्ति; कलंक; कुख्याति; लोकनिंदा (4)
6. लोकसमर्थन; जनता का समर्थन (6)
10. कांपना; डरना (4)
11. अनेक बार; फिर फिर; पुनः पुनः (2,2)
13. घबरा जाना; भ्रमित हो जाना; हिचकना; चौंक जाना; भौचक रह जाना (4,2)
16. तोड़ना; अलग करना; दूर करना; चिढ़ाना (4)
17. अत्यधिकता होना; वस्तु की अधिक मात्रा में उपलब्धि होना; लाभ होना; समृद्धि होना (4,2)

ऊपर से नीचे
1. केंद्रीय; मुख्य; प्रधान; सभापति (3)
2. धड़ पर पहनने का पुरुषों का वस्त्र (3)
3. अभिवादन करना; नमस्कार करना; विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ना (3,3)
4. इज्जत करना; आदर करना; मान देना (3,3)
7. पर्वत; नगीना; मणि; रत्न (2)
8. वस्तु; सामान; संपत्ति (2,4)
9. दूसरे स्थान पर आए प्रतियोगी को मिलने वाला पदक; चांदी का तमगा (3,3)
12. अधिपति; नरेंद्र; नृप; भूपाल; प्रशासक; धनी; प्रिय; स्वामी (2)
14. नृत्य करना; खुशी के मारे झूमना; उछलना कूदना; प्रफुल्लित होना (3)
15. रूप; आकृति; डील डौल; कद (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8277

सुडोकू : 8260

* कठिन

				9				
8	3						6	2
5	2						4	9
2			6		8			3
9			3		5			6
4	8						3	7
6	1						8	5
				6				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8259

8	9	5	3	1	2	6	4	7
3	7	4	8	6	5	9	2	1
2	1	6	4	7	9	5	8	3
5	2	9	7	8	6	3	1	4
7	6	1	5	3	4	8	9	2
4	3	8	9	2	1	7	5	6
9	8	2	6	4	3	1	7	5
6	4	7	1	5	8	2	3	9
1	5	3	2	9	7	4	6	8

न्यूनतम राशि-एसएमएस के नाम पर बैंक वसूल रहे मोटा जुर्माना

विशेष

अरुण चड्ढा

नई दिल्ली। बैंकों द्वारा शुल्क के नाम पर ग्राहकों से सालाना मोटी रकम वसूली जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते पांच वर्षों के दौरान देश भर में साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एसएमएस और न्यूनतम बैलेंस न होने पर बैंकों ने ग्राहकों की खातों में जमा धनराशि से काटी है।

जबकि एटीएम चार्ज के तौर पर भी 26 करोड़ की धनराशि वसूली गई है।

आंकड़ों से पता चलता हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के बीच बैंकों ने न्यूनतम शुल्क के तौर पर साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वसूली है। यह धनराशि उन खातों से वसूली की है जिनमें बैंक द्वारा तय सीमा से कम धनराशि उपलब्ध थी। न्यूनतम बैलेंस न होने के मामले पर शुल्क काटे जाने पर निजी बैंकों द्वारा सबसे ज्यादा शुल्क वसूला गया है। इसके बाद एटीएम चार्ज के तौर पर करीब 2600 करोड़ और एसएमएस चार्ज के तौर पर 5700 करोड़ से अधिक की धनराशि ग्राहकों के खाते से काटी गई है। इसमें एटीएम चार्ज उन खातों से काटा गया, जिन्होंने एक महीने में निर्धारित सीमा से अधिक बार एटीएम से धनराशि निकाली। इससे पता चलता है कि ग्राहकों से जुड़ी सेवाओं पर लगाए जा रहे शुल्कों के तौर पर अपना राजस्व संग्रह बढ़ा रहे हैं।

पांच सालों में बैंकों द्वारा लिया गया शुल्क (करोड़ में)

वित्त वर्ष	न्यूनतम बैलेंस	एटीएम	एसएमएस
2020-21	1637.41	-416.68	1044.32
2021-2	1805.75	-507.49	1282.03
2022-23	2294.68	-451.46	1193.19
2023-24	2909.10	-594.12	977.28
2024-25	2889.05	-647.32	1218.60

■ नोट : एटीएम चार्ज में इंटरचेंज फीस आदि का समायोजन शामिल है। इसलिए एटीएम शुल्क को हटाने के बाद बैंकों ने शुद्ध तौर पर 14634 करोड़ रुपये वसूले हैं।

क्या कहती है सरकार

बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक और निजी बैंक न्यूनतम बैलेंस न रखने, एटीएम से ज्यादा निकासी और एसएमएस अलर्ट जैसी सेवाओं पर शुल्क लेते हैं। हालांकि यह सभी चार्ज भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत तय किए जाते हैं और इन्हें पारदर्शी व उचित होना जरूरी है। सरकार के अनुसार बैंक अपने बोर्ड द्वारा तय नीतियों के आधार पर चार्ज लेते हैं।

हर साल 1.2 लाख करोड़ की कर्ज माफी

एक तरफ छोटे ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर बैंक खाते से शुल्क काटा जा रहा है। दूसरी तरफ, आंकड़े बताते हैं कि भारत में बैंकों द्वारा करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हर वर्ष माफ या डूबा हुआ माना जा रहा है। बीते पांच वर्षों के दौरान करीब 6.15 लाख करोड़ रुपये का राइट ऑफ किया गया। यानी ऐसा कर्ज जिसकी वसूली करनी मुश्किल होती है या फिर कर्ज अदा करने वाली कोई व्यक्ति सक्षम नहीं था तो उसे गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में डाला।

ग्राहक ऐसे बचा सकते हैं यह शुल्क

मौजूदा समय में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते पर कोई शुल्क न्यूनतम शुल्क नहीं लगता है। जनधन खाता हर किसी व्यक्ति का नहीं खुलता है लेकिन बीएसबीडीए, जिसे बुनियादी बचत बैंक जमा खाता भी कहा जाता है, उसे कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। हालांकि इसी लेनदेन और सालाना जमा की सीमा निर्धारित है। जैसे आप महीने में केवल चार बार ही पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद चार्ज लगेगा।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स			निफ्टी		
74,068 +1372.06			22,912 +399.75		
टॉप गेनर			**टॉप गेनर**		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%	कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एलटी	3515.35	5.19	इंडिगो	4162.00	5.49
इंडिगो	4151.15	5.18	एलटी	3515.10	5.17
टॉप लूजर			**टॉप लूजर**		
पावरग्रिड	299.20	-0.81	कोल इंडिया	441.60	-3.00
सनफार्मा	1752.80	-0.20	पावरग्रिड	298.00	-1.36

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,44,000	+1,200
चांदी	2,30,000	स्थिर

करेंसी
डॉलर/रुपया
93.76 -0.23

बैंक ग्राहकों की अधिक जानकारियां जुटाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने आयकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब खाताधारकों से पहले से ज्यादा जानकारी जुटानी होगी।

यह कदम टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। नए नियमों का असर आम खाताधारकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी पर पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, अब बैंकों को खाताधारकों से यह जानकारी भी लेनी होगी कि खाता एकल है या संयुक्त, खाते में कितने लोग जुड़े हैं, खाता नया है या पुराना है और अगर खाता किसी कंपनी या संस्था के नाम पर है तो उसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है।

यानी अब बैंक यह भी पता लगाएंगे कि किसी कंपनी या संस्था के पीछे असली मालिक कौन है। इसके अलावा बैंकों को अब खाताधारकों से टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर (टिन), जन्म तिथि और अन्य जरूरी जानकारी भी लेनी होगी। खासकर पुराने खातों को अपडेट करते समय यह जानकारी अनिवार्य होगी। यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े कानूनों के तहत भी जरूरी माना जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से खातों से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। खाताधारक को बताए बिना उसके खाते में लेन-देन हो रहा है। अब इस कदम से सख्ती बढ़ेगी।

शेयर-म्यूचुअल फंड से हुई आय बतानी होगी

अब वित्तीय संस्थानों को यह भी रिपोर्ट करना होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय संपत्ति बेची है तो उससे कितनी राशि मिली। अगर बैंक या वित्तीय संस्था ब्रोकर या कस्टोडियन की भूमिका में है, तो उसे यह जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। इनका सबसे ज्यादा असर उच्च आय वर्ग के लोगों पर पर पड़ेगा। पहले बैंक केवल यह बताते थे कि खाते को कौन नियंत्रित करता है, लेकिन अब यह भी बताना होगा कि नियंत्रण किस तरह का है। इससे ऑफशोर कंपनियों, ट्रस्ट और फैमिली ऑफिस जैसी जटिल निवेश संरचनाओं की जानकारी भी सामने आ सकती है।

क्रिप्टो और डिजिटल संपत्ति का खुलासा : नए नियमों में क्रिप्टोकरंसी और डिजिटल संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। यानी अब क्रिप्टो निवेश की जानकारी भी सरकार तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर क्रिप्टो लेनदेन पहले से किसी अन्य रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत दर्ज हो रहे हैं, तो उन्हें दोबारा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी।

इसलिए किया गया बदलाव : सरकार ने यह बदलाव इसलिए किए हैं, क्योंकि दुनिया भर में टैक्स पारदर्शिता के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम और साझा वित्तीय जानकारी रिपोर्टिंग मानक जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत देश एक-दूसरे के साथ वित्तीय जानकारी साझा करते हैं ताकि कोई व्यक्ति विदेश में पैसा छिपाकर टैक्स चोरी न कर सके।

ट्रंप के बयान से बाजार में तेज उछाल

मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौटी और मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1,372 अंक उछल गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 400 अंक की बढ़त रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की योजना को अस्थायी रूप से टाले जाने की घोषणा के बाद एशिया के अन्य बाजारों में तेजी के साथ घरेलू बाजार बढ़त में रहे।

सेंसेक्स 1,372.06 अंक चढ़कर 74,068.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 1,793 अंक तक चढ़ गया था। निफ्टी 399.75 अंक की बढ़त के साथ 22,912.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, इटर्नल, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख रूप से लाभ में रहीं।

जानकारों ने कहा, भारतीय शेयर बाजारों में सकारात्मक उछाल देखने को मिला। पिछले सत्र की भारी बिकवाली के बाद बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। यह उछाल मुख्य रूप से जोखिम धारणा में नरमी के कारण हुआ। अमेरिका-ईरान तनाव में संभावित कमी के शुरुआती संकेतों ने निवेशकों का कुछ भरोसा बहाल करने में मदद की है।

शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की संपत्ति 7.56 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4,22,78,312.77 करोड़ रुपये (4,500 अरब डॉलर) हो गई।

रुपया 93.76 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 23 पैसे लुढ़ककर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण निवेशकों में चिंता का माहौल रहने से घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों की निकासी ने भी रुपये पर दबाव डाला।

स्विगी ने भी बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क

नई दिल्ली। प्रमुख ऑनलाइन मंच स्विगी ने ग्राहकों से लिए जाने वाले 'प्लेटफॉर्म शुल्क' में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 17.58 रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क देना होगा। स्विगी ने यह कदम अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी जोमैटो द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उठाया है। स्विगी के ऐप पर मंगलवार को दिख रहे शुल्कों के अनुसार, अब प्रति ऑर्डर 17.58 रुपये (जीएसटी सहित) लिए जा रहे हैं।

सोना 1,200 चढ़कर 1.44 लाख पर पहुंचा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में चार दिन से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया और इसके भाव 1,200 रुपये बढ़कर 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी की कीमतें 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी रहीं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है।

अदाणी की बोली पर अंतरिम रोक से इनकार

नई दिल्ली। एनसीएलएटी ने मंगलवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अदाणी समूह की 14,535 करोड़ रुपये की बोली पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। वेदांता समूह ने एनसीएलटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदाणी की बोली को मंजूरी दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

एसबीआई ने चुनिंदा एफडी पर ब्याज की दरों में इजाफा किया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ खास समय-सीमा वाली एफडी यानी सावधि जमा की ब्याज दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। बदली हुई ब्याज दरें 15 मार्च, 2026 से लागू हो गई हैं।

बैंक ने 46 दिनों से 179 दिनों के बीच परिपक्व होने वाले जमा के लिए, ब्याज दर 5.10% से बढ़ाकर 5.35% कर दी है। 180 दिनों से एक साल से कम समय-सीमा के लिए, दर 5.60% से बढ़ाकर 5.85% कर दी है, जबकि एक साल से दो साल से कम समय-सीमा वाले जमा के लिए, दर 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दी है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 46 से 179 दिनों के बीच वाले जमा के मामले में, दर 5.60% से बढ़ाकर 5.85% कर दी है। 180 दिनों से एक साल से कम समय के लिए यह दर 6.10% से बढ़ाकर 6.35% कर दी गई है। वहीं एक साल से दो साल से कम समय के लिए परिपक्वता वाले जमा के लिए दर 6.75% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है।

बैंक वे कहा कि बदली हुई ब्याज दरें नए जमा और पुराने परिपक्व हो रहे जमा को रिन्यू कराने पर लागू होंगे।

यूएई से सोना आयात लाइसेंस की वैधता बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशियाई संकट के बीच सरकार ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कोटा आधारित शुल्क रियायत पर सोने के आयात के लिए जारी लाइसेंस की वैधता तीन जून तक बढ़ा दी है।

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत, भारत ने शुल्क दर कोटा के तहत सोने के आयात पर कोटा-आधारित शुल्क रियायतें दी हैं। नोटिस में कहा गया, भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने के आयात के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में जारी वैधता को तीन महीने यानी 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

फिंगरप्रिंट या चेहरा दिखा कर भुगतान संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने डिजिटल भुगतान को और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ता भीम ऐप के जरिए ₹5,000 तक यूपीआई लेन-देन बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान कराकर कर सकेंगे।

इस नई सुविधा को यूपीआई भुगतान के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन के तहत लागू किया गया है।

इस पहल का मकसद उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो अक्सर यूपीआई का पिन भूल जाते हैं या गलत पिन डालने की वजह से लेन-देन असफल हो जाता है। अब ऐसे मामलों में भुगतान प्रक्रिया ज्यादा सहज और भरोसेमंद हो जाएगी। यह फीचर खास तौर पर रोजमर्रा के लेनदेन—जैसे दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करने, ऑनलाइन खरीदारी करने या दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने में काफी उपयोगी साबित होगा।

■ अब उपभोक्ता को भीम ऐप के जरिए ₹5,000 तक यूपीआई लेन-देन पर कोई पिन नहीं डालना पड़ेगा

बायोमीट्रिक सत्यापन एक ऐसी तकनीक है, जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके फिंगरप्रिंट या चेहरे के जरिए की जाती है। इससे न केवल भुगतान तेज होगा, बल्कि सुरक्षा भी मजबूत रहेगी क्योंकि हर व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा अलग होते हैं।

गिफ्ट कार्ड से फंड में निवेश पर विचार

नई दिल्ली, एजेंसी। सेबी ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट प्रीपेड भुगतान कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

सेबी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इसके तहत, गिफ्ट पीपीआई का खरीदार इसे किसी प्राप्तकर्ता को उपहार में दे सकता है, जो इसका उपयोग म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए कर सकता है।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

क्रमांक :– अ.अ/पीएचई/2025–26/21131615 दिनांक : 18.03.2026

:: ई–बिड सूचना संख्या:– जोन पीएचई/20/2025–26 दिनांक 18.03.2026

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से सीवरेज के कार्य हेतु संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। इन उक्त कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्ते आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE :- JOD2526A0276
Tender ID/UBN No. :- (JOD2526WSOB00599)
राज.संवाद/सी/25/23164 अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) CIN- U40109UR2001SGC025867
कार्यालयः अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल (नगरीय) न्यू फोरेस्ट, एफ०आर०आई० कैम्पस, देहरादून।
Email: seedcurban@gmail.com Website: www.upcl.org

ई–निविदा विस्तार सूचना

विद्युत वितरण मण्डल (नगरीय) देहरादून के अन्तर्गत ई–निविदा संख्या 53/वि0वि0म0(न0)/2025–26 को दिनांक **31.03.2026** तक अपरिहार्य कारणों से विस्तारित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु बेबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर देखें।

पत्रांकः 3440/वि0वि0म0(नगरीय)/दे0दून दिनांकः 24/03/2026 **अधीक्षण अभियन्ता**
"राष्ट्र हित में बिजली बचायें" टोल फ्री नं0 1800–419–0405

मध्य रेल
ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना क्रमांक. NIT/01/26/14 दिनांक 20 मार्च 2026

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, मध्य रेलवे निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

क्र.	निविदा क्र.	विवरण	मात्रा	नियत तिथि
1	42251270	16" इलेक्ट्रो-न्यूमैटिक ब्रेक यूनिट	53 नग	06 अप्रैल 26
2	43261079	110V ब्रुशलेस DC पंखा, फिक्स्ड टाइप, 400 mm	4916 नग	10 अप्रैल 26
3	36365003	जोड़-रहित खांचेदार तांबे का संपर्क तार 193 वर्ग मिमी	52.5 किमी	13 अप्रैल 26
4	27261331	LED -आधारित लोकोमोटिव चेतावनी बत्ती	255 सेट	06 अप्रैल 26
5	51256065	एचवीएन लाइनर्स के लिए रनिंग कॉन्ट्रैक्ट 1) T-8751-9000000 नग 2) T-3706-8000000 नग 3) T-8752/53-400000 नग 4) End cut T-3706-100000 नग		27 अप्रैल 26
6	51256055	60 Kg (UIC) रेल के लिए Thick web Switch expansion joint हेतु Prestressed Concrete Sleepers के निर्माण और आपूर्ति, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट RDSO Drg. No. RDSO/T-8838	2500 set	04 मई 26
7	51266074	रनिंग कॉन्ट्रैक्ट - HVN LINERS 6938/39 और 8992 के लिए चालू अनुबंध 2) T-6938- 200000 नग 3) T-8992-20,00000 नग	HVN LINERS 6938/39 और 8992	06 अप्रैल 26
8	51256060	रनिंग कॉन्ट्रैक्ट - 60 किग्रा/60E1 (R-260 ग्रेड) रेलों के फ्यूज़न वेल्डिंग हेतु वेल्डिंग पोर्शन के निर्माण एवं आपूर्ति	60,000 नग	15 अप्रैल 26

नोट : उपरोक्त सभी निविदाएं ई-निविदाएं हैं और सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियां IREPS वेबसाइट www.ireps.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। उपर्युक्त निविदाओं और अन्य आपूर्ति निविदाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया IREPS वेबसाइट पर जाएं।

रेल्वे फाटक को बंद स्थिति में पार करना मना है 1015

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम)
(पुणे मेट्रो रेल परियोजना – फेज ।।)
चौथी मंजिल, मेट्रो भवन, जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन परिसर, न्यायमूर्ति रानाडे पथ, शिवाजीनगर, पुणे–411005,
ई–मेल: tenders.pmrp@mahametro.org
वेबसाईट : www.punemetrorail.org दूरभाष: 020-26051074

ई–निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या : P2-Misc 02/2026 (NCB) दिनांक : 25/03/2026
कार्य का विवरण : पुणे मेट्रो परियोजना में फेज 1 विस्तार और फेज 2 के लिए पीएमसी / पीसीएमसी सीमा के भीतर 41000 वृक्षारोपण और सात (07) वर्षों तक रखरखाव हेतु ठेकेदार की नियुक्ति।
निविदा **03/04/2026 रोज 16:00 बजे से 27/04/2026 रोज 11:00 बजे तक** उपलब्ध है।

निविदा सूचना संख्या : P2-PC 01/2026 (NCB) दिनांक : 25/03/2026
कार्य का विवरण : पुणे मेट्रो रेल परियोजना, फेज–2 की लाइन 2A, 2B, 4, 4A और 4B की मेट्रो और डबल डेकर वायडक्ट्स के विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रूफ चेकिंग (पीसी)।
निविदा **02/04/2026 रोज 16:00 बजे से 23/04/2026 रोज 11:00 बजे तक** उपलब्ध है।

निविदा सूचना संख्या : P2-Misc-01/2026 (NCB) दिनांक : 25/03/2026
कार्य का विवरण : पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज–2 के लिए पीएमसी और पीसीएमसी क्षेत्र के भीतर नए भवनों का निर्माण, भूमिगत प्रवेश–निकास और सबवे, मौजूदा भवनों का वर्टिकल एक्सटेंशन, सड़कें, औद्योगिक शेड, और आर्किटेक्चरल फिनिशिंग कार्य, सिविल और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का स्थानांतरण, पुरानी इमारतों को ध्वस्त करना / तोड़ना / मरम्मत करना, सीमा दीवारें, भूमिगत जल टैंक, पीईबी संरचनाएं/दुकानें, बागवानी और भूनिर्माण कार्य, कार्यालयों/दुकानों का विकास आदि जैसे विविध कार्य।
निविदा **27/03/2026 रोज 16:00 बजे से 20/04/2026 रोज 11:00 बजे तक** उपलब्ध है।

ऊपर दिए गए सभी टेंडरों के लिए, इच्छुक बोली लगाने वाले पुणे मेट्रो रेल की वेबसाइट www.punemetrorail.org तथा सीपीपीपी पोर्टल https://eprocure.gov.in पर भेंट करें। निविदा दस्तऐवज डाउनलोड करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के ई-टेंडर पोर्टल https://mahatenders.gov.in पर जाएँ और जानकारी प्राप्त करें।
कार्यकारी निदेशक/खरीद एवं अनुबंध
महा मेट्रो, हरित मेट्रो — महा–मेट्रो, पीएमआरपी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्या :- 12 /18/विज्ञापन अनुभाग/2016/16-(04)/2016
लखनऊः दिनांक-23 मार्च, 2026

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या-16(4)/2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री/डिप्लोमा अर्हता धारक हेतु अनुदेशक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के 03 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिये अर्ह/औपबंधिक अर्ह कुल 34 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार **दिनांक 28.03.2026,** को **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ** में आयोजित किया जाना निर्धारित है। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या-**42/06/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह) /2023-26/16(4)/2016 दिनांक 18 मार्च 2026** द्वारा साक्षात्कार पत्र व अन्य सम्बन्धित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये है।

तदनुक्रम में साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

UP 248897 Dt. 24.03.2026
Website: www.upgov.nic.in

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सोन नहर प्रमण्डल, आरा
पत्रांक –741

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01 एस०बी०डी०/2025–26
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट **www.eproc2.bihar.gov.in** पर)

1. कार्य का विवरण –

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (लाख रू0 में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल/मैनुअल मोड में भुगतेय)	परिमाण–विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू0	बेलट्रॉन को देय "बीड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतेय)रू0	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01.	असनी वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर गाद सफाई एवं तटबंध मरम्मति तथा HR, फॉल, फॉल सह पुल एवं विभिन्न बिन्दुओं पर अवस्थित पुल, पुलिया का मरम्मति एवं सुरक्षात्मक कार्य, धनुपरा वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर गाद सफाई एवं तटबंध मरम्मतिएवं एक अदद् आउटलेट का नवीकरण कार्य, आरा मुख्य नहर के 68.73 कि0मी0 से 84.05 कि0मी0 के विभिन्न बिन्दुओं पर गाद सफाई एवं बांध मरम्मति कार्य, RPC-B के HR पर मरम्मति कार्य आउटलेट निर्माण कार्य एवं मिट्टी कार्य, डिलियानरायणपुर वितरणी में सुरक्षात्मक कार्य एवं आउटलेट निर्माण कार्य, आरा मुख्य नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर बांध मरम्मति एवं गाद सफाई कार्य, कुम्हरी नहर विभिन्न बिन्दुओं पर बांध मरम्मति एवं गाद सफाई तथा आउटलेट निर्माण कार्य, पनवारी वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर सुरक्षात्मक दीवार निर्माण एवं मरम्मति कार्य, आरा मुख्य के 21.724 कि0मी0 से 30.554 कि0मी0 के बीच विभिन्न बिन्दुओं पर G.E.O Bag विचिंग, बांध मरम्मति एवं सुरक्षात्मक दीवाल का निर्माण कार्य, सकला वितरणी के 0.00 कि0मी0 से 15.00 कि0मी0 तक आउटलेट निर्माण एवं गाद सफाई कार्य, कटैया वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर G.E.O Bag से बांध मरम्मति एवं सुरक्षात्मक दीवाल का निर्माण कार्य, गड़हनी उपवितरणी के G.E.O Bag से बांध मरम्मति एवं सुरक्षात्मक दीवाल का निर्माण कार्य, B.B.C G.E.O Bag G.E.O Bag से बांध मरम्मति एवं सुरक्षात्मक दीवाल का निर्माण कार्य, केशरी डिस्ट्रीब्यूटरी के 4.7 कि0मी0 पर सुरक्षात्मक दीवार सी0सी0 ब्लॉक एवं 1200 मी0मी0 व्यास का साईफन निर्माण कार्य एवं गाद सफाई कार्य विभिन्न बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त आउटलेट का निर्माण कार्य, तार वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर 10 अदद आउटलेट निर्माण कार्य 4 अदद क्षतिग्रस्त फेस वाल का निर्माण कार्य एवं 2 अदद साईफन के बेड में पी0सी0सी0 कार्य, LPC-B के विभिन्न बिन्दुओं पर बांध मरम्मति एवं गाद सफाई कार्य, अमौना वितरणी के 0.00 कि0मी0 से 04.50 कि0मी0 के बीच बांध मरम्मति एवं गाद सफाई एवं सुरक्षात्क दीवार निर्माण कार्य, कोरी उपवितरणी के 0.00 कि0मी0 एच0आर0 के पास मरम्मति कार्य, LPC-D के विभिन्न बिन्दुओं परबांध मरम्मति एवं गाद सफाई कार्य, चौराई उपवितरणी के विभिन्न बिन्दुओं परबांध मरम्मति एवं गाद सफाई कार्य, बिछियांव उपवितरणी के विभिन्न बिन्दुओं परबांध मरम्मति एवं गाद सफाई कार्य, बेलाउर उपवितरणी में एक अदद् आउटलेट का नवीकरण कार्य, हेतमपुर वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर आउटलेट का निर्माण कार्य, R.P.C-3 के विभिन्न बिन्दुओं पर 3 अदद आउटलेट निर्माण कार्य एवं 2 अदद फेस वाल का निर्माण कार्य एवं R.P.C-4 के विभिन्न बिन्दुओं पर 2 अदद आउटलेट निर्माण कार्य।	700.23	14,00,500.00	10000	5,900.00	30 मई 2026

2	विज्ञापन दाता का नाम	:	कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा
3	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	:	दिनांक – 20.03.2026
4	निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि	:	दिनांक 06.04.2026 से दिनांक 10.04.2026 के 3 बजे अपराहन तक (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5	प्री–बीड मीटिंग का समय स्थान एवं तिथि	:	दिनांक 08.04.2026 को 03.00 बजे अपराहन में मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के कार्यालय कक्ष में
6	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 10.04.2026 के अपराह्न 03.30 बजे (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
7	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर घोषित की जायेगी।
8	निविदा खोलने का स्थान	:	केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
9	निविदा की वैद्यता अवधि	:	निविदा प्राप्ति के 120 दिन बाद तक।
10	विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु	:	वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in www.wrd.bih.nic.in / www.state.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
सोन नहर प्रमण्डल, आरा
मो0 – 7463889367

PR. No. 027141 (WRD) 2025-26

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

गाजियाबाद नगर निगम
(I.S.O. 14001, 18001 एवं 19001 प्रमाणित संस्था)
पत्रांक–338/नजारत विभाग/2025–26 दिनांक–23.03.2026

ई–निविदा आंमत्रण सूचना

गाजियाबाद नगर निगम के नगर निगम मुख्यालय में नयी लिफ्ट (लिफ्ट नं0–02) लगाये जाने के कार्य के साथ–साथ उसका 02 वर्षों के रख–रखाव के कार्य हेतु ई–निविदा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.03.26 से दिनांक 16.04.26 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित है। उक्त कार्य की तकनीकी निविदाएं दिनांक 17.04.26 को अपरान्ह 4:00 बजे खोला जायेगा। प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क (Tender Fees Non Refundable) वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर जमा करना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के समय धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी, जोकि लेखाधिकारी, गाजियाबाद नगर निगम के नाम पर बन्धक होगी। निविदा में प्रतिभागी फर्म योग्य होने पर वित्तीय निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश रहता है, तो निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जायेगी। विस्तृत शेष नियम व शर्ते एवं सूचना वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है।
प्रभारी नजारत
गाजियाबाद नगर निगम

उत्तर रेलवे
ई–निविदा सूचना संख्या TS265001

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य अभियंता/टीएसपी, उत्तर रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली–110001 ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित निविदा आमंत्रित करते हैं:

क्रम सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	निविदा दस्तावेज की कीमत (रुपये में)	बयाना राशि (रुपये में)	अनुमानित निविदा मूल्य (रुपये में)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	समापन की अवधि
1	TS265001	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में डायवर्जिंग लाइन पर 45 किमी प्रति घंटे की संभावित गति के लिए उपयुक्त 1 इन 12 कैंटेड टर्नआउट का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और फील्ड ट्रायल।	कुछ नहीं	15,25,980/-	7,62,98,800/-	24.04.2026 को 14:30 बजे	15 माह

नोटः– उपरोक्त ई–प्रोक्योरमेंट टेंडर की संपूर्ण जानकारी **"www.ireps.gov.in"** वेबसाइट पर उपलब्ध है।
संख्याः TS265001 दिनांकः 24.03.2026 **998/2026**
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

युद्ध समस्याओं से भागने का केवल एक कायरतापूर्ण तरीका है। - थॉमस मान

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन पेश कैग की रिपोर्ट पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं पर सवाल खड़े करती है। यह दुखद ही है कि ऐसी रिपोर्टें राजनीतिक विवादों के दलदल में फंस जाती हैं, जबकि इन्हीं मामलों में तो लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा होती है।

रिपोर्ट और सवाल

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल पर गंभीर सवाल तो खड़े करती ही है, इससे जवाबदेही व पारदर्शिता के मुद्दे एक बार फिर राजधानी की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास के नवीनीकरण पर अनुमानित लागत से 342 फीसदी अधिक खर्च हुआ और इसमें भी आधे से अधिक खर्च महंगी सजावटी वस्तुओं पर किया गया। इसके अतिरिक्त, काम शुरू होने के बाद मंजूरी लेने और टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। इसी रिपोर्ट में 2016-22 के बीच दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी, औषधियों व उपकरणों की भारी अनुपलब्धता, अधूरी परियोजनाओं व फंड के दुरुपयोग का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट के साथ ही पेश की गई लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी 'आप' सरकार की आबकारी नीति से 2021-22 में हुए भारी वित्तीय नुकसान की ओर इशारा करती है। आम आदमी पार्टी शुद्ध व नैतिक किस्म की राजनीति के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन शासन की प्राथमिकताओं, वित्तीय अनुशासन और जनहित को लेकर प्रतिबद्धता को ताक पर रखते ये मुद्दे, जिनकी ओर कैग व संसदीय समिति की रिपोर्टें इशारा कर रही हैं, कुछ और ही कहानी कहते दिख रहे हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि विपक्ष (आप) ने सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार का रास्ता चुनकर आरोपों का सामना करने के बजाय टकराव का रास्ता चुना है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जवाब देना और तथ्यों के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना भी है। कोरे बहिष्कार से न तो सवालों के जवाब मिलते हैं, और न ही जनता का भरोसा मजबूत होता है। ध्यान देने वाली बात है कि कैग एक सांविधानिक संस्था है, जिसकी रिपोर्ट सरकारों के वित्तीय कामकाज का निष्पक्ष आकलन करती है।

इसलिए, इन रिपोर्टों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ तभी वे आत्मसुधार की प्रेरणा बन सकती हैं। अगर विपक्ष रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, तब भी सदन से पलायन के बजाय उसे तथ्यों व साक्ष्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कैग की रिपोर्ट कल अपना दूसरा बजट पेश कर चुकी दिल्ली की वर्तमान सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को सरकारी खर्च में अनुशासन बरतने की सीख देती है। यह दुखद ही है कि ऐसी रिपोर्टें राजनीतिक विवादों के दलदल में फंस जाती हैं, जबकि इन्हीं मामलों में तो लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा होती है।

युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं

अमेरिका व इस्राइल का ईरान पर हमला सही हो या गलत, लेकिन यह तय है कि ये दोनों ही देश युद्ध के उन बुनियादी नियमों का पालन करते नहीं दिखे, जिनके बगैर कोई भी लड़ाई निर्णायक तौर पर जीती नहीं जा सकती।

ईरान के खिलाफ इस युद्ध को लेकर मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं रही हैं। हालांकि, तेहरान में एक अच्छी सरकार के सत्ता में आने से ज्यादा पश्चिम एशिया के हालात को सुधारने वाली कोई और चीज नहीं हो सकती, लेकिन मुझे संदेह है कि सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को तबाह करके यह बदलाव लाया जा सकता है। काश! राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई भी कदम उठाने से पहले, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बजाय किसी और से भी सलाह-मशविरा किया होता। मैं उन कुछ नियमों को साझा करके अपनी बात ठीक से समझा सकता हूं, जिन्होंने लंबे समय से इस क्षेत्र को कवर करने में मेरा मार्गदर्शन किया है।

■ दुश्मन यों हमेशा के लिए खत्म नहीं होते

किसी भी सैन्य खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका है- बल और राजनीति का मेल, यानी दूसरी तरफ एक बेहतर और आत्मनिर्भर नेतृत्व तैयार करना। यह काम बेहद पेचीदा है और इसमें हमेशा राजनीतिक समझौते करने की जरूरत पड़ती है। किसी को मार कर हमेशा के लिए समस्या खत्म की जा सकती है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। मैंने देखा है कि इस्राइल ने अपने ठीक पड़ोस, गाजा में हमास के पूरे नेतृत्व को एक नहीं, बल्कि तीन बार मार गिराया है; इसके बावजूद वह वहां से हमास के नियंत्रण को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाया है।

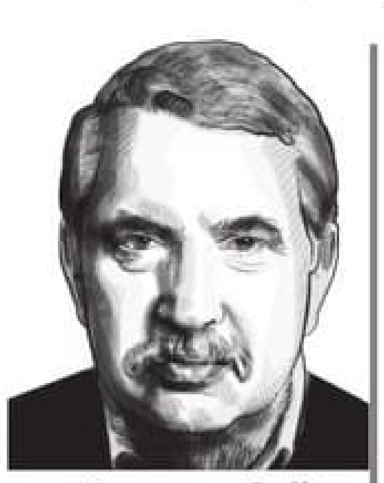

थॉमस एल फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

जरा सोचिए कि ईरान में मौजूद नेतृत्व के साथ ऐसा करना, और वह भी लगभग एक हजार मील दूर से हवाई हमले के जरिये कितना मुश्किल होगा। ईरान की कहानी भी कुछ इसी तरह के पैटर्न पर चलती दिख रही है। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार ईरान के नेताओं को मारते जा रहे हैं, और ईरान उन्हें फिर से पैदा करता जा रहा है। अब तक, ईरानी विपक्षी आंदोलन के बहादुर सदस्य (जिनके पास सत्ता संभालने के लिए अब भी न तो कोई नेता है और न ही कोई साझा एजेंडा) अपने घरों में ही दुबके हुए हैं और वे तेहरान में सरकारी गुंडों और तेल अवीव से बरसते हुए बमों से खौफजदा हैं।

■ दुश्मन का पूरा मिल्कशेक न पिएं

मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि दुनिया के किसी भी देश के लिए यह कभी भी अच्छा विचार नहीं होता कि वह अपने दुश्मन की गरिमा को इस हद तक छीन ले कि उसे लगने लगे कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अक्सर यही बात बाद में आपको ही भारी पड़ जाती है। वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि वेस्ट बैंक में इस्राइली बाशिंदे धीरे-धीरे फलस्तीनियों का 'मिल्कशेक' पीते जा रहे हैं, और उनके लिए वहां फलस्तीनी राज्य बनने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। यह नीति इस्राइल को ही भारी पड़ेगी, और लंबे समय में उसके सामने केवल दो ही रास्ते बचेंगे-या तो वह एक 'द्वि-राष्ट्रीय राज्य' बने, न कि एक 'यहूदी राज्य' या फिर एक 'रंगभेद वाला राज्य' बने, न कि एक 'लोकतांत्रिक राज्य'।

इस्राइल लेबनान में हिजबुल्ला के नेतृत्व और ईरान में इस्लामी शासन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में, जिसमें इस्राइल हर बड़े नेता को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वह लेबनान के बड़े इलाकों को तबाह करके उन पर कब्जा भी कर लेता है और ईरान की तेल अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर देता है, ठीक वैसे ही, जैसे उसने गाजा को तबाह किया था, तो वह दो काम कर चुका होगा। पहला, वह उन्हीं स्थानीय लोगों को अपने खिलाफ कर देगा, जिन्हें वह हिजबुल्ला और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ खड़ा करना चाहता था।

दूसरा, वह उनके देशों को ऐसी आर्थिक बदहाली में छोड़ देगा कि कोई भी उन पर शासन नहीं कर पाएगा। इसलिए, इस्राइल को लेबनान में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा।

वाशिंगटन का लक्ष्य इस शासन को चुनिंदा तरीके से कमजोर करना है। इसके लिए वह अहम मुद्दों (जैसे परमाणु संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइल का विकास और प्रॉक्सी गतिविधियां) पर अपनी बात मनवाने के लिए उतना ही दबाव डालता है, जिससे शासन पूरी तरह से ढह न जाए, क्योंकि ऐसा होने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। इसके लिए वाशिंगटन को अपने हमलों की गति और तीव्रता के बीच संतुलन बिठाना पड़ता है, ताकि एक तरफ तो शासन कमजोर हो, पर दूसरी तरफ उसकी संस्थागत एकजुटता भी इतनी बनी रहे कि वह बातचीत करने या कूटनीतिक दबाव में आकर झुकने की स्थिति में बना रहे।

■ ताकतवर और कमजोर की ताकत, आपकी सोच से कहीं ज्यादा बराबर होती हैं

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ अपनी छाती फुलाकर ताकत का बखान करते हैं कि उन्होंने ईरान में कितने ठिकानों को उड़ा दिया। पर, अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है, तो ट्रंप प्रशासन तेल की कीमतों में आए उस भारी उछाल से इतना हैरान क्यों था, जो ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में जहाजों पर और पड़ोसी अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले के कारण पैदा हुआ था? कीमतों में इस उछाल से ट्रंप पर भारी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में हम रहते हैं, वहां एक कमजोर ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल की आपूर्ति रोकने के लिए किसी सब्जी के ट्रक के पीछे से दिन में बस एक ड्रोन लॉन्च करने की जरूरत होती है और ऐसा होते ही दुनिया भर में तेल, गैस और खाद की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

इस युद्ध में अब तक कई अप्रिय आश्चर्य देखने को मिले हैं। क्या कोई सुखद आश्चर्य भी हो सकता है? यदि इस वैश्विक नाटक का कोई स्थायी और सुखद अंत होना है, तो वह इसलिए नहीं होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने हमास, हिजबुल्ला और ईरान के हर नेता को मार गिराया है, या उनसे उनकी हर गोली, मिसाइल और ड्रोन छीन लिया है। असल में, इसकी वजह यह हो सकती है कि उन्होंने बंदूकों वाले इन सख्त लोगों को इतना कमजोर कर दिया कि गाजा, लेबनान और ईरान में असली राजनीति की गुंजाइश पैदा हो सकती है। यही एकमात्र तरीका है, जिससे ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। पर यहां से वहां तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। यदि अमेरिका व इस्राइल को ईरान के निपटाने की जल्दी है, तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने गलत लड़ाई शुरू की है।

©The New York Times 2026

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

प्रकृति की हर चीज में एक गूढ़ रहस्य और आनंद छिपा होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। नदी के बहाव में, पेड़ की पत्तियों की हरकत में और हवाओं के संगीत में, हमें जीवन की अनकही सच्चाई मिलती है।

जो दिखता नहीं वही सबसे सुंदर है

__देखना__ और सुनना जीवन की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। अगर आपकी आंखें चिंताओं से अंधी हो गई हैं, तो आप डूबते सूरज की खूबसूरती नहीं देख सकते। हममें से ज्यादातर लोगों का प्रकृति से नाता टूट गया है। सभ्यता तेजी से बड़े शहरों की ओर बढ़ रही है और हम शहरी बनते जा रहे हैं, भीड़-भाड़ वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, शाम-सुबह आसमान देखने के लिए भी हमारे पास बहुत कम जगह होती है, और इसलिए हम कई तरह की खूबसूरती से दूर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने यह गौर किया है या नहीं कि हममें से कितने कम लोग उगते या डूबते सूरज, चांद, या पानी पर रोशनी के अक्स को देखते हैं।

प्रकृति से नाता टूटने के कारण, हम स्वाभाविक रूप से अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने लगते हैं। हम बहुत सारे म्यूजियम और कॉन्सर्ट में जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं और मनोरंजन के कई दूसरे साधन अपनाते हैं। हम बार-बार दूसरों के विचारों का हवाला देते हैं और कला के बारे में बहुत सोचते व बातें करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम कला पर इतना ज्यादा निर्भर रहते हैं? क्या यह भागने का, या खुद को जगाने का कोई तरीका है? अगर आप सीधे तौर पर प्रकृति के संपर्क में हैं; अगर आप उड़ते हुए किसी पक्षी की उड़ान को देखते हैं, आसमान की हर हरकत में खूबसूरती देखते हैं, पहाड़ों पर पड़ती परछाइयों या किसी दूसरे इन्सान के चेहरे की खूबसूरती को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी तस्वीर को देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाना चाहेंगे?

शायद ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपको अपने आसपास की चीजों को देखना ही नहीं आता, और शायद इसीलिए आप खुद को बेहतर ढंग से देखने के लिए किसी नशीली चीज का सहारा लेते हैं। लेखकों ने प्रकृति के साथ समय बिताया है, और हम दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। हम भले ही ज्ञान के पुस्तकालयों में समय बिताएं, पर जीवन की असली सुंदरता हमारे हाथों से फिसल रही होती है। प्रकृति की हर चीज में, एक गहन रहस्य और आनंद छिपा होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। किसी नदी के बहाव में, किसी पेड़ की पत्तियों की हरकत में, हवाओं के संगीत में, हमें जीवन की अनकही सच्चाई मिलती है। और जब हम सचमुच देखना सीखते हैं, तभी हम अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से जुड़ते हैं। यह ध्यान और सजगता का कार्य है-यह केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि मन की गहराइयों से अनुभव करना है।

आज के व्यस्त जीवन में, अगर हम थोड़ी देर रुकें, अपने विचारों और योजनाओं से मुक्त होकर, ध्यान से आसपास की चीजों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जीवन खुद में कितना समृद्ध और सुंदर है। एक पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी में, एक फूल में या हल्की हवा में हमें वही आनंद और शांति मिल सकती है, जो किसी चित्र या संगीत में भी नहीं मिलती।

-फ्रीडम फ्रॉम द नोन के अनूदित अंश

अपने आसपास देखें

सूत्र

जब हम अपनी चिंताओं और भागदौड़ से ऊपर उठकर ठहरते हैं और सच में देखना सीखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन की असली सुंदरता हमारे चारों ओर ही बिखरी हुई है-उगते सूरज की रोशनी में, उड़ते पक्षी के कोलाहल में, हवा के कोमल स्पर्श में और प्रकृति की शांत लय में। यही वह क्षण है, जब हम शांत महसूस करते हैं।

दूसरा पहलू

देश में पंजीकृत करीब 2,000 गौशालाओं का सालाना बजट अरबों रुपये का है, पर इसका लाभ जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता।

गौ-रक्षा एक आर्थिक मॉडल भी हो सकता है

सनातन हिंदू संस्कृति में गाय को मां माना जाता है। गाय का दूध, उससे बना दही, छाछ, पनीर व घी स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। देशी गाय के गोबर और मूत्र के गुण वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हो चुके हैं। सदियों से हर सनातनी के घर गौ पालन की प्रथा थी, पर शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली ने इस परंपरा को तेजी से नष्ट किया है। गत 100-150 वर्षों में शहरों में हजारों गौशालाएं स्थापित हुई हैं, पर अधिकतर गौशालाओं की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है।

विनीत नारायण

आज देश में करीब 8,000 गौशालाएं हैं, जिनमें से लगभग 2,000 गौशालाएं ही पंजीकृत हैं। इन गौशालाओं का सालाना बजट अरबों रुपये का है। पर इसका लाभ जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता। इस दिशा में हमने एक छोटा-सा प्रयोग 20 बरस पहले मथुरा में करके देखा था, जिसके सकारात्मक परिणाम आए। हम इसे आगे इसलिए नहीं चला पाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ब्रज के कृष्ण कालीन सरोवरों और वनों को बचाने की थी। ये मॉडल बहुत सरल हैं। देश में 10,210,000 हेक्टेयर भूमि चरागाहों के लिए उपलब्ध है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की 3-4 फीसदी है। हर गांव में कई भूमिहीन परिवार होते हैं, जिन्हें 'मनरेगा' जैसी योजनाएं चला कर, साल के कुछ दिन सरकार रोजगार देती है। जिले और गांवों में ऐसे तमाम पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। होना यह चाहिए कि गांव के भूमिहीन परिवारों की समिति बना कर उन्हें चरागाहों की भूमि पर चारा उगाने के काम में लगाया जाए। यह चारा फिर भूमिहीन परिवारों को दिया जाए। ये परिवार चरागाह में मेहनत करके आय प्राप्त करें और मुफ्त के चारे से अपने गोवंश की सेवा करके उसके दुग्ध उत्पादन से अपने परिवार का पालन-पोषण करें और स्वस्थ जीवन जी सकें।

गांव के भूमिहीन परिवारों की समिति बना कर उन्हें चरागाहों की भूमि पर चारा उगाने के काम में लगाया जाना चाहिए।

आईआईटी व आईआईएम से पढ़कर तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरियां छोड़कर कुछ नौजवान मध्य भारत में इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हजारों गरीबों की जिंदगी खुशहाल बना दी है।

हमने जब यह प्रयोग मथुरा में किया, तो हमने दानदाताओं से कहा कि वे एक गांव की चरागाह पर चारा उगाने में आर्थिक मदद करें और गौ सेवा के नाम पर धन का दान न करें। हमें ऐसे कई उदारमना दानदाता मिल गए और नौजवान भी, जिन्होंने इस प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग किया। हमारा प्रयोग तो बहुत छोटे स्तर का था। पर आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरियां छोड़कर कुछ नौजवान मध्य भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हजारों गरीबों की जिंदगी खुशहाल बना दी और इस प्रक्रिया से उत्पन्न गोबर की खाद से बंजर पड़ी जमीनों में फलों के बड़े-बड़े बगीचे लगा दिए हैं। शुरू में उनका विरोध करने वाले लोग अब उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। जरूरत है एक ईमानदार और उदार सोच की।

आंकड़े

चीन सबसे आगे

नवीनतम डाटा के अनुसार, दुनिया में लगभग 70 से अधिक परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, और इनमें सर्वाधिक चीन में हैं।

चीन	38
भारत	08
रूस	07
तुर्किये	04
मिस्र	04

आंकड़े देशों में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों के, संख्या में। | स्रोत : विश्व परमाणु संघ (डब्ल्यूएनए)

ऋषि मेधावी कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन वह मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। कई वर्ष बीत जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई है।

मोह और भटकाव

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि मेधावी भगवान शिव के परम भक्त थे और चैत्ररथ वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन गंधर्वों के राजा चित्ररथ अप्सराओं के साथ वहां आए। उन्हीं में से एक अप्सरा मंजुघोषा ऋषि पर मोहित हो गई। वह उनकी तपस्या भंग करना चाहती थी, परंतु शाप के भय से दूर रहकर मधुर गीत और वाद्य से उन्हें आकर्षित करने लगी। कामदेव ने भी उसका साथ दिया, और धीरे-धीरे ऋषि तपस्या भूलकर उसके प्रेम में पड़ गए।

दोनों साथ रहने लगे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने घर लौटने की अनुमति मांगी, पर ऋषि ने मना कर दिया। बार-बार निवेदन के बाद भी वह टालते रहे। अंततः जब अप्सरा ने दृढ़ता से जाने की बात कही, तब ऋषि को एहसास हुआ कि उन्होंने वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को भूत बनने का शाप दे दिया। डरी हुई अप्सरा ने क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का मार्ग बताया।

अंतर्यात्रा
संकलित

मंजुघोषा ने अपने पिता की आज्ञा से यह व्रत किया और स्वयं ऋषि मेधावी ने भी विधि-विधान से इसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों अपने-अपने पापों से मुक्त हो गए और उन्हें शांति प्राप्त हुई।

मोह और भटकाव मनुष्य को उसके सत्मार्ग से दूर कर सकते हैं, पर सच्चे पश्चाताप और सही आचरण से किसी भी गलती का प्रायश्चित संभव है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 मार्च, 1955

कांग्रेसजनों का सरकारी कामों के पीछे दौड़ना शोभनीय नहीं

कांग्रेसजनों का सरकारी कामों के पीछे दौड़ना शोभनीय नहीं

कांग्रेसजनों के बीच भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के नियोजन मंत्री चंद्रभानु गुप्त ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोटे अथवा बड़े सरकारी कार्यों के पीछे दौड़ना शोभा नहीं देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्यों की सेवा करने के अन्य मार्ग भी हैं।

मलयालम को लेकर क्यों उठ रहे सवाल

केरल के विधानसभा चुनाव में मलयालम को आधिकारिक दर्जा मिलना बड़ा मुद्दा होगा, पर कर्नाटक की आपत्तियों से उठे सवाल भी गौर करने लायक हैं।

उमेश चतुर्वेदी | **मुद्दा**

केरल का नाम 'केरलम' किया जाना और मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा की मंजूरी मिलने को कुछ लोग संयोग बता सकते हैं। हालांकि, यह महज संयोग नहीं है। केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा इन कदमों का श्रेय लेने की होड़ मचना स्वाभाविक है। पर भाषा विधेयक को लेकर केरल की सीमा के बाहर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं।

मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा बनाने का पहला प्रयास करीब दस साल पहले कांग्रेस की अगुआई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, यानी यूडीएफ की सरकार ने किया था। पर तब कर्नाटक सरकार ने एतराज जताया था। राष्ट्रपति ने इसे 1963 के ऑफिशियल भाषा एक्ट के नियमों को हटाकर जमा करने के सुझाव के साथ वापस भेज दिया था। फिर दस साल बाद मौजूदा वाममोर्चा की सरकार ने इसे नए रूप में पारित किया। कर्नाटक इस बार भी इसका विरोध कर रहा है।

नए कानून के तहत सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक मलयालम को पहली भाषा के तौर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाना जरूरी होगा। इसके साथ ही, अदालती फैसले और कार्यवाही भी अनिवार्य तौर पर मलयालम भाषा में अनूदित की जाएगी। अब से राज्य विधानसभा में सभी बिल और अध्यादेश मलयालम में पेश किए जाएंगे। राज्य सचिवालय में मौजूदा पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (ऑफिशियल लैंग्वेज) विभाग का नाम बदलकर मलयालम भाषा विकास विभाग किया जा रहा है। साथ ही, राज्य में मलयालम भाषा विकास निदेशालय भी गठित किया जाएगा। केरल का यह कदम क्रांतिकारी और भारतीय भाषाओं के हित में है, पर कर्नाटक की आपत्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार का तर्क है कि यह कानून केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों की भाषाई अस्मिता के लिए खतरा है। कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मानना है कि कासरगोड और केरल के दूसरे कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अभी स्कूलों में कन्नड़ को पहली भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। केरल में स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाती रही है। इसलिए, माना जाता है कि केरल में हिंदी विरोधी माहौल नहीं है। पर केरल के विद्वान इस कानून के पक्ष में तर्क देते वक्त केंद्र सरकार पर केरल में हिंदी थोपने का आरोप लगाने से नहीं हिचक रहे। ऐसा ही आरोप कर्नाटक की ओर से लगाया जा रहा है, बस वहां हिंदी की जगह मलयालम को थोपे जाने की बात हो रही है।

हालांकि, केरल सरकार ने सफाई दी है कि जिनकी मातृभाषा तमिल, कन्नड़, तुलु या कोंकणी है, उनके लिए भी कानून में प्रावधान हैं। कानून में इस बात की चर्चा है कि राज्य के भाषायी अल्पसंख्यक अपनी भाषा में राज्य सचिवालय, विभागों और स्थानीय सरकारी कार्यालयों से पत्राचार कर सकेंगे। दूसरी मातृभाषा वाले छात्र नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। इसी तरह, दूसरे राज्यों या विदेश से आने वाले छात्रों को नौवीं, दसवीं और हायर सेकेंडरी स्तर पर मलयालम की परीक्षा देने से छूट मिलेगी।

मलयालम को आधिकारिक भाषा बनाने का स्थानीय नागरिक स्वागत तो कर रहे हैं, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून के नाम से ही अलगाववादी और वर्चस्ववादी झलक मिलती है। केरल के एक बौद्धिक वर्ग का कहना है कि बेहतर होता कानून का नाम 'मलयालम भाषा एक्ट 2025' की जगह 'केरल स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2025' होता। इससे समावेशी संदेश जाता। साथ ही, विधेयक में मलयालम की जगह राज्य में प्रयोग में लाई जाने वाली तमिल, कन्नड़, कोंकणी, तुलु व गुजराती का भी जिक्र होता। एक वर्ग का तर्क है कि केरल में जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की भाषाओं की अस्मिता की रक्षा का बोध भी इसमें होना चाहिए था।

केरल के विधानसभा चुनाव में मलयालम को आधिकारिक दर्जा मिलना बड़ा मुद्दा होगा। राज्य की राजनीति में प्रभावी दखल देने की ताक में बैठी भाजपा, कांग्रेस और वाममोर्चा, सभी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। केरल में मांग उठ रही है कि वहां के सिविल सर्विस सुधार विभाग को मलयालम भाषा विकास विभाग के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। कानून में इस विभाग के पुनर्गठन और मलयालम भाषा व विकास निदेशालय बनाने का प्रावधान है। यहां के भाषाशास्त्री इसे स्वागतयोग्य कदम बता तो रहे हैं, पर मलयालम के साथ अन्य भाषाओं के प्रतिनिधित्व का सुझाव भी दे रहे हैं।

मातृभाषा से इतर समूहों से आने वाले लोग किसी भी भाषा को अवसरों और जरूरत के लिहाज से सीखते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में मजबूरी के बजाय उत्साह जुड़ जाता है, तो भाषाएं समृद्ध होती हैं और वे सौहार्द का प्रतीक बनती हैं। आधिकारिक भाषा बनने के बाद मलयालम भी उसी तरह उम्मीद की भाषा बने, शायद यही केरल के बौद्धिक चाहते हैं। मलयालमभाषियों की इस सोच से हिंदीभाषी विद्वानों, राजनेताओं और प्रशासनिक तंत्र को प्रेरित होना चाहिए।

edit@amarujala.com

तेल में उछाल का असर...निजी क्षेत्र की वृद्धि दर 2.5 साल में सबसे कम

■ कच्चे माल की लागत में तेज बढ़ोतरी व घरेलू मांग में नरमी के चलते आई गिरावट
ऊर्जा संकट के कारण विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में घटी उत्पादन की रफ्तार

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर भी दिखने लगा है। देश के निजी क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार मार्च, 2026 में धीमी होकर करीब साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर आ गई। कच्चे माल की लागत में तेज बढ़ोतरी और घरेलू मांग में नरमी के कारण यह बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है।

56.5 रहा इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स घटकर मार्च में

एसएंडपी ग्लोबल के आंकड़ों के मुताबिक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में नरमी से एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स गिरकर मार्च में 56.5 पर आ गया। यह अक्तूबर, 2022 के बाद सबसे कम वृद्धि दर है। फरवरी में फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई 58.9 रहा था।

एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, ऊर्जा संकट के कारण विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार घटी है। कमजोर घरेलू मांग से नए ऑर्डर में गिरावट आई, जिससे कंपनियों को उत्पादन की रफ्तार घटानी पड़ी। हालांकि, नए निर्यात ऑर्डर में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। भंडारी ने कहा, तेल की कीमतों में उछाल और कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनियों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है। हालांकि, कंपनियां मार्जिन में कटौती कर महंगाई के झटके को कम करने का प्रयास कर रही हैं। ब्यूरो

विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक मार

विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सुस्ती ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई के दबाव के कारण विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन की रफ्तार तेजी से घटकर करीब साढ़े चार साल के निचले स्तर पर आ गई। आंकड़ों के मुताबिक, विनिर्माण पीएमआई फरवरी के 56.9 से घटकर मार्च में 53.8 पर आ गया। वहीं, विनिर्माण उत्पादन इंडेक्स भी गिरकर 55.1 पर आ गया।

■ **सेवा क्षेत्र की गतिविधियों की रफ्तार भी धीमी रही।** इससे सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक फरवरी के 58.1 से गिरकर 57.2 पर आ गया, जो जनवरी, 2025 के बाद 14 महीने में सबसे कम है।

नए कारोबार में कमजोर वृद्धि

विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के नए कारोबार में कमजोर वृद्धि दर्ज की गई। कंपनियों को मिले कुल नए ऑर्डर की रफ्तार नवंबर, 2022 के बाद सबसे धीमी रही। हालांकि, निर्यात मांग मजबूत बनी हुई है। भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों से रिकॉर्ड नए ऑर्डर मिले। एशिया, यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया से नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार तेज रही।

लागत का दबाव चार साल में सबसे ज्यादा : तेल और कच्चे माल की कीमतों में उछाल विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ी है। ऊर्जा, धातु, रसायन और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल से कंपनियों की इनपुट लागत करीब चार साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है।

म्यूचुअल फंड में गिफ्ट कार्ड के जरिये निवेश की तैयारी

सेबी ने नए प्रस्ताव पर मांगी आम लोगों से राय

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड में निवेश को आसान बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब गिफ्ट कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटके जरिए भी निवेश किया जा सकेगा। इसके जरिए कोई व्यक्ति गिफ्ट कार्ड खरीदकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकेगा। जिसे यह गिफ्ट मिलेगा, वह इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने में कर सकेगा। रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इन निवेशों पर नजर रखेंगी।

सेबी ने सुरक्षा के लिए एक सीमा भी तय करने का सुझाव दिया है। एक निवेशक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपये तक ही निवेश कर सकेगा। अगर यह सीमा पार होती है तो लेनदेन को रद्द कर दिया जाएगा। पैसा वापस जारी करने वाले के खाते में भेज दिया जाएगा। सेबी का यह सुझाव भारतीय म्यूचुअल फंड संघ की सिफारिश के बाद आया है। सेबी का मानना है कि इससे नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश में जोड़ना आसान होगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और लोग छोटे-छोटे निवेश से शुरुआत कर सकेंगे। एजेंसी

न्यूज डायरी

सोने की कीमतों में 1,200 रुपये का उछाल

नई दिल्ली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। 99.9 फीसदी शुद्ध सोना 1,44,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो सोमवार के 1,43,600 रुपये से 1,200 रुपये अधिक है। वहीं, चांदी की कीमत 2.30 लाख प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। व्यापारियों के अनुसार, सोने में यह बढ़त वैश्विक बाजारों में तेजी और हाल ही में आई तीव्र गिरावट के बाद कुछ खरीदारी के कारण हुई है। एजेंसी

जोमैटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस

नई दिल्ली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने यूजर्स से लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब एप पर हर ऑर्डर के लिए प्लेटफॉर्म फीस 17.58 रुपये (जीएसटी सहित) होगी। यह बढ़ोतरी जोमैटो द्वारा हाल ही में शुल्क बढ़ाने के कुछ दिन बाद की गई है। इस नई बढ़ोतरी के बाद, दोनों फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की फीस लगभग बराबर हो गई है। एजेंसी

ईंधन लागत और बढ़ी तो हवाई किराये बढ़ेंगे : इंडिगो

मुंबई। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अगर लागत और बढ़ती है, तो हवाई किराये में वृद्धि होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण विमान ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं और पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों से एयरलाइन कंपनियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। एजेंसी

मारुति गुजरात में करेगी 10,189 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपने नए विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण में 2.5 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए 10,189 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसके निदेशक मंडल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। यह देश में मारुति का पांचवां विनिर्माण संयंत्र होगा। पहले चरण के 2029 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। एजेंसी

जेपी मामला : एनसीएलएटी में वेदांता का दावा खारिज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को वेदांता समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अदाणी समूह की जयप्रकाश एसोसिएट्स को 14,535 करोड़ में खरीदने की मंजूरी पर अंतरिम रोक की मांग की थी। हालांकि, एनसीएलएटी ने क्रेडिटर्स की समिति से एक सप्ताह में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। एजेंसी

ट्रंप के बयान से शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी में 2% उछाल

ईरान तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार को राहत दी, लेकिन निवेशक अभी सतर्क

मुंबई। भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को मजबूत उछाल देखा गया। बीएसई सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 फीसदी बढ़कर 74,068.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी-50 399.75 अंक या 1.78 फीसदी की बढ़त के साथ 22,912.40 पर बंद हुआ। मंगलवार की रैली ने निवेशकों की संपत्ति में लगभग 7.56 लाख करोड़ रुपये की बढ़त दिखाई। लार्सन और टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की। पावर ग्रिड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर पिछड़ गए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों को पांच दिन के लिए रोके जाने की घोषणा की और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की समयसीमा बढ़ाई। इसके बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा और बाजार में तेजी आई। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार को राहत दी, लेकिन निवेशक अभी भी सतर्क हैं।

लिविंगलॉन्ग वेल्थ के शोध विश्लेषक हरिप्रसाद ने कहा, भारतीय बाजार में सकारात्मक उछाल देखा गया। हाल की बिकवाली के बाद ऐसी तेजी आम है और निवेशक गुणवत्ता वाली कंपनियों में अवसर का लाभ उठाते हैं। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों में अस्थायी विराम के बाद घरेलू बाजार में राहत भरी तेजी देखी गई। एजेंसी

अन्य इंडेक्स और सेक्टर्स : सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त में रहे। आईटी सेक्टर 3.46 फीसदी की तेजी के साथ सबसे आगे रहा। ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल और कमोडिटी सेक्टर्स भी बढ़त में रहे। मझोली कंपनियों से संबंधित बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 2.77 फीसदी चढ़ा, जबकि छोटी कंपनियों से संबंधित स्मॉलकैप में 2.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

■ **विदेशी निवेशकों का हाल...**मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,009.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,867.15 करोड़ के शेयर खरीदे। बीते सोमवार को सेंसेक्स 1,836.57 अंक गिरकर 72,696.39 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 601.85 अंक टूटा था।

रुपया 23 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर

मुंबई। रुपये ने डॉलर के मुकाबले एक बार फिर गोता लगाया। रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.76 प्रति डॉलर पर आ गया। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण निवेशकों में चिंता का माहौल रहने से घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई। फॉरेक्स कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों की निकासी ने भी रुपये पर दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 93.66 पर खुला और पूरे सत्र के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव बना रहा। अंत में यह 93.76 पर रहा, जो पिछले बंद स्तर से 23 पैसे की गिरावट है। सोमवार को रुपया पहली बार 94 के नीचे पहुंच गया था। हालांकि, बाद में 93.53 पर बंद हुआ। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.23 फीसदी बढ़कर 99.18 पर पहुंच गया। एजेंसी

केंद्रीय बैंक के समर्थन में कमी से बॉन्ड में दबाव

मुंबई। भारत में रुपये और सरकारी बॉन्ड की हालिया गिरावट से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक का समर्थन अब पहले जैसा मजबूत नहीं है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के प्रभाव से बाजारों में उतार-चढ़ाव और तेज हो सकते हैं। सोमवार को रुपये ने डॉलर के मुकाबले लगभग 94 का रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया। 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 6.89 फीसदी हो गई, जो एक साल के उच्च स्तर के करीब है। बैंकर्स को डर है कि विदेशी निवेशकों के बाहर जाने और फॉरवर्ड बाजार में मांग बढ़ने से और गिरावट आ सकती है। मध्य पूर्व संघर्ष के बाद आरबीआई ने 1,77,000 रुपये के बॉन्ड खरीदे। मार्च में अब तक केंद्रीय बैंक ने लगभग 16-18 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा बेचकर बाजार से डॉलर की मांग को संतुलित किया। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा 50 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल

■ भारत ने 2019 के बाद पहली बार ईरान से खरीदा क्रूड

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 50 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल खरीदा है। यह सौदा उस समय हुआ, जब अमेरिका ने ईरान पर तेल संबंधी प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए थे। तेल खरीद नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी से की गई।

सूत्रों के अनुसार, यह तेल आईसीई ब्रेंट वायदा के मुकाबले लगभग 7 डॉलर प्रति बैरल प्रीमियम पर खरीदा गया। यह स्पष्ट नहीं है कि तेल की डिलीवरी कब होगी। रिलायंस का यह कदम वैश्विक तेल बाजार और ईरान के साथ भारत के व्यापार संबंधों में नया मोड़ दिखाता है। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की छूट दी। यह छूट 20 मार्च को या उससे पहले किसी भी जहाज पर लादे गए और 19 अप्रैल तक उतारे जाने वाले तेल पर लागू होती है।

यह सौदा इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने अस्थायी रूप से कुछ प्रतिबंधों में छूट दी है, ताकि बढ़ती ऊर्जा कमी को दूर किया जा सके। इसी के बाद भारत के रिफाइनर ईरानी तेल खरीदने के लिए आगे आए हैं।

इससे पहले, भारतीय तेलशोधक कंपनियां इस महीने 40 मिलियन बैरल से ज्यादा रूसी तेल भी खरीद चुकी हैं, ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। यह सौदा भारत की ऊर्जा रणनीति में बदलाव का संकेत देता है, जहां देश सस्ती और नजदीकी आपूर्ति के विकल्प तलाश रहा है। भारत के अलावा एशिया के अन्य रिफाइनर भी ईरानी तेल खरीदने की संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि, चीन की बड़ी कंपनी सिनोपेक ने फिलहाल ईरानी तेल में रुचि नहीं दिखाई है। एजेंसी

ईरानी तेल महंगा, फिर भी खरीद रहीं कंपनियां

अमेरिकी राहत उपायों के बाद ईरानी तेल अब भारत की कंपनियों को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले प्रीमियम यानी महंगे दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी उद्योग सूत्रों ने दी। ईरानी तेल की खरीद ब्रेंट से लगभग 6-8 डॉलर प्रति बैरल प्रीमियम पर हुई। भुगतान कार्गो के आगमन के सात दिनों के भीतर किया जाना है। मई, 2019 के बाद से भारत ने ईरानी कच्चा तेल नहीं खरीदा है। हाल ही में ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो गई है। इस संकट को देखते हुए भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां ईरान से तेल और एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रही हैं, ताकि घरेलू जरूरत पूरी हो सके।

बेरोजगारी दर घटी, पर किचन का बजट बढ़ा रही महंगाई

आरबीआई की रिपोर्ट...अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को सहन करने की मजबूत क्षमता, कई क्षेत्रों में बढ़ीं नौकरियां

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। विदेशी मुद्रा और व्यापार घाटे के बढ़ते दबाव के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का मानना है कि अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को सहन करने की मजबूत क्षमता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बाद भी देश में बेरोजगारी दर में मामूली कमी आई है। विशेष रूप से बीमा, बीपीओ, आईटीईएस और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के नए अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। ब्यूरो

सब्जी, तेल और फलों की कीमतों में उछाल

महंगाई के आंकड़े चिंताजनक हैं। फरवरी में मुद्रास्फीति बढ़कर 3.2 फीसदी पहुंच गई, जो जनवरी में 2.7 फीसदी थी। यह उछाल मांस, मछली, खाद्य तेल, फल और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण आया है। अरहर और मूंग दालों के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि, चावल और गेहूं की कीमतों में स्थिरता या मामूली गिरावट रही।

■ ***एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव :*** *अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगातार पांचवें महीने नकारात्मक रहा है। इस दौरान 75 फीसदी बाहरी निवेश अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन और यूएई की ओर चला गया। वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि से चालू खाता घाटा भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में 24.4 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है।*

तेल और विदेशी निवेश की चुनौती

आरबीआई ने आगाह किया है कि कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता को देखते हुए वर्तमान वैश्विक संकट पर करीबी निगरानी जरूरी है। भारत ने आयात स्रोतों में विविधता लाकर और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधान के प्रति सरकार को सक्रिय उपाय करने होंगे।

रोजगार के मोर्चे पर सुधार के संकेत : जॉबस्पीक इंडेक्स ने भी व्हाइट कॉलर जॉब्स में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्शाई है। एक राहतभरी खबर यह भी है कि मनरेगा के तहत काम की मांग में लगातार आठवें महीने कमी आई है। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और वहां वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के तौर पर देखा जा रहा है।

लचीले कार्यस्थल की बढ़ी मांग कंपनियां कर रहीं विशेष तैयारी

सीबीआरई इंडिया रिसर्च और फिक्की की रिपोर्ट फ्लेक्स-प्लोजन:भारत में लचीले कार्यस्थल का दौर के अनुसार, देश में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का महत्व बढ़ रहा है। 2027 तक भारत की लगभग 65 फीसदी कंपनियां अपने ऑफिस पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस शामिल करने की योजना बना रही हैं। ब्यूरो

कैसे हुआ बाजार का विकास

2020-2025 के बीच फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का कुल स्टॉक लगभग 3 गुना बढ़ा।

2025 तक भारत में लचीले कार्यस्थल लगभग 1100–1140 लाख स्क्वायर फीट थे।

टियर-1 शहरों में यह संख्या 90 फीसदी से अधिक है।

शहरवार स्थिति

■ बंगलूरू सबसे बड़ा बाजार, 300–320 लाख स्क्वायर फुट स्टॉक

■ दिल्ली-एनसीआर, 210–230 लाख स्क्वायर फुट

■ मुंबई मे मांग मुख्यत बड़े कॉरपोरेट्स से, 2024-25 में लीजिंग लगातार बढ़ी

निवेश और भविष्य

फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर अब पब्लिक लिस्टिंग के जरिए पूंजी जुटा रहे हैं। इससे तेजी से नेटवर्क विस्तार और एसेट-लाइट मॉडल को बढ़ावा मिला।

राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च हर साल जुटाए जाएंगे 8 लाख करोड़

मुंबई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया। यह ट्रस्ट बीएसई में सूचीबद्ध भी हो गया है।

इस ट्रस्ट के पहले पब्लिक इश्यू को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह 14 गुना भरा हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम भारत के हाईवे सेक्टर में निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गडकरी ने कहा, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से राजमार्ग निर्माण का बहुत महत्व है और इस पर अधिक खर्च करने से देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया एक रुपया, अर्थव्यवस्था में तीन रुपये के बराबर की गतिविधियां पैदा करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारी समस्या यह है कि हम खर्च करने में असमर्थ हैं। हमारे खर्च करने की गति बहुत धीमी है। आम लोग भी सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में निवेश कर सकेंगे। ब्यूरो

डिजिटल भुगतान को बेहतर बनाने की तैयारी

यूपीआई लेनदेन पूरा न होने पर स्वचालित प्रणाली से दर्ज होगी शिकायत

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक कृत्रिम मेधा और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का लाभ उठाकर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और भुगतान परिवेश को मजबूत करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और भुगतान इंटेलिजेंस मंच विकसित कर रहा है। आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन ने एमपीएआई मर्चेंट्स दिवस 2026 के मौके पर कहा, हम अधिक से अधिक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआई) बना रहे हैं। हम सभी डीपीआई और एपीआई को बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन गतिविधियों का भविष्य होंगे। डिजिटल लेनदेन की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय बैंक ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायत निवारण को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम मेधा के उपयोग पर विचार कर रहा है। अगर कोई यूपीआई लेनदेन असफल होता है या पूरा नहीं होता तो यूपीआई हेल्प जैसे फीचर स्वचालित शिकायत दर्ज कर देंगे। एजेंसी

एचडीएफसी बैंक : पूर्व चेयरमैन के इस्तीफे में उठाए गए मुद्दों की जांच करेंगी विधि कंपनियां

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक ने पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए विधि कंपनियों को नियुक्त किया है। बैंक का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। धि कंपनियों की मदद से इस्तीफे में उठाए गए सभी पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा की जाएगी, ताकि पारदर्शी आकलन हो सके।

चार सूत्रों ने बताया कि घरेलू फर्म ट्राइलीगल और वाडिया गांधी एंड कंपनी से बैंक में अपनाए जाने वाले गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। यह प्रक्रिया बैंक के उच्च कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों के अनुरूप है। अतानु चक्रवर्ती ने नैतिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो 18 मार्च से प्रभावी हुआ। यह पहली बार है जब बैंक के किसी अंशकालिक चेयरमैन ने कार्यकाल के बीच में पद छोड़ा है। इस्तीफे में चक्रवर्ती ने कहा था कि दो वर्षों में उन्होंने बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं देखी, जो उनके निजी मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। एजेंसी

तीन सत्रों की गिरावट के बाद उछले शेयर

एचडीएफसी बैंक के शेयरों में मंगलवार, 24 मार्च को करीब 3 फीसदी की बढ़त देखने को मिली। यह बढ़त बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन के इस्तीफे और बैंक द्वारा तीन कर्मचारियों को हटाए जाने से जुड़े नए घटनाक्रमों के सामने आने के बाद हुई। पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में स्टॉक फीसदी 12 गिरा था। पिछले एक महीने में यह 17 फीसदी नीचे आया है।

ट्रंप की ईरान पर हमले टालने की घोषणा से ठीक पहले तेल बाजार में भारी सट्टेबाजी

मिनटों में सैकड़ों मिलियन डॉलर की बाजी ने खड़े किए इनसाइडर ट्रेडिंग के सवाल

अमर उजाला नेटवर्क

लंदन/ वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर संभावित हमले टालने की घोषणा से ठीक पहले तेल बाजार में असामान्य सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। बीबीसी द्वारा समीक्षा किए गए डाटा से पता चलता है कि घोषणा से करीब 15 मिनट पहले अचानक भारी मात्रा में ट्रेडिंग हुई, जिससे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट का कुछ ट्रेडर्स ने बड़ा फायदा उठाया। इस घटनाक्रम ने इनसाइडर जानकारी के दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म दे दिया है।

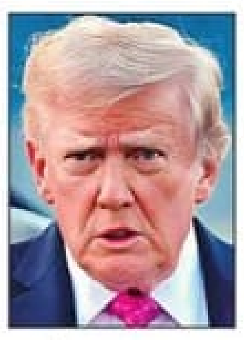

सुबह 06:49 ईटी पर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (एनवाईमेक्स) पर डब्ल्यूटीआई क्रूड के 733 कॉन्ट्रैक्ट्स पर दांव लगाए गए थे, जो महज एक मिनट में बढ़कर 2007 हो गए। यह करीब 170 मिलियन डॉलर यानी 1,400 करोड़ रुपये के सौदों के बराबर था। इसी तरह ब्रेंट क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक मिनट के भीतर 20 से बढ़कर 1600 से ज्यादा ट्रेड दर्ज किए गए, जिनकी कीमत 150 मिलियन डॉलर यानी 1245 करोड़ आंकी गई। सामान्यतः सोमवार सुबह इस समय इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं होती, जिससे इस गतिविधि पर संदेह और गहरा गया। जिन ट्रेडर्स ने पहले से दांव लगाया था, उन्हें भारी मुनाफा हुआ।

विशेषज्ञों की नजर में असामान्य गतिविधि

एक्सएनालिस्ट्स के मुख्य तेल विश्लेषक मुकेश साहदेव ने इस ट्रेडिंग पैटर्न को स्पष्ट रूप से असामान्य बताया। उनके अनुसार उस समय अमेरिका और ईरान के बीच किसी गंभीर बातचीत के संकेत नहीं थे, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में तेल गिरने पर दांव लगाना स्वाभाविक नहीं लगता। वहीं, किलिक एंड कंपनी की पार्टनर रैचल विंटर ने कहा कि कई निवेशकों ने ट्रंप के पोस्ट से ठीक पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जिनसे उन्हें तेल कीमत गिरने पर लाभ मिलना तय था।

नियामकों की नजर और बढ़ती जांच की मांग : यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े घटनाक्रमों के आसपास सट्टेबाजी बढ़ी हो। जनवरी में पॉलीमार्केट नामक क्रिप्टो-आधारित प्लेटफॉर्म पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने पर भारी दांव लगाए गए थे। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी बलों ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे एक खाते को 32,537 डॉलर के दांव पर 436,000 डॉलर से ज्यादा का मुनाफा हुआ था।

एजुकेशन & कॅरिअर

हर दिन एक नई शुरुआत है और इसे सार्थक बनाएं।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

सशस्त्र सीमा बल में निकली भर्ती

कॉन्स्टेबल के पदों पर करें आवेदन

827 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 23, 25 व 27 वर्ष
यहां आवेदन करें : ssb.gov.in

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ■ 153 पद

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि
01 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
दसवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
ibpsreg.ibps.in/epfofeb26

एसएसबी में रोजगार के अवसर ■ 58 पद

सब इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि
20 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
बारहवीं, इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
ssb.gov.in

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ■ 373 पद

कंपाउंडर, टेक्नीशियन व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 30 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : esb.mp.gov.in

राष्ट्रीय जैविक संस्थान में रिक्तियां ■ 46 पद

प्रशासनिक सहायक, सहायक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
08 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
एमबीबीएस, स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
nib.gov.in

एनएबीएफआईडी में निकली भर्ती ■ 29 पद

सीनियर एनालिस्ट के पदों पर योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
08 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
nabfid.org/careers

यहां भी रोजगार के अवसर...

- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलूरू : वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 06 अप्रैल, 2026
- hal-india.co.in
- सचिवालय सुरक्षा बल : कॉन्स्टेबल के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 28 अप्रैल, 2026
- recruitment.itbpolice.nic.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

असली प्रेरणा तो आपके भीतर है

अगर काम के बीच में ध्यान भटके, तो निराश होने के बजाय इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह लें

रॉबिन अब्राहम
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

जब आप किसी काम में अटक जाते हैं, तो इसे असफलता नहीं, बल्कि एक संकेत मानें कि अभी कुछ नया सीखना बाकी है। ऐसे में नकारात्मक सोचने के बजाय, थोड़ी जिज्ञासा दिखाएं। 'इसे कैसे किया जा सकता है', इस सोच से आपका दिमाग खुलता है और नए रास्ते भी दिखने लगते हैं। अगर ध्यान बीच में भटक जाए, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यह हर किसी के साथ होता है। बस, थोड़ा ब्रेक लेकर दोबारा शुरू करें। जब आप खुद के साथ सख्त होने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं, तो धीरे-धीरे आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगते हैं।

Harvard Business Review

■ उद्देश्य से पुनः जुड़ें
अपने रोजमर्रा के काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह न देखकर यह समझना कि वह आपके व्यक्तिगत मूल्यों और संगठन के बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ा है। जब आप अपने कार्यों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि आपका हर छोटा प्रयास भी किसी बड़े परिणाम में योगदान दे रहा है। इससे काम के प्रति स्पष्टता बढ़ती है, प्रेरणा मजबूत होती है और आप अपने काम के वास्तविक प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे कार्य अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक लगने लगता है।

■ छोटे कदम उठाएं
किसी बड़ी और जटिल परियोजना को एक साथ करने के बजाय उसे छोटे, स्पष्ट और आसानी से पूरे होने वाले चरणों में बांटें। इससे काम कम बोझिल लगता है और आप हर चरण को पूरा करते हुए लगातार प्रगति महसूस करते हैं। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे काम में निरंतर गति बनी रहती है। धीरे-धीरे ये छोटे कदम मिलकर आपको उस बड़ी परियोजना में महारत हासिल करने में मदद करते हैं और पूरे काम को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना देते हैं।

■ उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें
अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखना और सहकर्मियों की सराहना को बढ़ावा देना, एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपनी छोटी-बड़ी सफलताओं को

'हैप्पी फोल्डर' या साप्ताहिक लॉग में दर्ज करते हैं, तो समय के साथ आपकी प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने प्रयासों की अहमियत समझ में आती है। साथ ही, जब आप दूसरों के काम की सराहना करते हैं या उनकी सराहना प्राप्त करते हैं, तो आपसी सम्मान और सहयोग की भावना मजबूत होती है।

■ प्राथमिकताएं तय करें
हर काम को तुरंत करने की जरूरत नहीं होती। पहले यह समझें कि कौन-सा काम सच में जरूरी है और कौन-सा बाद में भी किया जा सकता है। जब आप कामों को उनकी अहमियत के अनुसार चुनकर करते हैं, तो सब कुछ ज्यादा आसान और व्यवस्थित लगने लगता है। इससे बेवजह का तनाव भी कम होता है और आप सही समय पर सही काम पर ध्यान दे पाते हैं।

खुद को परखें

1. प्रारंभ-2026 (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई) पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?
   (a) वाणिज्य मंत्रालय
   (b) वित्त मंत्रालय
   (c) कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय
   (d) विधि एवं न्याय मंत्रालय
2. सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?
   (a) झारखंड (b) गुजरात
   (c) हरियाणा (d) मध्य प्रदेश
3. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स-2026 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
   (a) यूरोपीय संघ
   (b) संयुक्त राष्ट्र
   (c) विश्व बैंक
   (d) इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस

उत्तर : 1.b, 2.a, 3.d

सामान्य ज्ञान

इंडिया बायोइकनॉमी रिपोर्ट

■ क्या है
यह भारत के बायोटेक सेक्टर की स्थिति, वृद्धि और संभावनाओं को बताने वाली एक महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बीआईआरएसी जारी करते हैं।

■ चर्चा में क्यों
हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने इंडिया बायोइकनॉमी रिपोर्ट (आईबीईआर)-2026 का अनावरण किया।

■ इसके तथ्य
आईबीईआर 2026 के अनुसार, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक 195 अरब डॉलर पहुंचकर जीडीपी में 4.8% योगदान दे रही है। यह 2014 में मात्र 10 अरब डॉलर थी, जिससे स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में इसमें वृद्धि हुई है, और केवल पिछले वर्ष में ही इसमें लगभग 17-18% की वृद्धि दर्ज हुई।

■ प्रमुख सेक्टर
भारत की बायोइकनॉमी बायोफार्मा, बायोइंडस्ट्रियल, बायोएग्रीकल्चर और बायोआईटी व रिसर्च पर आधारित है, जो क्रमशः स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाते हैं।

फेलोशिप अलर्ट

समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम-2026

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली द्वारा समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कार्यक्रम मेधावी अंडरग्रेजुएट तथा एमटेक/एमई छात्रों को संस्थान के फैकल्टी के मार्गदर्शन में अभिनव रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। आवेदन के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों ने अपने पिछले सेमेस्टर के अंत तक संबंधित प्रोग्राम में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक या 7.00 सीजीपीए प्राप्त किया हो। इस फेलोशिप की अवधि आठ सप्ताह निर्धारित है। चयनित छात्रों को ट्रेन के स्लीपर क्लास के अनुसार यात्रा व्यय के साथ-साथ आईआईटी दिल्ली में आवास एवं भोजन की सुविधा (हॉस्टल सहित) प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रति सप्ताह 2,000 रुपये की फेलोशिप राशि भी दी जाएगी। आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/mr38y8jb पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है।

स्पेशल पुस्तक
अमर उजाला उड़ान

ऑनलाइन खरीदने के लिए QR कोड को तुरंत स्कैन करें।

उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल परीक्षा-2026 ▸ सामान्य अध्ययन वनलाइनर विशेषांक

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001211166 या व्हाट्सएप नंबर 7065047252 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ मोटिवेशनल किताबें udaan.amarujala.com पर उपलब्ध।

आवेदन आमंत्रित

साइबर सुरक्षा ऑनलाइन कोर्स

दुनिया भर के किसी भी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट (एडीबीआई) के साइबर सुरक्षा ऑनलाइन कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। यह कोर्स साइबर सुरक्षा की मूल अवधारणा, उसके महत्व, विभिन्न साइबर हमलों के प्रकार तथा उन्हें पहचानने और उनसे निपटने के प्रभावी तरीकों को समझाता है। साथ ही, इसमें डाटा सुरक्षा से जुड़े उपयोगी उपकरण भी बताए गए हैं, जो व्यक्तियों और संगठनों को जोखिमों की पहचान करने तथा साइबर घटनाओं और डाटा उल्लंघनों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करते हैं। इस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए सभी तीन वीडियो पाठों को देखना अनिवार्य है। इसके बाद क्विज में कम से कम 8/10 अंक प्राप्त करने होंगे और अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) जमा करनी होगी। इसके पश्चात एक सत्यापित डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक लिंक tinyurl.com/yx8tjmsp पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

टेक-टॉक

Gadgets Ai Technology

वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी

अब कंपन से बिजली पैदा की जा सकेगी। भविष्य में यह तकनीक न केवल प्रभावी होगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रहेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अब पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इसी दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सीसा-मुक्त पीजोइलेक्ट्रिक्स, पतली परतों का सफल विकास किया है, जो साधारण सिलिकॉन वेफर पर सीधे तैयार की जा सकती हैं। यह शोध भविष्य में ऐसे ऊर्जा-संग्रहण उपकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो न केवल प्रभावी होंगे, बल्कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी होंगे।

■ पीजोइलेक्ट्रिक्स क्या हैं : पीजोइलेक्ट्रिक्स पदार्थ ऐसे सामग्री होते हैं, जो यांत्रिक दबाव या कंपन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह तकनीक माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन जैसे उपकरणों में उपयोग हो रही है। हालांकि, अब तक के सबसे प्रभावी पीजोइलेक्ट्रिक्स पदार्थों में सीसा का उपयोग होता रहा है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

■ सीसा-मुक्त विकल्प : इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने बिस्मथ फेराइट नामक एक सीसा-मुक्त विकल्प पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, इसकी उपयोगिता अब तक सीमित रही थी, क्योंकि इसमें विद्युत रिसाव अधिक होता था और ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता अपेक्षाकृत कम थी।

■ तकनीक और नवाचार : शोधकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंगनीज-डोप्ड बिस्मथ फेराइट की अत्यंत पतली परत तैयार की, जिसे सीधे सिलिकॉन वेफर पर उगाया गया। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि सिलिकॉन के साथ इस सामग्री का स्वाभाविक मेल नहीं बैठता। आमतौर पर बेहतर पीजोइलेक्ट्रिक्स प्रदर्शन के लिए दबाव(कंप्रेसिव स्ट्रेन) की आवश्यकता होती है, लेकिन सिलिकॉन वेफर ठंडा होने पर खिंचाव (टेंसाइल स्ट्रेन) उत्पन्न करता है।

■ फायदों को समझें : वैज्ञानिकों ने इस बाधा को अवसर में बदलते हुए टेंसाइल स्ट्रेन का उपयोग किया और एक नई संरचनात्मक अवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 'बायएक्सियल कॉम्बिनेटोरियल स्पटरिंग' नामक एक नई तकनीक विकसित की, जिसके माध्यम से एक ही वेफर पर अलग-अलग तापमान और संरचना की स्थितियों का परीक्षण किया जा सकता है। इससे शोध की गति कई गुना बढ़ गई।

■ दक्षता में सुधार : इस नवाचार के परिणामस्वरूप, वैज्ञानिकों ने पाया कि एक विशेष अवस्था में यह सामग्री अपनी क्रिस्टल संरचना बदलकर अधिक प्रभावी बन जाती है। इस बदलाव ने पीजोइलेक्ट्रिक्स क्षमता को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। जब इस तकनीक को कंपन-आधारित ऊर्जा संग्रहण उपकरणों में लागू किया गया, तो इसकी दक्षता पहले की तुलना में पांच गुना अधिक पाई गई।

■ सेमीकंडक्टर उद्योग को लाभ : ये उपकरण निरंतर और अचानक दोनों प्रकार के कंपन में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं, जिससे इनका उपयोग मोटर, मशीनों और अन्य औद्योगिक उपकरणों में संभव हो सकेगा। इस तकनीक की बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह से मौजूदा सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान हो जाएगा।

■ पर्यावरण संरक्षण : भविष्य में इस तकनीक का उपयोग स्मार्ट सेंसर और स्वयं-चालित उपकरणों में किया जा सकेगा। इस सामग्री का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है।

एक फ्रेम से वीडियो बनाएगा 'रीइमेजिन'

यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को और मजेदार बनाने के लिए 'रीइमेजिन' नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर यूजर्स को किसी भी शॉर्ट वीडियो के एक फ्रेम को 8 सेकंड के वीडियो में बदलने की सुविधा देता है। यानी अब एक साधारण सीन भी कुछ ही सेकंड में नया और मजेदार रूप ले सकता है। इस फीचर की असली ताकत एआई है। यूजर किसी भी शॉर्ट वीडियो से एक फ्रेम चुन सकता है और उसे अलग-अलग तरीकों से कस्टमाइज कर सकता है। इसमें वह अपनी फोटो या ऑब्जेक्ट जोड़ सकता है। एआई को निर्देश दे सकता है या फिर दिए गए क्रिएटिव सुझावों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद यह टूल खुद ही एक नया वीडियो क्लिप तैयार कर देता है, जिसमें ऑडियो भी सिंक रहता है।

क्रिएशन को और बेहतर करेगा 'एडिट्स'

मेटा का टूलकिट 'एडिट्स' सोशल मीडिया क्रिएटर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्रिएशन और कस्टमाइजेशन विकल्पों की बढ़ती संख्या को और भी बेहतर बना सकता है। मेटा ने इस टूलकिट में नए अपडेट्स किए हैं, जिसका उद्देश्य एडिटिंग को बेहतर बनाना है। दरअसल यह फीचर एक नया सिनेमैटिक इफेक्ट्स बंडल है, जिसमें जूम, पैन और शटर सहित 5 नए इफेक्ट्स शामिल हैं। एडिट्स ने फोटोग्राफर एथन बार्बर के साथ साझेदारी में डिजाइन किया गया एक नया कलर फिल्टर भी जोड़ा है, जो उपयोगकर्ताओं को सिनेमैटिक शैली को अपनाने में मदद करेगा।

आने वाला है

जल्द आएगा एप्पल का फोल्डेबल आईफोन

एप्पल जल्द ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है। हालांकि ये डिवाइस तुरंत मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि इस फोल्डेबल फोन का नाम वी68 हो सकता है। इसमें लगभग 7.8-8 इंच का फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा, टच आईडी (साइड बटन में) और 12 जीबी रैम के साथ शक्तिशाली ए 19 चिप होने की संभावना है। इसकी कीमत लगभग 1.6 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। खबरों के अनुसार, कंपनी इस फोन में बड़े डिस्प्ले के साथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें यूजर्स एक साथ दो एप्स चलाने जैसे फीचर्स का भी उपयोग कर पाएंगे।

आने वाली है

विलासिता और तकनीक का संगम

मर्सिडीज-बेंज भारत में जल्द ही अपना इलेक्ट्रिक वर्जन सीएलए लॉन्च करने वाली है। यह गाड़ी अगले महीने सड़कों पर दिखाई दे सकती है। मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक आधुनिक डिजाइन को दिखाती है। इसके फ्रंट फेसिया में चमकदार काले रंग की ग्रिल है, जिस पर रोशन तीन-नुकीले तारे के आकार के मोटिफ बने हैं, जो इसे एक दमदार पहचान देते हैं। ट्विन-पॉड एलईडी हेडलाइट्स को एक पतली एलईडी स्ट्रिप के साथ जोड़ा गया है, जो सेडान को हाई-टेक लुक प्रदान करती है। फ्लश डोर हैंडल और 18-इंच के अलॉय व्हील एयरोडायनामिक्स और आकर्षक लुक को बढ़ाते हैं।

आज का दिन

25 मार्च, 1306

रॉबर्ट द ब्रूस को स्कॉटलैंड का राजा घोषित किया गया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता के युद्ध में स्कॉटलैंड का नेतृत्व किया और बैनॉकबर्न की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की।

- **1655 :** डच खगोलशास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की।
- **1807 :** ब्रिटिश संसद ने दास व्यापार को अवैध घोषित कर दिया।
- **1957 :** यूरोपीय देशों द्वारा रोम में की गई संधियों के बाद ईईसी की स्थापना हुई थी।
- **1965 :** अमेरिकी अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर का जन्म हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी। **कल :** श्री दुर्गाष्टमी, श्रीरामनवमी व्रत, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 13.30 से 15.00 तक

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 05 चैत्र मास शक 1948, चैत्र मास 13 प्रविष्टे, 06 सव्वाल हिजरी 1447, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 11.48 तक उपरांत नवमी, आर्द्रा नक्षत्र 16.18 तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र, शोभन योग 24.31 तक उपरांत अतिगंड योग, बव करण 11.48 तक उपरांत बालव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में दिन-रात।

■ सूर्योदय : 06.22
■ सूर्यास्त : 18.32
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। नौकरी में उन्नति हो सकती है। नए कार्य में निवेश से बचें। व्यवसाय में लाभ होगा।

वृष : मानसिक तनाव से बचें। कार्यक्षेत्र में सम्मान बना रहेगा। अर्थ प्राप्ति संभव है। व्यवसाय में उत्तम होगा।

मिथुन : दिनमान अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होगा।

कर्क : मानसिक उत्तेजना से बचें। बनते कार्य में निराशा होगी। व्यय अधिक होगा। नौकरी में सावधानी बरतें।

सिंह : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। अर्थ प्राप्ति संभव है। मित्र सहयोग मिलेगा।

कन्या : नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। अचानक व्यय हो सकता है।

तुला : नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे।

वृश्चिक : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। उधार देने से बचें। व्यवसाय में सावधानी बरतें। यात्रा में कष्ट हो सकता है।

धनु : मित्र सहायक रहेंगे। नौकरी में नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। व्यवसाय में नया अनुबंध हो सकता है।

मकर : वाणी पर नियंत्रण रखें। नए प्रोजेक्ट में विलंब संभव है। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

कुंभ : आरोग्य सुख मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय में उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे।

मीन : कार्यक्षेत्र में दौड़-भाग रहेगी। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

जन्मदिन

नायला उषा, अभिनेत्री

इस वर्ष आत्मबल बना रहेगा। विकास के नए मार्ग मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। नौकरी में अप्रैल से जून के मध्य प्रमोशन का अवसर मिल सकता है। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। साझेदारी में नए कार्य का प्रारंभ हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

		1		2				
		5	8		7			
8	7		1			3		
	5			8	3	2		
	1						5	
		4	6	5			8	
		2			8		9	1
			5		9	4		
				4		8		

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

3	9	1	4	2	6	5	7	8
4	2	5	8	3	7	1	6	9
8	7	6	1	9	5	3	4	2
6	5	7	9	8	3	2	1	4
9	1	8	2	7	4	6	5	3
2	3	4	6	5	1	9	8	7
5	4	2	3	6	8	7	9	1
7	8	3	5	1	9	4	2	6
1	6	9	7	4	2	8	3	5

डेली हेल्थ कैप्सूल

कुटकी को कितना जानते हैं आप

कुटकी का उपयोग लिवर की समस्याओं, पाचन को बेहतर बनाने और बुखार से आराम दिलाने के लिए किया जाता है।

कुटकी को लिवर की समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह लिवर की सफाई करने और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने कुटकी पर शोध कर इसके सक्रिय तत्व पिक्रोजाइड को अलग करके एक हर्बल दवा विकसित की है, जो लिवर पर

होने वाले विषैले प्रभाव कम करने और कोशिकाओं की मरम्मत में उपयोगी पाई गई। कुटकी का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। साथ ही इससे भूख को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज में आराम मिलता है। कुटकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर वजन को नियंत्रित रखती है। यह प्राकृतिक रूप से खून को साफ करने का कार्य करती है, जिससे फोड़े-फुंसी, खुजली, एलर्जी और मुंहासे जैसी त्वचा से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कुटकी बुखार में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स इम्युनिटी को मजबूत कर बीमारियों से बचाते हैं। इसमें मौजूद एंटीइंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

कुटकी के अधिक सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे खुद से डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही इसका सेवन करें।

-डॉ. नवदीप जोशी
प्राकृतिक चिकित्सक

Your Time Is Most Valuable Thing.
I will not let you down 🙏

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

📚Indian Newspapers:

Uploding starts from 5AM

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard

+All Editorial PDFs

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)